भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | शनिवार, 4 जुलाई 2026 | 20 आषाढ़, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 70, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | bhartendunewsmedia@gmail.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

विदेशी मुद्रा भंडार 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 पर

एजेंसी, नई दिल्ली। आर्थिक मोंचे पर झटका लगने वाली खबर है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 जून को समाप्त हफ्ते में 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 अरब डॉलर रह गया। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 96.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 672.58 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में बताया कि स्वर्ण भंडार और विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट के कारण विदेशी मुद्रा भंडार 26 जून को समाप्त हफ्ते में 5.654 अरब डॉलर घटकर 666.933 अरब डॉलर रह गया। आंकड़ों के मुताबिक 26 जून को समाप्त हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां (एफसीए) 15 करोड़ डॉलर घटकर 541.07 अरब डॉलर रह गईं।

यूपी में कंटेनर ने रोडवेज बस यात्रियों को रौंदा, 5 की मौत

एजेसी, एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बागवाला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को तड़के एक सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। 11 लोग घायल हो गए। हादसा कीलरमाऊ गांव के पास उस समय हुआ, जब खराब होकर सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के बाहर खड़े यात्री इसकी चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलते ही बागवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज भिजवाया। वहां डॉक्टरों ने बुलंदशहर निवासी सतेंद्र (38), फर्रुखाबाद निवासी राजेश (34), सुखराम (30), शैलेश (29) व एक अन्य अज्ञात को मृत घोषित कर दिया।

आरएसएस बोला-चढ़ावा चोरी से रामभक्त आहत

एजेंसी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने वीडियो संदेश में कहा कि यह घटना श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने वाली है और मंदिर की व्यवस्था में मौजूद कमियों को गंभीरता से सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रबंधन और जांच एजेंसियों को मिलकर पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। होसबाले ने यह भी कहा कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जरूरी है।

दमिश्क के कैफे में बम विस्फोट, नौ की मौत

एजेंसी, दमिश्क। सीरिया की राजधानी दमिश्क के 'पैलेस ऑफ जस्टिस' के पास हिजाज इलाके में एक कैफे में वीरवार को हुए बम विस्फोट में करीब नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 अन्य घायल हो गए। सीरियाई अधिकारियों के अनुसार विस्फोट पैलेस ऑफ जस्टिस के पास स्थित कैफे में रखे गए आईईडी के कारण हुआ। फ्रांस के अंतरराष्ट्रीय समाचार टेलीविजन नेटवर्क फ्रांस 24 ने सीरिया की सरकारी टीवी के हवाले से बताया कि धमाके के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। विस्फोट के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। एंबुलेंस और सुरक्षा बल तत्काल मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

इंटरनेट के जरिए आतंकी गतिविधियों का नेटवर्क चला रहे थे संदिग्ध : एटीएस

गुजरात-मध्य प्रदेश से जैश के 8 संदिग्ध आतंकी काबू

एजेंसी, नई दिल्ली। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते ने गुजरात और मध्य प्रदेश से प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के आठ संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है।

इनमें सात को गुजरात के पतन एवं नवसारी से पड़ा है, जबकि एक बिलाल दुर्रानी घाघरा को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया है। गुजरात में जैश ऐ मोहम्मद का आतंकी नेटवर्क खड़ा करने के लिए यह स्लीपर सेल की तैयारी कर रहे थे। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से यह पाकिस्तान स्थित अपने आंखों से जुड़े हुए थे और उनसे आतंकी गतिविधियों और स्लीपर सेल के बारे में जानकारी साझा करते थे। आतंकवाद निरोधक दस्ते इसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद बताया कि वह गुजरात में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकी नेटवर्क बनाना चाहते थे, ताकि किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सके।

यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज

गिरफ्तारियों के बाद, एटीएस ने 'गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आपराधिक साजिश से जुड़ी 'भारतीय न्याय संहिता' की धाराओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

बड़े आतंकी नेटवर्क को कर रहे थे तैयार

अधिकारियों ने बताया कि यह संगठन पर नए सदस्य बनाने, चरमपंथी विचारधारा फैलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए सपोर्ट नेटवर्क तैयार करने का काम कर रहा था। ये आरोपी गुजरात के बनासकांठा, पाटन और नवसारी जिलों और मध्य प्रदेश के देवास के रहने वाले हैं। एटीएस ने बताया कि इनमें से तीन लोग सिद्धपुर व चिखली के मदरसों से भी जुड़े थे। जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह संगठन अपने ऑपरेशनल नेटवर्क को मजबूत करके गुजरात में एक संगठित जेईएम मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहा था। शक है कि यह मॉड्यूल गुजरात और भारत के अन्य हिस्सों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था।

फ्रांसीसी कंपनियों को 'विकसित भारत' में भागीदार बनने के लिए वित्त मंत्री का न्योता

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फ्रांस के कारोबारियों और निवेशकों को 'विकसित भारत 2047' की यात्रा में भारत के साथ साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया।

उन्होंने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए काम करने की जरूरत पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेरिस में आयोजित भारत-फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने फ्रांसीसी निवेशकों से जीवन विज्ञान, टीके, सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), नैदानिक अनुसंधान, सटीक चिकित्सा और डिजिटल स्वास्थ्य में दोनों देशों की पूरक शक्तियों का लाभ उठाकर स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और जैव प्रौद्योगिकी में साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाने का आग्रह किया, ताकि लचीली स्वास्थ्य

◆ **सीतारमण ने कहा, भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी लगातार हो रही है मजबूत**

सेवा मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण किया जा सके। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं।

उन्होंने बताया कि भारत में लगभग 1 हजार फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। निर्मला सीतारमण ने भारत के वित्तीय परिवेश का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में उभरा है। वित्त मंत्री ने बताया कि जून 2026 तक इसके साथ 1,200 से अधिक संस्थाएं पंजीकृत थीं, जबकि बैंकिंग परिसंपत्तियां 111 अरब अमेरिकी डॉलर और संचयी बैंकिंग लेनदेन 176 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि बैंकिंग, कोष प्रबंधन, पट्टे (लीजिंग), वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी), पुनर्बीमा और टिकाऊ वित्त जैसे क्षेत्रों में अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस वैश्विक कृत्रिम मेधा (एआई) परिवेश को आकार देने में विश्वसनीय साझेदार हैं और विश्वसनीय एआई, डिजिटल अवसंरचना तथा अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में सहयोग का दायरा बढ़ा सकते हैं।

सीतारमण ने कहा कि आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर, ओएनडीसी और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से संचालित भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था दुनिया में होने वाले वास्तविक समय के डिजिटल भुगतान का लगभग आधा हिस्सा संभालती है।

सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण कंटेंट को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों पर मेटा को किया तलब

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम पर बाल यौन शोषण सामग्री को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को लेकर मेटा को तलब किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अपने मंत्रालय के अधिकारियों को ऐसा करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार, मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस गंभीर मामले में मेटा से जवाब तलब करें और यह स्पष्ट करें कि ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे प्रसारित हुए। मंत्रालय इस पूरे मामले में कंपनी से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगेगा। एक मीडिया जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंस्टाग्राम पर रेप वीडियो और चाइल्ड वीडियो जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर भुगतान किए गए विज्ञापन चलाए जा रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, इन विज्ञापनों के जरिए उपयोगकर्ताओं को ऐसे टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचाया जा रहा था, जहां कथित तौर पर बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) 99 रुपये जैसी कम कीमत पर बेची जा रही थी। फिलहाल मेटा की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

विजन-2047 : कृषि को नई दिशा देगा हरियाणा किसानों की आय बढ़ाने पर जोर : मुख्यमंत्री सैनी

एजेंसी, चंडीगढ़। हरियाणा को विजन-2047 के अनुरूप कृषि क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में कृषि विभाग के आगामी पांच वर्षों के रोडमैप एवं कार्ययोजना की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री घोषणाओं, बजट घोषणाओं और संकल्प पत्र में शामिल कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विजन-2047 के लक्ष्यों को तय समय सीमा में धरातल पर उतारा जाए, ताकि हर किसान तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और कृषि

अधिक लाभकारी बन सके। बैठक में सेम प्रभावित भूमि को सेम मुक्त बनाने के अभियान की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष 1.40 लाख एकड़ भूमि को सेम मुक्त करने का लक्ष्य लेकर कार्य किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में 15 लाख स्वायल हेल्थ कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में 3.75 लाख मिट्टी के नमूने लिए जाने हैं, जिनमें से अब तक 50,620 नमूने एकत्र किए जा चुके हैं। शेष लक्ष्य जुलाई तक पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस अभियान में स्कूलों के विद्यार्थियों, कॉलेज के छात्रों और ग्रामीण युवाओं को स्वयंसेवक के रूप में जोड़ा जाए, ताकि वे मिट्टी परीक्षण की प्रक्रिया को समझ सकें और कृषि के प्रति उनकी रुचि भी बढ़े।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों के कैग ऑडिट पर लगाई रोक

एजेंसी, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार द्वारा तीन प्राइवेट बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के कैग ऑडिट के आदेश पर रोक लगा दी। यह मामला उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले 'रेगुलेटरी एसेट्स' (आरए) के तौर पर वर्षों में जमा हुए भारी-भरकम 38,500 करोड़ रुपए से जुड़ा है। जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस चंद्रशेखर की बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। बेंच ने कहा कि बिजली रेगुलेटर 'दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन' (डीईआरसी) के कैग को नियुक्त करने के फैसले की कानूनी वैधता पर सवाल उठते हैं, जिन पर न्यायिक निर्णय की जरूरत है।

गुणवत्ता, विश्वास व वैश्विक मानकों पर खरा उतरे यूपी का आम : सीएम योगी

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुक्रवार को आम महोत्सव-2026 का शुभारंभ किया।

उन्होंने स्टॉल्स का अवलोकन कर आम की 800 से अधिक प्रजातियों के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी तैयारी इस तरह होनी चाहिए कि यूपी के किसानों का आम गुणवत्ता, विश्वास व वैश्विक मानकों पर खरा उतर सके। हमारा लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित न रहे, बल्कि ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग के साथ ही प्रोडक्ट की ट्रेसेबिलिटी व ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन पर भी ध्यान देना होगा। तभी यह एक्सपोर्ट के लिए स्वीकार्य होगा। एक बाग आय के कई मॉडल

◆ **सीएम ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया आम महोत्सव का शुभारंभ**

के रूप में फल उत्पादन, प्रोसेसिंग, टूरिज्म, ऑर्गेनिक उत्पाद, मधुमक्खी पालन, खाद्य उद्योग और एक्सपोर्ट के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने का माध्यम बन सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश 26 फीसदी हिस्सेदारी करता है। महोत्सव में 7 श्रेणियों के 56 वर्गों में 800 से अधिक वैरायटी हैं। सीएम ने आम महोत्सव में बायर्स-सेलर्स मीट की सराहना की। कहा कि यूपी में हम लोग ओडीओपी से जुड़े आयोजन करते हैं तो बायर्स-सेलर्स मीट अवश्य रखते हैं। इससे किसानों व उद्यमियों को अपने उत्पाद आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। औद्यानिक फसलों से जुड़े किसान, स्वयं सहायता समूह, पैक हाउस, एक्सपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग, नर्सरी मालिक, बैंकर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाला मैकेनिज्म, मशीनरी व उपकरण आपूर्तिकर्ता, रिसर्च व डवलपमेंट से जुड़े वैज्ञानिक भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। उद्यान विभाग ने यूपी में औद्यानिक फसलों के लिए ईकोसिस्टम बनाने का कार्य किया है।

दुश्मन की खैर नहीं! 52 हजार करोड़ रुपए की मेगा डिफेंस डील को मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा खरीद परिषद की बैठक में करीब 52 हजार करोड़ रुपए की रक्षा खरीद योजनाओं को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई।

इन योजनाओं के तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना को अत्याधुनिक हथियार, मिसाइलें, ड्रोन रोधी प्रणाली, हवाई सुरक्षा प्रणाली और निगरानी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे देश की युद्ध तैयारी और सुरक्षा क्षमता पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। थल सेना के लिए ड्रोन रोधी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली आकाश तरंग, कंधे से दागी जाने वाली टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली, बेहद कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली, टैंकों की सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित आत्मघाती ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे सेना की मारक क्षमता और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। बेहद कम दूरी की हवाई सुरक्षा प्रणाली कई तरह की बाधाओं के बीच भी प्रभावी ढंग से काम करेगी। टैंकों के लिए नई सुरक्षा प्रणाली उन्हें दुश्मन के हमलों से बचाने और उनकी जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी। जेट आधारित आत्मघाती ड्रोन प्रणाली कम लागत में अधिक मारक क्षमता और बेहतर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता उपलब्ध कराएगी।

ड्रोन व टैंकों से निपटने की ताकत होगी मजबूत

आकाश तरंग सेना को दुश्मन के ड्रोन हमलों से प्रभावी सुरक्षा देगा। कंधे से दागी जाने वाली टैंक रोधी मिसाइल दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने में मदद करेगी। वहीं मध्यम दूरी की हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली दुश्मन के हवाई खतरों को समय रहते रोकने में सक्षम होगी।

मुख्यमंत्री धामी ने 187 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- सरकारी सेवा अधिकार नहीं, जनसेवा का संकल्प

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) की पीसीएस मुख्य परीक्षा-2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों तथा कृषि व कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित पांच अभ्यर्थियों सहित कुल 187 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवचयनित अधिकारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र नहीं है, बल्कि यह राज्य की सवा करोड़ जनता के विश्वास, अपेक्षाओं और सेवा के दायित्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा

कि किसी भी लोकसेवक की वास्तविक पहचान उसके पद से नहीं, बल्कि जनता के प्रति उसके व्यवहार, कार्यशैली और सेवा भावना से होती है।

उन्होंने नवचयनित अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन का उद्देश्य जनता पर शासन करना नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं का समाधान करना और उसके जीवन को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ करें, ताकि आम नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास और अधिक मजबूत हो। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले लोगों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई नागरिक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबी दूरी तय कर सरकारी कार्यालयों तक पहुंचते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को कार्यालयों में सम्मानजनक व्यवहार, सहज संवाद और त्वरित समाधान मिलना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे जनता की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनें और नियमों के अनुरूप शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

चलते ई-रिक्शा को बंद करने वाले चाइनीज ऐप बीएटी-बीएमएस बंद

एजेंसी, नई दिल्ली। ई-रिक्शा को चलते-चलते रोकने वाले चीनी मोबाइल एप्स पर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने बीएटी- बीएमएस, लॉसिजी और इपोच ली-आयन जैसे एप्स को तुरंत प्ले स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन एप्स के जरिए कुछ ब्लूटूथ आधारित लिथियम बैटरियों वाले ई-रिक्शा को दूर से बंद किए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थी। सरकार का कहना है कि जिन अन्य एप्स का भी इसी तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें भी ब्लॉक किया जाएगा। सरकार ने अभी आदेश दिया है। इस पर काम जारी है। हालांकि, प्लेस्टोर से एप हटने में कुछ समय लग सकता है। सरकार के अनुसार, ये एप मूल रूप से बैटरी की जांच और सर्विसिंग के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ लोग

◆ **केंद्र ने प्लेस्टोर से तुरंत हटाने के दिए आदेश**

इनका दुरुपयोग कर रहे थे। ऐसे मामलों में ई-रिक्शा की बैटरी से बिना अनुमति कनेक्ट होकर वाहन की पावर सप्लाई बंद की जा सकती थी। इसी को देखते हुए केंद्र ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित एप्स को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही भविष्य में ऐसे किसी भी एप को लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बनने से रोकने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है।

आईटी सचिव एस कृष्णन ने कहा कि एप स्टोर संचालकों को ऐसे एप्स की जांच में अधिक सतर्क रहना होगा। सरकार एप स्टोर कंपनियों के साथ मिलकर ऐसा तंत्र तैयार करेगी, जिससे भविष्य में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले एप उपलब्ध न हो सकें।

समीक्षा

हिमाचल के आईजीएमसी व चमियाना अस्पताल में शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित करने के निर्देश

सीटी स्कैन व एक्स-रे जांच में नहीं हो इंतजार : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सीटी स्कैन, एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड जैसी जांच सेवाओं में मरीजों को इंतजार नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा कि विभाग ऐसी व्यवस्था विकसित करे, जिससे इन जरूरी जांचों के लिए शून्य प्रतीक्षा अवधि सुनिश्चित की जा सके और मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश शुक्रवार को इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय (आईजीएमसी), शिमला और चमियाना सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निदान विभागों की समीक्षा बैठक के दौरान

दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन सेवाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधन और आधुनिक जांच उपकरण उपलब्ध करवा रही है। अब विभाग को समन्वित प्रयास कर जांच सेवाओं में प्रतीक्षा समय समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से भी सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि निदान सेवाओं को और मजबूत बनाने तथा मरीजों के लिए शून्य प्रतीक्षा अवधि के लक्ष्य को हासिल करने में डॉक्टरों का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य लोगों को हिमाचल के भीतर ही बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और तकनीकी कर्मचारियों के रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है। उनका कहना था कि इससे गंभीर और उन्नत इलाज के लिए मरीजों को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

आईजीएमसी को जल्द मिलेगी 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन : मुख्यमंत्री

आईजीएमसी के चिकित्सकों की मांग पर मुख्यमंत्री ने संस्थान को जल्द 256-स्लाइस सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं है और सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत कर रही है। उन्होंने बताया कि एम्स, नई दिल्ली के समकक्ष उच्चस्तरीय चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये आधुनिक मशीनें मेडिकल कॉलेजों के साथ जिला अस्पतालों, जोनल अस्पतालों और अन्य नागरिक अस्पतालों में भी स्थापित की जाएंगी, जिससे प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और मजबूत होगा।

'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना सितंबर से विश्व बैंक 65% वित्तीय सहायता कराएगा उपलब्ध

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार विश्व बैंक के सहयोग से 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना सितंबर से शुरू करने जा रही है। यह पर्यावरण विभाग की सात वर्षीय परियोजना है, जिसे विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपए है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि परियोजना की तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिकाएं तय की जाएंगी और कार्यक्रम के प्रभावी

◆ **परियोजना की तैयारियों के लिए 10 जुलाई को होगी विशेष कार्यशाला**

और समयबद्ध क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपए है, जिसमें 65 प्रतिशत वित्तीय सहायता विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा, जबकि 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत परिवहन, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएंडडी) अपशिष्ट, ठोस कचरा प्रबंधन, उद्योग, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है। पहला स्तंभ दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इसके तहत परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए एक समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाई जाएगी। आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने टांडा मेडिकल कॉलेज आरकेएस बैठक की अध्यक्षता की

मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक उपकरण व मशीनों से स्वास्थ्य सेवाएं होंगी मजबूत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने शिमला से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में मंत्री ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों की उपलब्धियों और प्रदर्शन की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रोगी देखभाल सेवाओं को सुदृढ़ करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के कायाकल्प की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। देश के प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों की तर्ज पर

राज्य के चिकित्सा संस्थानों को स्तरोन्नत किया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से राज्य में अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटीज चमियाणा, आईजीएमसी शिमला और टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आधुनिक ऑटोमेटिड लैब स्थापित करने के लिए 75 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में पीजी की सीटों में वृद्धि, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कोर्सिस (एमएलटी) और नर्सिंग की छात्राओं की सुविधा के लिए बेहतर अधोसंरचना को सुनिश्चित किया जाएगा। महाविद्यालय में मरीजों की सुविधा के लिए हाई-परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (एचपीएलसी), कंटीन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरपी (सीआरआरटी) और हीमोडायफिल्ट्रेशन (एचडीएफ) डाईलिसिस मशीनें स्थापित की गई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालय में लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग की सुविधा के विस्तार की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में दशकों पुरानी मशीनों एवं उपकरणों के स्थान पर नई अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों को स्थापित किया जा रहा है। स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक एमआरआई, सीटी स्कैन, डिजिटल रेडियोग्राफी और डिजिटल मैमोग्राफी सहित आधुनिक उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य संस्थानों में बड़े स्तर पर डॉक्टरों, प्रोफेसरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को भर्ती किया जा रहा है जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में ठोस निर्णय लिए जा रहे है। बैठक में विशेष सचिव स्वास्थ्य डॉ. अश्वनी शर्मा और वर्चुअल माध्यम से टांडा से एसपीटीडीसी के अध्यक्ष आर.एस. बाली और टांडा चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. मिलाप तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

किन्नौर के चोलिंग में फटा बादल

एनएच-5 पर मलबे में दबीं दो गाड़ियां, आठ घंटे बंद रहा हाईवे

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मानसून का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।

शुक्रवार तड़के चोलिंग क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने शिमला-किन्नौर राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर भारी मात्रा में मलबा ला दिया, जिससे यातायात घंटों तक बाधित रहा। इस घटना में एक पिकअप और एक स्कॉर्पियो वाहन मलबे में दब गए, हालांकि राहत की बात यह रही कि दोनों वाहनों में सवार लोग सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे और किसी भी जानमाल की हानि नहीं हुई। यह घटना शुक्रवार सुबह लगभग चार बजे हुई। राजमार्ग पर मलबा आने के कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यातायात करीब आठ घंटे तक प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही प्रशासन और मशीनरी हरकत में आई और मलबा हटाने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया गया। सुबह करीब 10:30 बजे यातायात को पुनः सुचारू किया जा सका। एक अन्य घटना में, रिब्बा क्षेत्र के ओठंग नाले में तड़के करीब तीन बजे अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के तेज बहाव के कारण रिब्बा-कंडे संपर्क सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई। कई वाहन मलबे में टायर तक दब गए और आसपास के रास्तों पर मोटी मलबे की परत जम गई। पानी की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। किन्नौर में पिछले दो दिनों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले भावा वैली की शांगो खड्ड में बादल फटने से एक पैदल पुल बह गया था। लिप्पा गांव में पेंजर खड्ड में आई बाढ़ से सिंचाई व्यवस्था और संपर्क मार्ग बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इसके अलावा, रिस्पा गांव के पास होल्डो नाले में जलस्तर बढ़ने से एक अस्थायी रास्ता भी बह गया था।

एनएचएआई को लाखों का नुकसान

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अनुसार, मानसून के दौरान अब तक विभाग को करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। यह घटनाक्रम जिले में मानसून के गंभीर प्रभाव को दर्शाता है और भविष्य में और अधिक क्षति की आशंका को बढ़ाता है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी रखे हुए है।

पर्यटकों के लिए हिमाचल सुरक्षित, कुछ घटनाओं से पूरे प्रदेश को न आंकें: नरेश

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं होना सामान्य बात है। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के आधार पर पूरे प्रदेश को असुरक्षित बताना सही नहीं है। प्रदेश के अधिकांश पर्यटन स्थल पूरी तरह सुरक्षित हैं और पर्यटकों को अनावश्यक रूप से घबराने की जरूरत नहीं है। नरेश चौहान ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया में कुछ क्षेत्रों में आई आपदा की खबरें प्रमुखता से आने के कारण पर्यटकों में पूरे हिमाचल को लेकर भय का माहौल बन जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि केवल कुछ इलाकों में ही बारिश से नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन प्रभावित लोगों के साथ खड़े हैं और अधिकांश सड़कें यातायात के लिए खुली हुई हैं। उन्होंने लोगों से नदी-नालों के किनारे जाने से बचने की अपील भी की।

सरस्वती पैराडाइज पब्लिक स्कूल का प्रशासनिक निरीक्षण, स्टूडेंट्स के हित सर्वोपरि : ज्योति राणा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। जिला प्रशासन शिमला द्वारा सरस्वती पैराडाइज पब्लिक स्कूल, संजौली के सुचारू संचालन एवं विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियुक्त प्रशासक एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा ने विद्यालय का विस्तृत निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं विद्यालय प्रबंधन से विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान ज्योति राणा ने विभिन्न कक्षाओं में जाकर विद्यार्थियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने बच्चों से पढ़ाई, शिक्षण व्यवस्था, अध्यापकों की उपलब्धता तथा विद्यालय में मिल रही सुविधाओं के बारे में विस्तार से फीडबैक लिया। विद्यार्थियों ने भी अपनी जिज्ञासाएं एवं सुझाव उनके समक्ष रखे, जिन्हें उन्होंने गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया। उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा

कि जिला प्रशासन उनकी शिक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है तथा किसी भी छात्र के भविष्य से समझौता नहीं होने दिया जाएगा।

उन्होंने बच्चों को आश्वस्त किया कि अब विद्यालय में नियमित रूप से कक्षाएं संचालित होंगी और शैक्षणिक गतिविधियां व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगी। उन्होंने विद्यार्थियों से पूरी लगन और अनुशासन के साथ अध्ययन करने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रशासन उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। निरीक्षण के दौरान विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं, कक्षाओं की व्यवस्था, स्वच्छता, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया गया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जाएं। साथ ही विद्यालय का वातावरण सुरक्षित, अनुशासित एवं शिक्षण के अनुकूल बनाए रखने पर विशेष बल दिया। ज्योति राणा ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी को बिना किसी व्यवधान के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए प्रशासन लगातार विद्यालय की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है तथा समय-समय पर निरीक्षण भी किए जाएंगे।

सेब सीजन से पहले सड़कों को दुरुस्त करे प्रशासन

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड संख्या-15 गोरली मडावग से भाजपा समर्थित जिला परिषद सदस्य अतुल शर्मा ने सेब सीजन को देखते हुए क्षेत्र की जर्जर सड़क व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों को लेकर अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) शिमला को ज्ञापन सौंपा है।

उन्होंने कहा कि ऊपरी शिमला की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेब उत्पादन पर आधारित है और हजारों किसान-बागवान पूरे साल की आय के लिए इस फसल पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में सेब सीजन शुरू होने से पहले सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जानी चाहिए। अतुल शर्मा ने कहा कि पिछले साल पर्याप्त तैयारियां नहीं होने के कारण एचपीएमसी के गोदामों, बगीचों और सड़कों पर हजारों टन सेब फंस गया था, जिससे किसानों व बागवानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात शुरू हो चुकी है और 15 जुलाई से कई क्षेत्रों में सेब सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से जरूरी तैयारियां दिखाई

अतुल शर्मा ने एडीसी को सौंपा ज्ञापन

नहीं दे रही हैं। उन्होंने बताया कि करगोली नाला-देहा मुख्य मार्ग, देहा-चौपाल सड़क, सरांह-जोड़ना-पुलबाहल-नेरीपुल मार्ग और बमटा-मडावग-खिड़की सड़क सहित कई महत्वपूर्ण संपर्क मार्गों की हालत खराब है। इन सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं, कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और झुके हुए पेड़ों के कारण हादसे का खतरा बना हुआ है। उनका कहना है कि यदि सेब सीजन शुरू होने से पहले इन सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो सेब का परिवहन प्रभावित हो सकता है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि सभी मुख्य व वैकल्पिक मार्गों की तत्काल मरम्मत कर उन्हें पूरी तरह यातायात योग्य बनाया जाए। भारी बारिश के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए लोक निर्माण विभाग की मशीनों की अलग व्यवस्था की जाए और पुलिस विभाग प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन योजना लागू करे, जिससे सेब मंडियों तक पहुंच सके। अतुल शर्मा ने पंचायत स्तर पर लिंक रोड खोलने के लिए विशेष फंड जारी करने, एचपीएमसी की ओर से किसानों का लंबित भुगतान जल्द करने, बिना लाइसेंस सेब खरीद पर रोक लगाने और आढ़तियों की ओर से किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को प्रशासन की तैयारियों की जानकारी भी समय पर दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेब हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सरकार और प्रशासन को इस विषय को प्राथमिकता देते हुए समय रहते आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सोशल मीडिया में सीएम सुक्खू को जान से मारने की धमकी की पोस्ट, युवक गिरफ्तार

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हमीरपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी की पहचान की और उसे हिरासत में ले लिया। शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार शिवनगर निवासी विश्व शामा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि एक युवक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि वीडियो में मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है तथा एक विशेष समुदाय के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, जिससे सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की। डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया विश्लेषण के आधार पर आरोपी की पहचान हमीरपुर जिले के एक गांव के निवासी के रूप में हुई। इसके बाद उसे भोटा पुलिस चौकी में पूछताछ के लिए बुलाया गया और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तार कर लिया गया।

चार दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड मिली है। रिमांड के दौरान यह जांच की जाएगी कि वीडियो किस उद्देश्य से बनाया गया, किन-किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया और क्या इस मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता है। पुलिस ने मामले से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य सुरक्षित कर लिए हैं। अधिकारियों ने कहा कि जांच में यदि किसी अन्य की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त चेतावनी भी जारी की है।

पांच साल पुराने मामले में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। उद्घोषित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शिमला पुलिस ने रामपुर उपमंडल से एक उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस थाना रामपुर और पीओ सेल रामपुर की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को जाहू डीम क्षेत्र से आरोपी भगत राम (46) निवासी तहसील ननखड़ी, जिला शिमला को गिरफ्तार किया। आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, रामपुर की अदालत में पेश किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ वर्ष 2021 में पुलिस थाना ननखड़ी में घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ था। अदालत में सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने पर 17 फरवरी 2026 को उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया था। शिमला पुलिस ने बताया कि न्यायालय की प्रक्रिया से बचने वाले आरोपियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और ऐसे सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा।

शोघी के किसानों ने प्राकृतिक खेती से पेश की मिसाल : प्रो. सिकंदर कुमार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने कहा है कि शिमला जिले के शोघी गांव के किसानों ने सामूहिक रूप से प्राकृतिक खेती अपनाकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया है, जो हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह प्रयास रसायन-मुक्त खेती, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा उदाहरण है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चल रहे कार्यक्रमों के तहत शुक्रवार को प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने शोघी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गांव के प्रगतिशील किसान उमेश शर्मा और उनके साथ प्राकृतिक खेती कर रहे अन्य किसानों के खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने खेतों में उगाई जा रही विभिन्न फसलों और प्राकृतिक खेती की पद्धति की जानकारी ली। सिकंदर

कुमार ने कहा कि शोघी गांव में पांच से छह किसानों ने मिलकर एक समूह के रूप में प्राकृतिक खेती शुरू की है। इस सामूहिक प्रयास से खेती की लागत कम हुई है और उत्पादन में भी सुधार देखने को मिला है।

उन्होंने कहा कि किसान एक ही खेत में अलग-अलग तरह की फसलें उगा रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और सालभर आय के अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया है। उनकी जगह जीवामृत, घनजीवामृत और अन्य प्राकृतिक तरीकों से खेती की जा रही है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हुई है और भूमिगत जल तथा पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि रसायन-मुक्त खेती लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। रसायन-मुक्त खेती हिमाचल के कृषि क्षेत्र का भविष्य बन सकती है। सिकंदर कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में किसानों को प्राथमिकता देते वाली कई योजनाओं पर काम किया है। उनका कहना था कि शोघी के किसानों की यह पहल दिखाती है कि यदि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग हो और किसान मिलकर काम करें तो टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है।

कार से 38.95 ग्राम चिट्टे व 5 सिरिंज के साथ दो युवक धरे

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिरमौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। राजगढ़ थाना की डिटेक्शन सेल ने गिरीपुल क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 38.95 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कार में चिट्टा ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर गिरीपुल पुल के पास नाकाबंदी कर वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें एक बैग से हेरोइन और पांच इस्तेमाल की हुई इंसुलिन सिरिंज बरामद हुईं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरीश चौहान (31) निवासी शिमला और आकाशदीप उर्फ दीपू (25) निवासी सोलन के रूप में हुई है। डीएसपी राजगढ़ विद्या चंद नेगी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।

अनुराग सिंह ठाकुर ने की संसदीय स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता

हरित इस्पात उत्पादन, पर्यावरणीय सततता व आरआईएनएल के कार्यों की हुई समीक्षा

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद व संसदीय कोयला, खान एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद भवन में समिति की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान इस्पात क्षेत्र से जुड़े पर्यावरणीय सततता, हरित पहल, वित्तीय पुनरुत्थान, परिचालन प्रदर्शन तथा श्रमिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित इस्पात तकनीकों के उपयोग और उत्सर्जन नियंत्रण

उपायों की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही ग्रीन स्टील नीति, डीकार्बोनाइजेशन रणनीतियों और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज जैसी आधुनिक तकनीकों के क्रियान्वयन पर भी विचार-विमर्श हुआ।

आरआईएनएल की वित्तीय स्थिति, उत्पादन क्षमता और श्रमिक सुरक्षा सुधारों पर भी समिति ने विस्तृत जानकारी ली। अनुराग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का इस्पात क्षेत्र तेजी से हरित और कम-कार्बन उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ग्रीन स्टील मिशन पहल से औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संसदीय समिति का उद्देश्य इस्पात क्षेत्र को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, पर्यावरणीय दायित्वों का पालन सुनिश्चित करना तथा सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देना है।

शिव कथा में धूमधाम से मनाया गया माता पार्वती का जन्मोत्सव

आत्मदर्शन से जागृत होगी नारी की वास्तविक शक्ति: डॉ. सर्वेश्वर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान द्वारा खलीनी, शिमला में आयोजित सात-दिवसीय भगवान शिव कथा के चतुर्थ दिवस माता पार्वती के जन्मोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कथा का वाचन करते हुए डॉ. सर्वेश्वर ने बताया कि महाराज हिमवान व महारानी मैना ने आदिशक्ति जगदंबिका की 27 वर्षों तक आराधना कर उन्हें पुत्री रूप में पाने का वरदान मांगा। उसी वर के फलस्वरूप मां भवानी, पार्वती के रूप में महाराज हिमवान के घर कन्या बन जन्म लेकर आईं।

स्वामी ने बताया कि यह भारतीय संस्कृति का कितना अद्भुत पक्ष है, जहां पुत्री के जन्म के लिए 27-27 वर्षों की लंबी व घोर तपस्याएं की जाती थीं, लेकिन एक आज का भारत है जहां नारी की दशा इतनी शोचनीय व दयनीय है कि बेटी के जन्म लेते ही माता-पिता के माथे पर चिंता की रेखाएं खिंच जाती हैं। आज हर दिन

नारी शोषण, बलात्कार, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न की घटनाओं से समाचार पत्र अटे रहते हैं। चाहे वो दिल्ली का 'निर्भया कांड' हो या 'कोलकता रेप कांड', ये सब दर्शाते हैं कि आज का समाज कितना गिर गया है, जो नारी को केवल मात्र भोग की वस्तु मानता है और इससे भी अधिक शोचनीय तो यह है कि आज की नारी भी स्वयं की गरिमापूर्ण शक्ति को भूल चुकी है। आज उसे यह समझना ही होगा कि वह अबला नहीं, सबला है।

इसके लिए जरूरत है नारी को आत्मदर्शन प्राप्त कर अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जाग्रत करने की। बाहरी सौन्दर्य-प्रदर्शन तो छिछला है, नारी का वास्तविक सौन्दर्य तो उसकी आत्मा में समाया है। ब्रह्मज्ञान द्वारा जब उसके भीतर आत्मा का दिव्य ओज पैदा होगा तो उसकी तेजस्विता के सामने सम्पूर्ण विश्व नत हो जाएगा। हर वासनापूर्ण दृष्टि दग्ध हो स्वाहा हो जाएगी व जगत उसकी पवित्रता को नमन करेगा। स्वामी जी ने बताया कि दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान आज 'संतुलन' प्रकल्प के अंतर्गत समाज में नारी को आत्मदर्शन की ब्रह्मविद्या प्रदान कर पुनः महिमामंडित पद पर आसीन करने के लिए कटिबद्ध है। कथा में भाजपा के प्रदेश मीडिया संयोजक कर्ण नंदा, सूद सभा शिमला के अध्यक्ष राजीव सूद, विकास कपूर, विशाल शर्मा एवं लितेश कुमार ने आरती पूजन में हिस्सा लिया।

आयोजन | विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कोलकाता में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में की भागीदारी

सीएम व केंद्रीय नेताओं से की भेंट, ई-विधान प्रणाली की दी जानकारी

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया वायुमार्ग द्वारा चंडीगढ़ से दिल्ली होते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने समिति प्रणाली की समीक्षा हेतु आयोजित पीठासीन अधिकारी सम्मेलन तथा 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित ओरिएंटेशन कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। यह संस्थान लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सांसदों, विधायकों, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों को संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक

व्यवस्थाओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस सम्मेलन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समिति प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सात राज्यों की विधान मंडलों की एक समिति गठित की गई है। इस समिति के चेयरपर्सन मध्य प्रदेश विधानसभा के पीठासीन अधिकारी नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मिग्मा नोरबू शेरपा, ओडिशा विधानसभा अध्यक्ष सूर्य नारायण पात्रा तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु इसके सदस्य हैं। कोलकाता स्थित न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विधान मंडलों की समिति प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना तथा नव निर्वाचित विधायकों को संसदीय प्रक्रियाओं का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस दौरान विभिन्न सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समिति प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर समीक्षा बैठकें भी शामिल हैं। तीसरे सत्र की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया करेंगे। इस सत्र में लोकसभा सदस्य एन. के. प्रेमचंद्रन भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे, जबकि राज्यसभा सचिवालय के पूर्व संयुक्त सचिव प्रदीप चतुर्वेदी विशेषज्ञ एवं मध्यस्थ के रूप में शामिल होंगे।

इस सत्र में विधायी कार्यों तथा गैर-सरकारी सदस्य विधेयकों पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जिसमें नव निर्वाचित विधायकों को महत्वपूर्ण अनुभव एवं मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया, जबकि केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु ने भी उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर समिति प्रणाली के महत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पूर्व कोलकाता पहुंचने पर हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का पश्चिम बंगाल सरकार एवं विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। यह सम्मेलन 3 एवं 4 जुलाई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हिमाचल विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा भी अध्यक्ष के साथ उपस्थित हैं। कार्यक्रम के दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में लागू ई-विधान प्रणाली एवं इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी शिष्टाचार भेंट की और संसदीय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने आज राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश तथा पांच जिलों में कहीं-कहीं भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में गरज-चमक, आकाशीय बिजली गिरने और कुछ स्थानों पर तेज से अति तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं राज्य के सभी पर्वतीय जिलों में गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज बारिश के दौर की संभावना बनी हुई है। हरिद्वार और ऊधमसिंहनगर जैसे मैदानी जिलों में भी गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका व्यक्त की गई है।

विभाग ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें तथा नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास जाने से परहेज करें। पर्वतीय मार्गों पर यात्रा करने वाले लोगों को मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास रहा, जबकि पर्वतीय इलाकों में तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया।

79 लाख से अधिक मतदाताओं का डेटा डिजिटाइजेशन अंतिम चरण में

निर्वाचन विभाग ने साझा की एसआईआर अभियान की प्रगति, ड्राफ्ट रोल 14 जुलाई को होगा जारी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से इन मतदाताओं के घर-घर सत्यापन अभियान में सक्रिय सहयोग करने का आग्रह किया है, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम सही रूप से मतदाता सूची में शामिल रह सकें।

शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए राजनीतिक दलों के

◆ **15 सितंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची**

प्रतिनिधियों को अभियान की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित की जा रही है। आठ जून से सात जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।

बैठक में बताया गया कि राज्य में कुल 79 लाख 60 हजार 762 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें से 70 लाख 98 हजार 501 मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा किया जा चुका है। वहीं अब तक कुल 79 लाख 45 हजार 658 मतदाताओं से संबंधित उपलब्ध आंकड़ों का डिजिटाइजेशन भी किया जा चुका है, जिससे मतदाता सूची के अद्यतन का कार्य अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है।

निर्वाचन विभाग के अनुसार 'अनकलेक्टेड' श्रेणी में शामिल 8 लाख 39 हजार 486 मतदाताओं में 1 लाख 23 हजार 836 मृत घोषित मतदाता हैं, जबकि 4 लाख 77 हजार 148 मतदाता स्थायी रूप से अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 61 हजार 764 मतदाता पहले से अन्य स्थानों पर पंजीकृत पाए गए हैं। वहीं 1 लाख 68 हजार 259 मतदाता सत्यापन के दौरान अनुपस्थित मिले तथा 8 हजार 479 मतदाता अन्य कारणों से इस श्रेणी में रखे गए हैं। निर्वाचन विभाग इन सभी मामलों का सत्यापन कर अंतिम मतदाता सूची तैयार करेगा।

श्रीमहंत रविंद्र पुरी बने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पद पर पुनर्निर्वाचित श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्रीमहंत रविन्द्र पुरी महाराज का महानिर्वाणी अखाड़े में आयोजित स्वागत समारोह में संतों और श्रद्धालुओं ने भव्य अभिनंदन किया। श्री जंगम शिवालय एवं श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर के श्रीमहंत कृष्णा गिरि महाराज तथा रवि गिरि महाराज ने पुष्पमाला पहनाकर एवं पटका ओढ़ाकर उनका स्वागत किया।

समारोह में उपस्थित संतों ने कहा कि रविन्द्र पुरी का पुनः अध्यक्ष चुना जाना उनके प्रति संत समाज के अटूट विश्वास का प्रमाण है। उनके नेतृत्व में अखाड़ा परिषद ने बीते वर्षों में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर प्रभावी भूमिका निभाई है और संत समाज को एक मंच पर संगठित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

श्रीमहंत कृष्णा गिरि ने कहा

◆ **संत समाज ने जताया अटूट विश्वास**

कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद केवल अखाड़ों की संस्था नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। ऐसे में रविन्द्र पुरी महाराज का पुनः अध्यक्ष बनना पूरे देश के संत समाज के लिए गौरव और आत्मविश्वास का विषय है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसे रविन्द्र पुरी महाराज पूरी निष्ठा और दूरदर्शिता के साथ निभा रहे हैं।

लोक भवन में राज्यपाल से सिख प्रतिनिधिमंडल की शिष्टाचार भेंट

'राष्ट्र प्रथम' सिख पंथ की पहचान : राज्यपाल

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) से शुक्रवार को लोक भवन में सिख समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हाल में उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से संवेदनशील एवं प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार, मुख्यमंत्री तथा शासन-प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रशासन की ओर से परिस्थितियों का संतुलित, संयमित और संवेदनशील ढंग से किया गया प्रबंधन सामाजिक सौहार्द, एकता और अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों में विश्वास का वातावरण बना रहा।

राज्यपाल गुरमीत सिंह ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए

सिख समाज ने की राज्य सरकार की सराहना

राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड ने हमेशा 'अतिथि देवो भवः' की परंपरा का पालन करते हुए देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का खुले मन से स्वागत किया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार सभी धार्मिक यात्राओं को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन द्वारा आवश्यक सभी इंतजाम किए गए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

कहा कि सिख पंथ ने सदैव 'राष्ट्र प्रथम' और 'सरबत दा भला' की भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सेवा, समर्पण और मानवता का संदेश सिख परंपरा की सबसे बड़ी पहचान है, जो समाज को सद्भाव और एकता का मार्ग दिखाती है।

डॉक्टरों के बड़े पैमाने पर तबादलों पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को गंभीरता से लेते हुए सरकार से विस्तृत जवाब तलब किया है। अदालत ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है कि इन तबादलों के कारण राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, विशेषकर पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में, जहां पहले से ही डॉक्टरों और विशेषज्ञों की भारी कमी बनी हुई है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को निर्धारित की गई है, जिसमें सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

यह मामला राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दायर एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 16 डॉक्टरों के तबादले पर उठे सवाल

तबादलों ने अस्पतालों की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है और मरीजों को उचित इलाज मिलने में कठिनाई हो सकती है। प्राधिकरण ने अदालत को यह भी अवगत कराया कि कई अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण चिकित्सा सेवाएं चरमराने की स्थिति में पहुंच सकती हैं।

सुनवाई के दौरान वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार से पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर तबादलों का आधार क्या था और क्या इन निर्णयों के दौरान मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता को ध्यान में रखा गया था या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी राज्य की बुनियादी जरूरतों में से एक हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या असंतुलन सीधे जनता के जीवन को प्रभावित कर सकता है।

स्वास्थ्य सेवाओं के चरमराने का खतरा

जानकारी के अनुसार, नैनीताल स्थित बीडी पांडे जिला चिकित्सालय से छह विशेषज्ञ चिकित्सकों का तबादला किया गया है। इनके स्थान पर केवल पांच सामान्य चिकित्सक और एक विशेषज्ञ चिकित्सक को भेजा गया है, जो संतुलन को प्रभावित करता है। इसी तरह हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से 16 विशेषज्ञ चिकित्सकों का स्थानांतरण कर दिया गया है, जिससे वहां के प्रसूति रोग विभाग में केवल दो विशेषज्ञ डॉक्टर ही बचे हैं, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों के अनुसार इस विभाग में कम से कम 15 विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। यह स्थिति चिकित्सा शिक्षा और मरीजों की देखभाल दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है।

इसके अलावा मेडिकल कॉलेज में कुल 112 फैकल्टी पद पहले से ही रिक्त हैं, जिससे मौजूदा संकट और भी गंभीर हो गया है। अन्य अस्पतालों से भी विशेषज्ञ चिकित्सकों के तबादले किए गए हैं, लेकिन उनके स्थान पर पर्याप्त संख्या में प्रतिस्थानी डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई है। कई जगहों पर केवल सामान्य चिकित्सकों को भेजा गया है, जिससे विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता पर असर पड़ रहा है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि पर्वतीय जिलों से विशेषज्ञ डॉक्टरों के तबादले होने के कारण वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। इन क्षेत्रों में पहले से ही भौगोलिक कठिनाइयों और संसाधनों की कमी के कारण चिकित्सा सुविधाएं सीमित हैं, ऐसे में डॉक्टरों की कमी से आम जनता को इलाज के लिए दूर-दराज के शहरों पर निर्भर होना पड़ सकता है। इससे आपातकालीन स्थितियों में मरीजों की जान पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

कुल मिलाकर, यह मामला राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक निर्णयों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। अब अदालत के निर्देशों के बाद सरकार को इस पूरे मुद्दे पर विस्तृत और स्पष्ट जवाब देना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य सेवाओं पर किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े और जनता को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं समय पर उपलब्ध होती रहें।

न्यूज ब्रीफ

लक्सर के गांव में घर में घुसा मगरमच्छ , वन विभाग ने किया रेस्क्यू

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। जनपद के लक्सर क्षेत्र स्थित ग्राम डौसनी में शुक्रवार तड़के उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक मगरमच्छ अचानक एक ग्रामीण के घर में घुस आया। घर में मगरमच्छ दिखाई देने से परिवार के लोग दहशत में आ गए और आसपास के ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलते ही लक्सर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ का सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 4.30 बजे ग्राम डौसनी निवासी मदनपाल पुत्र जसवंत सिंह के घर में मगरमच्छ घुस आया। परिजनों ने जैसे ही घर के भीतर मगरमच्छ को देखा, उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी।

पौड़ी में सफल कार्यकाल के बाद रुद्रप्रयाग के लिए रवाना हुईं मनविंदर कौर

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी। पौड़ी से स्थानांतरित होकर रुद्रप्रयाग जनपद में नयी जिम्मेदारी संभालने जा रहीं जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर को शुक्रवार को विकास भवन सभागार में भावभीनी विदाई दी गयी। समारोह में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उनके सफल कार्यकाल, कुशल नेतृत्व और विकास कार्यों के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला विकास अधिकारी को नयी तैनाती के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सिद्ध पीठ जटेश्वर महादेव मंदिर में हुआ प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। पाबौ ब्लाक स्थित सिद्धपीठ जटेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव हवन-पूजन, पूर्णाहुति एवं विशाल भंडारे के साथ श्रद्धापूर्वक मनाया गया। वैदिक मंत्रोच्चार एवं धार्मिक विधि-विधान के बीच आयोजित हवन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। जटेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित महोत्सव में जन कल्याण सामाजिक समिति के पदाधिकारियों, क्षेत्रीय ग्रामीणों व श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की।

पौड़ी जेल में सुधारात्मक पहल, न्यायाधीश धर्म सिंह ने किया उद्घाटन

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी। जिला कारागार में बंदियों के पुनर्वास, सुधार एवं सम्मानजनक जीवन की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से आधुनिक हेयर सैलून का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश धर्म सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला न्यायाधीश द्वारा हेयर सैलून का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि कारागार केवल दंड का स्थान नहीं, बल्कि सुधार, पुनर्वास एवं समाज की मुख्यधारा से पुनः जुड़ने का माध्यम है।

आग का गोला बनी कार, उठीं लपटें,नानकमत्ता में बाइक सवार दो युवकों की मौत

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। नानकमत्ता थाना क्षेत्र के बिडोरा-मझोला मार्ग पर शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार और मोटरसाइकिल की आमने-सामने हुई टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दुर्घटना के तुरंत बाद कार में आग लग गई। आग

की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई, जबकि कार सवार वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस, दमकल और एंबुलेंस को सूचना दी। गंभीर रूप से घायल दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सितारगंज पहुंचाया गया, जहां इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. रविंद्र सिंह ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर खतरा बनीं चट्टानें, एलिवेटेड रोड पर काम जारी

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेसवे पर बनी एलिवेटेड रोड पर सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। इस मार्ग पर छह चट्टानें ऐसी चिन्हित की गई थीं, जो कभी भी गिरकर सड़क और यात्रियों के लिए खतरा बन सकती थीं। इनमें से तीन चट्टानों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा हटा दिया गया है, जबकि बाकी तीन पर अभी भी काम जारी है।

एनएचएआई के अनुसार, यह पूरा अभियान सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है, क्योंकि एलिवेटेड रोड पहाड़ी क्षेत्र में कटिंग करके बनाई गई है। ऐसे में ऊपर मौजूद अस्थिर चट्टानों से पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, जो किसी भी समय गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसी जोखिम को देखते हुए यह विशेष अभियान शुरू किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि अब तक हटाई गई तीन चट्टानों को सुरक्षित तरीके से नीचे लाया गया है। शेष तीन चट्टानों को हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इस दौरान पूरी एलिवेटेड रोड पर एहतियातन यातायात को डायवर्ट किया गया है। हालांकि, दोपहिया वाहन चालकों के लिए आवाजाही को सुचारु रखा गया है, ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो।

एनएचएआई के अधिकारियों के अनुसार, चट्टान हटाने का कार्य अगले एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस मार्ग को पूरी तरह से सामान्य यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से विशेषज्ञ टीम लगातार क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और हर चट्टान की स्थिति का मूल्यांकन कर रही है।

हरीश कुमार गोयल बने देहरादून के नए जिला जज

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक बदलाव करते हुए कई न्यायिक अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इस क्रम में पौड़ी गढ़वाल के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हरिश कुमार गोयल को देहरादून का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह पद लंबे समय से खाली था और उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके अलावा अन्य न्यायिक अधिकारियों को भी विभिन्न जिलों और विशेष न्यायालयों में अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नैनीताल के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार को एनडीपीएस विशेष न्यायालय, नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं देहरादून की एफटीसी/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुसुम को विशेष पॉक्सो न्यायालय, देहरादून का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।

रेल यात्रियों को झटका, अवध असम एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों का बदला रूट

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में रेल यात्रियों को जुलाई महीने में सफर से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जांच करनी होगी, क्योंकि मुरादाबाद-बरेली रेलखंड पर ट्रैक अनुरक्षण और टैंपिंग कार्य के चलते रेलवे ने अलग-अलग दिनों में ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है। इस ब्लॉक के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों को नियंत्रित गति से चलाया जाएगा। इससे यात्रियों की यात्रा अवधि बढ़ सकती है और उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, मुरादाबाद-बरेली रेलखंड पर संरक्षा और रखरखाव कार्य के लिए 4 जुलाई से 31 जुलाई तक कुल 25 ट्रैफिक ब्लॉक स्वीकृत किए गए हैं। यह कार्य रेलपथ के बेहतर रखरखाव और भविष्य में सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

अमृतसर-हावड़ा रूट समेत कई एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन बदला

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि इन ब्लॉकों के कारण मंडल से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ेगा और कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जाएगा।

जानकारी के अनुसार, गाड़ी संख्या 15910 लालगढ़-डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस को 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 23 और 29 जुलाई को मुरादाबाद-चंदौसी-कैंट मार्ग से संचालित किया जाएगा। इस बदलाव के चलते यह ट्रेन रामपुर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। इसके अलावा बरेली जंक्शन के बजाय बरेली कैंट स्टेशन पर इसका ठहराव निर्धारित किया गया है।

इसी तरह गाड़ी संख्या 13152 जम्मूतवी-कोलकाता एक्सप्रेस को 3 और 29 जुलाई को मुरादाबाद-चंदौसी-बरेली कैंट मार्ग से चलाया जाएगा।

भर्ती आंगनबाड़ी सेवाओं को मजबूत करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, रिक्त पदों पर जल्द भर्ती

उत्तराखंड में 3,211 आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती जल्द

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार

उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यस्तता के चलते विभागीय योजनाओं के प्रभावित होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन कम से कम एक घंटा अपने-अपने केंद्रों पर उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए।

शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभागार में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री आर्या ने कहा कि विभाग की अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार से वित्तपोषित हैं और उनकी नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाती है। यदि समय

आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली, पानी और शौचालय की सुविधाएं सुनिश्चित करने के आदेश

पर पोर्टलों पर डाटा अपलोड नहीं किया गया या फीडिंग में लापरवाही बरती गई तो इसका सीधा असर भविष्य में मिलने वाले केंद्रीय बजट और योजनाओं की प्रगति पर पड़ेगा।

उन्होंने विभागीय सचिव को निर्देशित किया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को तत्काल आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं, ताकि एसआईआर ड्यूटी के साथ-साथ विभागीय कार्य भी नियमित रूप से संचालित होते रहें।

बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य में लंबे समय से रिक्त पड़े आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

उन्होंने कहा कि 438 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा 2,773 सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई जारी है और विभाग का लक्ष्य अगस्त माह के अंत तक सभी पदों पर नियुक्तियां पूरी करना है। इससे प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यप्रणाली और सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

मंत्री ने समीक्षा बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड एवं अपार आईडी बनाए जाने की धीमी प्रगति पर भी असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को निर्देश दिए कि जुलाई माह के अंत तक सभी पंजीकृत बच्चों के आधार कार्ड और अपार आईडी बनवाने का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का नियमित वजन कराया जाए तथा पोषण ट्रैकर ऐप पर सभी सूचनाएं निर्धारित समय के भीतर अपलोड की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए पोषण सामग्री की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे पोषण योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से पहुंच सके।

हरिद्वार में सप्ताहभर चलेगा सेवा पखवाड़ा, जनता को मिलेगा लाभ

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार जनपद में 4 जुलाई से 'सेवा, सुशासन एवं समर्पण' थीम पर सेवा पखवाड़ा शुरू होगा। सप्ताहभर चलने वाले इस अभियान के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के पिछले पांच वर्षों की विकास योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष जनसेवा शिविर लगाए जाएंगे।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को बताया कि सेवा पखवाड़े का शुभारंभ 4 जुलाई को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय में होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण भी किया जाएगा। अभियान के तहत प्रत्येक दिन अलग-अलग विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें रोजगार एवं कौशल विकास, नई सरकारी योजनाएं, सड़क, रेल व रोपवे जैसी आधारभूत संरचना परियोजनाएं, उद्योग एवं एमएसएमई, कृषि, उद्यान और पशुपालन, महिला, युवा एवं

सैनिक कल्याण तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों पर आधारित गतिविधियां शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़े के दौरान चिकित्सा एवं दिव्यांग शिविर, महिलाओं और बालिकाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर, विभागीय प्रदर्शनी, योजनाओं के स्टॉल, ऑन-द-स्पॉट आवेदन एवं पंजीकरण, लाभार्थी संवाद, कौशल विकास एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन, डिजिटल सरकारी सेवाओं की जानकारी, मैराथन, खेलकूद प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा राजस्व विभाग की ओर से विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा।

प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने पर चन्नी ने शक्ति प्रदर्शन किया शुरू

प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने से नाराज चरणजीत सिंह ने समर्थक विधायकों और वरिष्ठ नेताओं संग रणनीतिक बुलाई बैठक

भारतेन्दु संवाददाता,चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही सियासी हलचल अब खुलकर सामने आने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए मोरिंडा स्थित अपने आवास पर समर्थक नेताओं की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक को पंजाब कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में कई मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए हैं। राजनीतिक हलकों में इसे पार्टी नेतृत्व के लिए स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि चन्नी के पास अब भी संगठन में मजबूत समर्थन मौजूद है।

सूत्रों के अनुसार, चन्नी ने इस बैठक में तीन सांसदों, 12 विधायकों और करीब 40 पूर्व विधायकों के अलावा वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव लड़ चुके कई नेताओं को आमंत्रित किया है। बैठक में पंजाब कांग्रेस की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, संगठन की दिशा और आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।

बैठक में सबसे पहले विधायक तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा पहुंचे। उनके अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री ओपी सोनी, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू, गुरकीरत सिंह कोटली, पूर्व विधायक गुरप्रीत कांगड़, नाजर सिंह मानशाहिया, दविंदर सिंह घुबाया, इंद्रबीर सिंह बुलारिया, लखबीर सिंह लक्खा, तरसेम डीसी, दर्शन बराड़, हरमिंदर सिंह गिल, मदन लाल जलालपुर, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बरिंदर सिंह ढिल्लों, कमलजीत कड़वल और पूर्व सांसद मोहम्मद सदीक सहित कई वरिष्ठ नेता चन्नी के आवास पर पहुंचे। नेताओं की बड़ी मौजूदगी ने बैठक के राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया है।

बैठक के दौरान पूर्व विधायक दर्शन बराड़ ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि चरणजीत सिंह चन्नी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनाया गया तो पंजाब में कांग्रेस के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। उनके इस बयान ने पार्टी के भीतर चल रहे असंतोष को सार्वजनिक रूप से सामने ला दिया है। माना जा रहा है कि यह बयान केवल व्यक्तिगत समर्थन नहीं बल्कि कांग्रेस के एक बड़े वर्ग की भावना को भी दर्शाता है।

दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चयन से पहले राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि हाईकमान चरणजीत सिंह चन्नी को संगठन की कमान सौंप सकता है। लेकिन अंतिम समय में पार्टी नेतृत्व ने लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बनाए रखने का फैसला किया। वहीं, चन्नी को चुनाव अभियान समिति (कैंपेन कमेटी) का चेयरमैन नियुक्त किया गया।

हालांकि, इस फैसले के बाद से ही चन्नी की नाराजगी की चर्चाएं तेज हो गई थीं। उन्होंने नियुक्ति के बाद सार्वजनिक रूप से पार्टी हाईकमान का धन्यवाद भी नहीं दिया। उनके करीबी नेताओं का दावा है कि चन्नी इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें लगता है कि संगठन में उनकी लोकप्रियता और राजनीतिक योगदान के अनुरूप जिम्मेदारी नहीं दी गई।

मोहाली सिविल अस्पताल में जांच शुल्क बढ़े, लैब के अलग रेट बने परेशानी

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

फेज-6 स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (सिविल अस्पताल) में नए यूजर चार्ज लागू होने के बाद सरकारी लैब में होने वाली कई मेडिकल जांचों के शुल्क बढ़ गए हैं। वहीं, अस्पताल परिसर में ही पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर संचालित लैब में इन्हीं जांचों के शुल्क अपेक्षाकृत कम हैं। एक ही अस्पताल में एक जैसी जांचों के अलग-अलग रेट होने से मरीजों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि किस लैब में जांच कराना अधिक उचित रहेगा।

मरीजों का कहना है कि पहले सरकारी अस्पताल में कम खर्च में इलाज और जांच की सुविधा मिल जाती थी, लेकिन अब बढ़े हुए यूजर चार्ज के कारण इलाज का कुल खर्च बढ़ गया है। इसका सबसे अधिक असर आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के मरीजों पर पड़ रहा है। सरकारी लैब में जांच के लिए लंबी कतारों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिससे मरीजों की परेशानी और बढ़ गई है।

अस्पताल आने वाले कई मरीजों ने बताया कि डॉक्टर किसी एक लैब से जांच कराने की सलाह देते हैं, जबकि दूसरी लैब में वही जांच काफी कम शुल्क पर उपलब्ध होती है। ऐसे में मरीज पहले दोनों लैब की दरों की जानकारी लेने में समय लगाते हैं और फिर जांच कराने का निर्णय करते हैं। इससे अनावश्यक भागदौड़ के साथ समय और मेहनत दोनों बढ़ रहे हैं।

सरकारी और पीपीपी लैब की जांच दरों में उल्लेखनीय अंतर देखने को मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर रैंडम ब्लड ग्लूकोज जांच सरकारी लैब में 30 रुपये में की जा रही है, जबकि पीपीपी लैब में यही जांच 14 रुपये में उपलब्ध है। ब्लड ग्रुप और आरएच टाइपिंग सरकारी लैब में 82 रुपये, जबकि पीपीपी लैब में 60 रुपये में हो रही है।

न्यूज ब्रीफ

पालतू कुत्ते की कृष्ण वेशभूषा पर एफआईआर रद्द

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जन्माष्टमी के अवसर पर एक महिला द्वारा अपने पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण की वेशभूषा पहनाकर उसकी तस्वीरें व्हाट्सएप स्टेटस पर साझा करने के मामले में दर्ज एफआईआर रद्द कर दी है। जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा कि महिला का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करना था। इसलिए इस कृत्य को अपराध नहीं माना जा सकता। यह एफआईआर तीन सितंबर 2024 को होशियारपुर के तलवाड़ा थाने में दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महिला ने अपने पालतू कुत्ते को भगवान कृष्ण जैसा स्वरूप देकर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। अदालत ने अपने फैसले में भगवद्गीता के अध्याय-5 के श्लोक-18 का उल्लेख करते हुए कहा कि ज्ञानी व्यक्ति सभी प्राणियों में समान रूप से परमात्मा का दर्शन करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपने पालतू पशु को स्नेह और श्रद्धा के साथ भगवान कृष्ण का स्वरूप देना धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति है, न कि किसी धर्म का अपमान।

नई टीम से बाहर हुए मनीष तिवारी, बढ़ी हलचल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़ । पंजाब कांग्रेस की नई संगठनात्मक टीम और चुनावी समितियों से सांसद मनीष तिवारी को बाहर किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तिवारी ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए बिना किसी का नाम लिए लिखा कि जब किसी की योग्यता दूसरों की असुरक्षा बन जाती है, तब फैसले संगठनात्मक नहीं बल्कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रेरित होते हैं। उनकी इस टिप्पणी के बाद पार्टी छोड़ने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। हालांकि, चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरमोहिंदर सिंह लक्की ने इन अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि मनीष तिवारी कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं तथा पार्टी उनके योगदान का सम्मान करती है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस नेतृत्व भविष्य में उनकी सेवाओं का उचित उपयोग करेगा। तिवारी ने अपनी पोस्ट में बताया कि उन्होंने वर्ष 1981 में एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में राजनीति शुरू की थी और चार दशक से अधिक समय तक पूरी निष्ठा से कांग्रेस की सेवा की है। उन्होंने अंत में लिखा, **'जो होगा, सो होगा। '**

भबात गांव में जल्द बनेगा पुलिस बीट बॉक्स

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। भबात गांव और आसपास के क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जल्द ही पुलिस बीट बॉक्स स्थापित किया जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक गजलप्रीत कौर ने बढ़ती आबादी और क्षेत्र में सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को देखते हुए इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला स्थानीय ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भबात गांव के स्टेडियम में प्रतिदिन शाम के समय बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसी क्षेत्र में दोपहिया वाहनों की चोरी, मारपीट और अन्य असामाजिक गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। ऐसे में पुलिस की स्थायी मौजूदगी आवश्यक महसूस की गई। प्रस्ताव के अनुसार पीएनबी बैंक के निकट सरकारी भूमि पर पुलिस बीट बॉक्स बनाया जाएगा। यहां एक पुलिस अधिकारी और एक कांस्टेबल की नियमित तैनाती रहेगी। पुलिस का मानना है कि बीट बॉक्स शुरू होने से क्षेत्र में गश्त बढ़ेगी, अपराधों पर अंकुश लगेगा और ट्रैफिक व्यवस्था की निगरानी भी पहले से अधिक प्रभावी हो सकेगी।

अमरूद घोटाला मामले में आरोपी जैसमीन कौर को अदालत से अमेरिका जाने की मिली अनुमति

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। वर्ष 2023 में दर्ज चर्चित अमरूद घोटाला मामले में आरोपी जैसमीन कौर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उन्हें 4 जुलाई से 20 जुलाई 2026 तक अमेरिका जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। जैसमीन कौर ने अदालत में पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी।

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनका आवेदन स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके साथ सात कड़ी शर्तें भी लागू की हैं, जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य होगा। जैसमीन कौर अमरूद घोटाला मामले में ट्रायल का सामना कर रही हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित साजिश के तहत अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले अमरूद के बाग का मुआवजा अनुचित तरीके से प्राप्त किया।

सात शर्तों पर मिली अनुमति

अदालत ने जैसमीन कौर को अमेरिका जाने की अनुमति सात सख्त शर्तों के साथ दी है। उन्हें 30 लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की एफडीआर, बैंक गारंटी या जमानती देना होगा। अमेरिका में रहने का पूरा पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अदालत को उपलब्ध करानी होगी। वीजा सहित पूरे पासपोर्ट की सत्यापित प्रति भी जमा करनी होगी।इसके अलावा अदालत की अनुमति के बिना वह अपना वकील नहीं बदल सकेंगी। उन्हें अपनी सभी अचल संपत्तियों का विवरण शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि उन्हें 20 जुलाई 2026 तक भारत लौटकर अदालत के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

मोहाली में भी वायरल हुआ कथित जॉम्बी ड्रग वीडियो, लोगों की बढ़ी चिंता

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली

चंडीगढ़ में कथित तौर पर 'जॉम्बी ड्रग' से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद अब पंजाब के मोहाली से भी ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। करीब 31 सेकंड के इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह मोहाली के फेज-11 क्षेत्र का है। वीडियो में एक युवक सड़क के बीचों-बीच असामान्य स्थिति में लड़खड़ाते हुए चलता दिखाई दे रहा है। उसकी शारीरिक गतिविधियां सामान्य नहीं लग रही हैं, जिससे सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इस वीडियो या इससे जुड़े दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने वाले कई लोगों का दावा है कि युवक कथित तौर पर 'जॉम्बी' नामक मादक पदार्थ के प्रभाव में था। उनका कहना है कि जिस तरह की स्थिति वीडियो में दिखाई दे रही है, वह इसी तरह के नशे का परिणाम हो सकती है। हालांकि, इन दावों के समर्थन में कोई आधिकारिक साक्ष्य या जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

वीडियो के साथ एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें एक व्यक्ति दावा करता है कि वीडियो मोहाली के फेज-11 इलाके का है और सड़क पर दिखाई देने वाला युवक कथित 'जॉम्बी ड्रग' के नशे में था। लेकिन इस ऑडियो क्लिप में किए गए दावों की भी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। ऐसे में वीडियो और ऑडियो दोनों की सत्यता जांच का विषय बनी हुई है। इससे पहले चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों से भी तीन युवकों के कथित रूप से नशे की हालत में झूमते हुए वीडियो वायरल हुए थे। उन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर 'जॉम्बी ड्रग' को लेकर व्यापक चर्चा शुरू हो गई थी। हालांकि, उन मामलों में भी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने किसी विशेष मादक पदार्थ के इस्तेमाल की पुष्टि नहीं की थी। अधिकारियों ने लोगों से अपुष्ट दावों पर भरोसा न करने और जांच पूरी होने तक संयम बरतने की अपील की थी।

जीरकपुर के लोहगढ़-बिशनपुरा में जलभराव से हजारों परेशान, बरसाती पानी निकासी व्यवस्था पूरी तरह फेल

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर

मानसून की शुरुआत के साथ ही जीरकपुर के लोहगढ़ और बिशनपुरा क्षेत्र एक बार फिर जलभराव की गंभीर समस्या से जूझने लगे हैं। बरसाती पानी की उचित निकासी नहीं होने के कारण हजारों लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें कीचड़ से भर गई हैं और कई स्थानों पर कई-कई फुट तक पानी जमा हो गया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, जबकि कई इलाकों में पानी घरों के भीतर तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन और संबंधित विभाग इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं।

अंबाला-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े लोहगढ़ और बिशनपुरा इलाके तेजी से विकसित हुए रिहायशी क्षेत्र हैं। यहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लेकिन बारिश के दौरान जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। सड़कों पर जमा पानी और कीचड़ के कारण दोपहिया वाहन चालकों, पैदल यात्रियों, बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई जगह सड़कें पूरी तरह पानी में डूब जाने से लोगों को गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटना का खतरा लगातार बना रहता है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि कॉलोनियों के निर्माण के समय बिल्डरों ने जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं की। इसके चलते आज संकरी गलियों और घनी आबादी वाले इलाकों से बरसाती पानी निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बारिश होने पर पानी लंबे समय तक सड़कों पर जमा रहता है और धीरे-धीरे लोगों के घरों में प्रवेश करने लगता है। इससे घरेलू सामान, वाहन और अन्य संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। लोहगढ़ और बिशनपुरा की भौगोलिक स्थिति भी इस समस्या को और गंभीर बना देती है। दोनों गांवों के बीच से अंबाला-चंडीगढ़ राजमार्ग गुजरता है, जिसके कारण एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक पहुंचने के लिए लोगों को कई किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ता है। वीआईपी रोड, रामगढ़ भुड्डा, गाजीपुर, ढकोली और सनोली जैसे क्षेत्रों के हजारों लोग रोजाना इन्हीं मार्गों का उपयोग करते हैं। लेकिन बारिश के दौरान जलभराव के कारण इन रास्तों से गुजरना जोखिम भरा हो जाता है। कई बार वाहन बीच रास्ते में बंद हो जाते हैं और लोगों को घंटों तक जाम का सामना करना पड़ता है।

बिशनपुरा निवासी रविंदरपाल सिंह ने बताया कि इलाके में बरसाती पानी की निकासी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। हर वर्ष बारिश के दौरान कई फुट तक पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है।

डिकरी गेम ठगी गिरोह का भंडाफोड़, छह आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। थाना सदर खरड़ पुलिस ने डिकरी गेम के बहाने लोगों से ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 25 हजार रुपये नकद और तीन सोने की अंगूठियां बरामद की हैं। मामले में दो अन्य आरोपियों को भी नामजद किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह लंबे समय से लोगों को लालच देकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहा था।

◆ गेम के बहाने 75 हजार ठगने वाला गिरोह बेनकाब, छह आरोपी गिरफ्तार

यह कार्रवाई डीएसपी खरड़-1 ईशान सिंगला और थाना सदर खरड़ के एसएचओ गुरप्रीत सिंह की निगरानी में की गई। पुलिस के अनुसार दर्पण सिटी, खरड़ निवासी सिकंदर चौधरी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 जून को कुछ लोग उनकी दुकान पर पहुंचे। आरोपियों ने प्लास्टिक की डिकियों पर दांव लगाने का खेल शुरू किया और उन्हें अधिक पैसे जीतने का लालच दिया। बातचीत और चालाकी से आरोपियों ने सिकंदर को अपने झांसे में ले लिया। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपियों ने खेल के बहाने उनसे 75 हजार रुपये ठग लिए। इतना ही नहीं, उनकी एक सोने की अंगूठी भी हड़प ली। वारदात के दौरान दुकान के काउंटर पर रखी दूसरी सोने की अंगूठी भी चोरी कर आरोपी मौके से फरार हो गए।

पीजीआई न्यू ओपीडी की डीजल भट्ठी पर 40 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं, जांच लंबित

भारतेन्दु संवाददाता,चंडीगढ

चंडीगढ़ स्थित पीजीआई (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च) की न्यू ओपीडी कैंटीन में डीजल भट्ठी के इस्तेमाल का मामला सामने आने के 40 दिन बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सकी है, जिससे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, 23 मई को न्यू ओपीडी कैंटीन में डीजल भट्ठी के इस्तेमाल की शिकायत मिलने के बाद पीजीआई प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी को कैंटीन में सुरक्षा मानकों, डीजल भट्ठी के उपयोग की अनुमति और संभावित जोखिमों की जांच कर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जांच रिपोर्ट अभी तक प्रशासन को नहीं सौंपी गई है।

इस बीच अस्पताल की स्टेट ब्रांच और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी किसी प्रकार की निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कैंटीन में डीजल भट्ठी के उपयोग को लेकर कई बार सुरक्षा संबंधी चिंताएं जताई गई थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में डीजल से चलने वाली भट्ठी का उपयोग आग लगने जैसी गंभीर घटनाओं का कारण बन सकता है। ऐसे में समय रहते उचित कदम उठाना बेहद आवश्यक है।

पीजीआई की न्यू ओपीडी में प्रतिदिन हजारों मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यदि सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है तो किसी भी अप्रिय घटना का खतरा बढ़ सकता है। अस्पताल परिसर में मौजूद मरीजों, कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस मामले का जल्द समाधान जरूरी माना जा रहा है।

जनगणना के दूसरे चरण में पूछे जाएंगे 40 महत्वपूर्ण सवाल

पंचकूला और फरीदाबाद में प्री-टेस्ट शुरू होगा, इस बार जाति और डिजिटल साक्षरता सहित पूछे जाएंगे 40 सवाल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में जनगणना के दूसरे चरण की तैयारियां तेज हो गई हैं। मकानों की गणना पूरी होने के बाद अब लोगों की गणना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत सोमवार से प्री-टेस्ट के साथ होगी। इस प्री-टेस्ट के लिए पंचकूला और फरीदाबाद जिलों का चयन किया गया है। जनगणना विभाग ने 42 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उनकी ड्यूटी लगाई है। इन शिक्षकों को मेहनताना के रूप में 10-10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी या मार्च में शुरू हो सकता है।

इस बार की जनगणना कई मायनों में खास होगी। वर्ष 1931 के बाद पहली बार लोगों से उनकी जाति से संबंधित जानकारी भी जुटाई जाएगी। इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। लोगों से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें कंप्यूटर चलाना आता है, ई-मेल लिखना आता है या नहीं तथा वे स्मार्टफोन का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। प्री-टेस्ट का उद्देश्य यह पता लगाना है कि एक व्यक्ति का पूरा विवरण दर्ज करने में कितना समय लगता है, ताकि वास्तविक जनगणना के दौरान कर्मचारियों की संख्या और कार्य योजना उसी अनुसार तय की जा सके। दूसरे चरण में लोगों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें परिवार के सदस्यों की जानकारी, शिक्षा, मातृभाषा, अन्य भाषाओं का ज्ञान, धर्म, जाति, बच्चों की संख्या तथा परिवार में किसी बच्चे की मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी। इससे पहले मई माह में मकानों की गणना के दौरान 34 प्रश्न पूछे गए थे। इस बार जनगणना में बेघर लोगों को भी शामिल किया जाएगा। पाइपों, फुटपाथों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले लोगों की भी गणना की जाएगी। अंतिम दिन विशेष टीमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट पर तैनात रहेंगी ताकि कोई भी व्यक्ति जनगणना से छूट न जाए।

राज्य के प्रमुख जनगणना अधिकारी डॉ. ललित जैन ने बताया कि जहां लोगों से सहयोग नहीं मिलेगा, वहां पार्षदों और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की सहायता ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जनगणना कानून के तहत सही जानकारी देना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। गलत जानकारी देना या जानकारी देने से इनकार करना कानूनन अपराध है। इसलिए सभी नागरिकों से जनगणना टीम का पूरा सहयोग करने की अपील की गई है।

सही आंकड़ों से बनेगी बेहतर विकास नीति

जनगणना अधिकारियों के अनुसार, इस बार पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तकनीक आधारित बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। प्री-टेस्ट के दौरान यह भी परखा जाएगा कि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से आंकड़े दर्ज करने में कर्मचारियों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे वास्तविक जनगणना के दौरान तकनीकी समस्याओं को पहले ही दूर किया जा सकेगा। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों से जानकारी जुटाने में औसतन कितना समय लगता है और किन परिस्थितियों में अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ सकती है।जनगणना के आंकड़े केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, पेयजल, सड़क, बिजली और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। विभिन्न सरकारी विभागों को भविष्य की योजनाएं बनाने और संसाधनों का उचित वितरण सुनिश्चित करने में भी जनगणना के आंकड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

फरीदकोट में यूके भेजने के नाम पर 58 .50 लाख की ठगी, चार आरोपी नामजद

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदकोट

यू.के. भेजने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने के दो अलग-अलग मामलों का खुलासा हुआ है। थाना सिटी फरीदकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंग्लैंड में रह रही दो महिलाओं समेत कुल चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दोनों मामलों में आरोपियों पर कुल 58 लाख 50 हजार रुपये की ठगी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने शिकायतों की जांच के बाद संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

पहले मामले में धर्मकोट (जिला मोगा) निवासी कुलदीप कौर, संजीव सेठी, बिक्रमजीत संधू, करमजीत कौर और राज कौर ने पुलिस को शिकायत दी थी। आरोप है कि इन लोगों को यू.के. भेजने का भरोसा देकर अलग-अलग समय पर कुल 51 लाख 50 हजार रुपये वसूले गए। लेकिन न तो उन्हें विदेश भेजा गया और न ही उनकी रकम वापस की गई। शिकायत के अनुसार कुलदीप कौर से 7 लाख रुपये, संजीव सेठी से 14 लाख रुपये, बिक्रमजीत संधू से 6 लाख रुपये और 500 पाउंड, करमजीत कौर से 14 लाख रुपये तथा राज कौर से 10 लाख 50 हजार रुपये लिए गए।

दूसरे मामले में गांव पहलूवाला निवासी सुच्चा सिंह ने आरोप लगाया कि उसके बेटे को यू.के. भेजने का झांसा देकर उससे 7 लाख रुपये लिए गए। आरोप है कि न तो वीजा लगवाया गया और न ही पैसे वापस किए गए। पीड़ित ने पुलिस से न्याय की मांग की थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई।

जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने पहले मामले में गुरशरण कौर पत्नी पुष्पिंदर सिंह (वर्तमान निवासी इंग्लैंड), कुलदीप कौर पत्नी अजयपाल सिंह (जर्मन कॉलोनी, फरीदकोट, वर्तमान निवासी इंग्लैंड) और अनोख सिंह पुत्र इंदर सिंह निवासी डोगर बस्ती, फरीदकोट को नामजद किया है। वहीं दूसरे मामले में गुरशरण कौर पत्नी पुष्पिंदर सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से लोगों को विदेश भेजने का सपना दिखाकर उनसे बड़ी रकम ऐंठी। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने कई लोगों को इसी तरह झांसे में लिया था।

थाना सिटी फरीदकोट पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों की गहन जांच जारी है। जांच के दौरान जो भी नए तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे और मामले में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका की विस्तृत जांच की जा रही है।

विदेशी वीजा ठगी

लोगों को विदेश, खासकर यूके भेजने का झांसा दिया जाता था और वीजा लगवाने व बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर उनसे लाखों रुपये लेकर ठगी की जाती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

लुधियाना में सुबह की सैर के दौरान महिला की सड़क हादसे में मौत

भारतेन्दु संवाददाता, लुधियाना। महानगर के पॉश और वीआईपी इलाके मॉडल टाउन में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू स्विफ्ट डिजायर कार ने सुबह की सैर पर निकली एक महिला को बेरहमी से कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी सहेली गंभीर रूप से घायल है। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।

◆तेज रफ्तार कार हादसा

जानकारी के अनुसार, मॉडल टाउन के चार खंभा चौक क्षेत्र की रहने वाली हरप्रीत कौर अपने घर से रोजाना की तरह सुबह करीब 6 बजे अपनी सहेली के साथ टहलने निकली थीं। दोनों महिलाएं सड़क किनारे सुरक्षित चलते हुए बातचीत कर रही थीं। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक सफेद स्विफ्ट डिजायर कार ने लापरवाही से उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों महिलाएं हवा में उछलकर सड़क पर जा गिरीं। हादसे के बाद कार चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी गति और बढ़ा दी, जिससे हरप्रीत कौर कार के नीचे आ गईं और करीब 5 से 10 मीटर तक सड़क पर घसीटती चली गईं। इस दौरान उनके सिर और छाती पर गंभीर चोटें आईं।

स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों घायल महिलाओं को दीप अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हरप्रीत कौर को मृत घोषित कर दिया। उनकी सहेली की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, मृतका का परिवार पहले से ही खुशहाल जीवन जी रहा था और हाल ही में उनकी इकलौती बेटी की शादी भी हुई थी। हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही थाना मॉडल टाउन की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिए हैं और कार के नंबर व मॉडल के आधार पर आरोपी चालक की पहचान की जा रही है।

कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व विवाद गहराया

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व विवाद से असंतोष गहराया

पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। पार्टी के भीतर बढ़ती नाराजगी और असंतोष के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए अपने समर्थकों की आपात बैठक बुला ली। यह बैठक उनके मोरिंडा स्थित आवास पर हुई, जिसे पार्टी के भीतर चन्नी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। बैठक में कई मौजूदा और पूर्व विधायक सहित वरिष्ठ नेता शामिल हुए।

चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह तेज हो गई है। इस बैठक के जरिए चन्नी ने पार्टी हाईकमान को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि पंजाब में उनके समर्थन में बड़ा आधार मौजूद है।

इसी बीच पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान संगत सिंह गिलजियां ने भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह पार्टी और हाईकमान का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी दिल्ली नेतृत्व द्वारा दी गई है, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही प्रक्रिया को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है।

गिलजियां ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के चयन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, जिसकी अगुवाई अजय माकन ने की थी। इस कमेटी ने पंजाब भर के लगभग 62 से 66 नेताओं, जिनमें पूर्व मंत्री, विधायक और जिला प्रधान शामिल थे, से राय लेकर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी।

उन्होंने दावा किया कि उस रिपोर्ट में अधिकांश नेताओं और कार्यकर्ताओं की भावना के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी का नाम सबसे ऊपर था। इसके बावजूद उस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में निराशा और असंतोष का माहौल पैदा हो गया है।

गिलजियां ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पार्टी में यह अंदरूनी फूट और असंतोष जारी रहा, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी बेहद मुश्किल हो जाएगी।

फरीदकोट में 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद, तीन तस्कर फरार

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदकोट

पंजाब सरकार द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिटी-2 फरीदकोट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक कार से 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद की है। हालांकि, कार्रवाई के दौरान कार में सवार तीनों तस्कर पुलिस को देखकर वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है।

जानकारी के अनुसार, थाना सिटी-2 के प्रभारी इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम फिरोजपुर रोड स्थित एक पेट्रोल पंप के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि बलबीर बस्ती निवासी करण शर्मा अपने दो अन्य साथियों के साथ एक कार में भारी मात्रा में हेरोइन लेकर इलाके में घूम रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर दी और संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया। लेकिन कार सवार तीनों आरोपी पुलिस को देखकर वाहन सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर कार की तलाशी ली, जिसमें से 1 किलो 20 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।

झ तलाशी के दौरान पुलिस को कार से कई अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिला। इनमें एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 20 पारदर्शी प्लास्टिक लिफाफे, एक आईफोन, एक पर्स जिसमें 500 रुपये नकद, एक आधार कार्ड और वाहन से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। पुलिस ने सभी सामान और कार को कब्जे में ले लिया है।

मावां-धीयां योजना का झांसा देकर साइबर ठग बना रहे शिकार

भारतेन्दु संवाददाता,लुधियाना

पंजाब में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर 'मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना' से जुड़े संदेश और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन संदेशों में दावा किया जा रहा है कि महिलाओं और माताओं को सरकारी सहायता राशि मिलने वाली है। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं और लोगों को फर्जी लिंक भेजकर ठगी की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऐसे किसी भी संदेश या लिंक पर बिना जांच-पड़ताल के भरोसा न करें।

साइबर अपराधी मोबाइल पर व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए संदेश भेज रहे हैं कि लाभार्थी के खाते में 24 घंटे के भीतर सरकारी राशि भेजी जाएगी। इसके लिए उन्हें एक लिंक पर क्लिक कर अपनी जानकारी अपडेट करने को कहा जाता है। कई लोग सरकारी योजना का लाभ मिलने की उम्मीद में बिना सोचे-समझे लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे वे साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं।

लुधियाना पुलिस ने इस बढ़ते खतरे को देखते हुए अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक जागरूकता वीडियो जारी किया है। लगभग 35 सेकंड के इस वीडियो में साइबर क्राइम टीम के अधिकारी अमरिंदर सिंह लोगों को फर्जी लिंक और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताते नजर आते हैं। वीडियो में समझाया गया है कि साइबर अपराधी लोगों की जरूरतों और सरकारी योजनाओं के प्रति उनकी उम्मीदों का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं।

पुलिस के अनुसार, ठगों द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा वेब पेज खुलता है, जो बिल्कुल सरकारी वेबसाइट जैसा दिखाई देता है। वहां लोगों से बैंक खाता संख्या, एटीएम कार्ड की जानकारी, आधार नंबर, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड और ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारियां मांगी जाती हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति यह जानकारी भरता है, साइबर अपराधी उसके बैंक खाते तक पहुंच बना लेते हैं और खाते से पैसे निकाल सकते हैं।

जागरूकता वीडियो में लोगों से स्पष्ट अपील की गई है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या संबंधित विभाग से ही किसी योजना की जानकारी प्राप्त करें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार कभी भी व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए संदिग्ध लिंक भेजकर लाभार्थियों से बैंक संबंधी जानकारी या ओटीपी नहीं मांगती।

साइबर सेल के प्रभारी सतबीर सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, आधार नंबर, पासवर्ड या ओटीपी जैसी निजी जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यदि किसी को किसी सरकारी योजना से संबंधित संदेश प्राप्त होता है, तो पहले उसकी सत्यता आधिकारिक माध्यमों से जांच लें।

फरीदकोट जेल में तलाशी के दौरान पांच मोबाइल फोन हुए बरामद

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदकोट

केंद्रीय जेल फरीदकोट में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से चलाए गए अचानक तलाशी अभियान के दौरान पांच लावारिस मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, जेल प्रशासन और सुरक्षा गार्डों ने संयुक्त रूप से जेल की विभिन्न बैरकों में औचक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान अलग-अलग बैरकों से पांच मोबाइल फोन बरामद हुए, जो लावारिस हालत में पड़े मिले। मोबाइल फोन की बरामदगी के बाद जेल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना थाना सिटी फरीदकोट पुलिस को दी।

इस संबंध में केंद्रीय जेल के सहायक सुपरिंटेंडेंट वीरपाल सिंह द्वारा दी गई लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। रिपोर्ट में बताया गया कि जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नियमित जांच के दौरान यह मोबाइल फोन मिले।

पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जेल अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रतिबंधित मोबाइल फोन जेल परिसर के अंदर कैसे पहुंचे और इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं।

फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं की गहन जांच कर रही है, जिसमें जेल स्टाफ की भूमिका और बाहरी स्रोतों से मोबाइल फोन की आपूर्ति जैसे बिंदु भी शामिल हैं।

न्यूज ब्रीफ

एएसआई की हार्ट अटैक से ड्यूटी पर मौत

भारतेन्दु संवाददाता, अमृतसर। पंजाब में ड्यूटी के दौरान एक एएसआई की हार्ट अटैक आने से मौत हो जाने का दुखद मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार, एएसआई तरसेम लाल पुत्र बंशी राम, निवासी गांव भगतपुरा (कादियां, थाना सिविल लाइन बटाला) 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम में तैनात थे और बटाला की ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में ड्यूटी कर रहे थे। वे रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर मौजूद थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। साथ ड्यूटी कर रहे हवलदार सुरिंदर सिंह ने उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल बटाला पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अचानक हुई इस घटना से पुलिस विभाग में गहरा शोक है और साथी कर्मियों ने दिवंगत एएसआई को श्रद्धांजलि दी है।

दो युवक 62 लाख कैश के साथ गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता,गुरदासपुर। जिला गुरदासपुर पुलिस ने नियमित चेकिंग के दौरान एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दो गुजराती युवकों को 62 लाख रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों की उम्र 20 वर्ष से कम बताई जा रही है, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया है। जानकारी के अनुसार, पुलिस शहर के एंट्री पॉइंट बाबरी नाका पर नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट वाली सफेद क्रेटा कार को रुकने का इशारा किया गया। जब पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई। डीएसपी शाहबाज सिंह ने बताया कि दोनों युवक अहमदाबाद के रहने वाले हैं और बिना किसी वैध दस्तावेज के इतनी बड़ी रकम लेकर यात्रा कर रहे थे। पूछताछ के दौरान वे संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आयकर विभाग को सौंप दिया है। आयकर विभाग अब यह जांच कर रहा है कि यह 62 लाख रुपये कहां से आए और इसे कहां ले जाया जा रहा था।

जालंधर में नशे में धुत पुलिस कर्मी गाड़ी चलाते पकड़ा गया

भारतेन्दु संवाददाता, जालंधर

मकसूदां थाने के नजदीक उस समय हंगामा हो गया जब लोगों ने एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी को नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़ लिया। आरोप है कि पुलिस कर्मी इतना अधिक नशे में था कि वह अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था और डीएवी कॉलेज के पास एक नाले में वाहन समेत गिरने की स्थिति में पहुंच गया। इस दौरान उसने कई अन्य वाहनों को भी हल्की टक्कर मार दी।

घटना के समय मौजूद आरती नाम की महिला ने बताया कि पुलिस कर्मी उनकी गाड़ी से भी टकराने वाला था, लेकिन समय रहते बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने मौके पर पूरी घटना का वीडियो भी बनाया, जिसमें पुलिस कर्मी स्पष्ट रूप से नशे की हालत में दिखाई दे रहा है और सामान्य बातचीत भी नहीं कर पा रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि जो पुलिस कर्मी लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और शराब पीकर वाहन न चलाने की सीख देते हैं, वही खुद नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। लोगों ने सवाल उठाया है कि यदि इस स्थिति में कोई बड़ा हादसा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता।

वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस कर्मी इतना नशे में था कि उसे वाहन स्टार्ट करने और संभालने में भी परेशानी हो रही थी। लोगों ने मौके पर उसे रोककर स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल इस मामले में पुलिस विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग संबंधित पुलिस कर्मी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और आरोपी कर्मी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है।

स्थायी पुल निर्माण में देरी से नाराज सात गांवों के सरपंचों ने आंदोलन और इस्तीफे की दी चेतावनी

रावी पुल निर्माण में देरी पर ग्रामीण नाराज

भारतेन्दु संवाददाता, गुरदासपुर

सरपंचों ने 10 दिन में निर्माण शुरू करने की मांग की

गुरदासपुर रावी दरिया के मकोड़ा पत्तन के पार बसे सात गांवों का सड़क संपर्क एक बार फिर मुख्य भूमि से कट गया है। अस्थायी पलटून पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद संबंधित विभाग ने उसे पूरी तरह खोल दिया है, जिसके कारण अब ग्रामीणों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ रहा है। इससे लोगों की दैनिक जिंदगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर गंभीर असर पड़ा है।

गांवों के सरपंचों ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से स्थायी पुल निर्माण के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है, लेकिन पंजाब सरकार ने अब तक टेंडर प्रक्रिया शुरू नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि 10 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो सातों गांवों के सरपंच सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही जम्मू-अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया गया है।

करीब 30 वर्षों से नाव चला रहे नछत्तर सिंह ने बताया कि बरसात के मौसम में रावी का जलस्तर बढ़ने से नाव चलाना भी जोखिम भरा हो जाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों से स्थायी पुल की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। हर साल लगभग चार महीने ग्रामीण पूरी तरह नाव पर निर्भर रहते हैं।

ग्रामीणों ने वर्ष 2022 में तत्कालीन मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल द्वारा किए गए पुल निर्माण के वादे का भी उल्लेख किया। उनका कहना है कि उस समय 190 करोड़ रुपये मिलने और जल्द निर्माण शुरू होने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ।

महिलाओं और ग्रामीणों ने कहा कि तीन ओर रावी दरिया और एक ओर पाकिस्तान सीमा होने से आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं, छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, क्योंकि जलस्तर बढ़ने पर नाव सेवा बंद हो जाती है।

ग्रामीणों ने सरकार से जल्द स्थायी पुल बनाकर उनकी वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

तलवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के साथ पकड़ा आरोपी

भारतेन्दु संवाददाता, तलवाड़ा। तलवाड़ा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश की अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

जानकारी के अनुसार, एसएचओ सतपाल सिंह के निर्देश पर मुख्य सिपाही अनिल कुमार की टीम गांव चंगड़वां में शाह नहर के पुल के पास नाकाबंदी कर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति कंधे पर बोरा लेकर पैदल आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह पीछे मुड़ने लगा, जिस पर पुलिस ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान यशपाल उर्फ साबी निवासी गांव कांववाली, थाना दसूहा के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर उसके बोरे से हिमाचल प्रदेश में बिकने वाली 'संतरा' मार्का शराब की 21 बोतलें बरामद हुईं।

तरनतारन में प्रेम विवाह के बाद घर में तोड़फोड़ और आग

भारतेन्दु संवाददाता, तरनतारन

तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के गांव पंजवड़ में कोर्ट मैरिज को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है कि करीब एक दर्जन लोगों ने एक बंद घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और सामान में आग लगा दी। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। यह मामला प्रेम विवाह से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें लड़की के परिजनों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है।

जानकारी के अनुसार, गांव निवासी परगट सिंह और एक लड़की के बीच पिछले सात वर्षों से प्रेम संबंध थे। दोनों परिवारों को इस संबंध की जानकारी पहले से थी और मामला कई बार पंचायत तक भी पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौते भी हुए थे। कुछ दिन पहले परगट सिंह ने लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया।

आरोप है कि जब लड़की के परिवार को कोर्ट मैरिज की जानकारी मिली, तो गुरुवार शाम करीब एक दर्जन लोग परगट सिंह के बंद घर में घुस गए। वहां उन्होंने घर का सामान तोड़ दिया, दीवारों को नुकसान पहुंचाया और कई वस्तुओं को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान आरोपियों के पास तेजधार हथियार और दातींं भी थे, जिससे इलाके में दहशत फैल गई।

घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर परगट सिंह के परिजन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। घर में काफी नुकसान होने की बात सामने आई है। परिवार ने इस घटना की सूचना थाना झबाल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

मुलाकात रंधावा ने शाह से गैंगस्टर गतिविधियों और कानून-व्यवस्था पर चर्चा की

अमित शाह से मिले रंधावा, अटकलों पर लगाया विराम

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

बदलाव और प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जारी राजनीतिक हलचल के बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। रंधावा के दिल्ली पहुंचने के बाद विभिन्न राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे, खासकर ऐसे समय में जब कांग्रेस के भीतर असंतोष और अंदरूनी खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। मुलाकात से पहले रंधावा कुछ भाजपा नेताओं के साथ भी नजर आए, जिससे राजनीतिक अटकलों को और बल मिला।

हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुद सामने आकर इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मुलाकात पूरी तरह पंजाब के सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और गैंगस्टर गतिविधियों जैसे गंभीर मुद्दों पर केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि इस बैठक का किसी राजनीतिक समीकरण या दलगत चर्चा से कोई संबंध नहीं था।

रंधावा ने बताया कि उन्होंने विशेष रूप से गुरदासपुर और पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में बढ़ती गैंगस्टर गतिविधियों और अपराध के कारण लोगों में व्याप्त भय का मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री के समक्ष उठाया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने अमित शाह को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पंजाब में गैंगस्टर नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करने, सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने की मांग की गई। रंधावा ने कहा कि पंजाब की शांति और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इस दिशा में केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

रंधावा के अनुसार, बैठक के दौरान पंजाब के सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार इन विषयों पर गंभीरता से विचार करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी। इस मुलाकात का समय इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पंजाब कांग्रेस इन दिनों संगठनात्मक बदलावों को लेकर सुर्खियों में है।

कुतबा गांव ने सभी पार्टियों का किया बहिष्कार

भारतेन्दु संवाददाता, बरनाला

पंजाब की सियासत में चुनावी हलचल तेज होने के बीच बरनाला जिले के ऐतिहासिक गांव कुतबा से एक अनोखा और जागरूकता भरा राजनीतिक संदेश सामने आया है। आमतौर पर चुनावों के दौरान जहां गांवों में राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे और प्रचार तेज हो जाते हैं, वहीं कुतबा गांव ने इस परंपरा को चुनौती देते हुए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का खुले तौर पर विरोध किया है।

गांव की दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए पोस्टरों में कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी सहित सभी दलों को कठघरे में खड़ा किया गया है। इन पोस्टरों में केवल 'नो एंट्री' का संदेश ही नहीं है, बल्कि बीते वर्षों में पंजाब की राजनीति से जुड़े विवादों और घटनाओं का उल्लेख करते हुए तीखे सवाल भी उठाए गए हैं।

शिरोमणि अकाली दल पर लगे पोस्टरों में बरगाड़ी बेअदबी कांड, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, अकाल तख्त साहिब से जुड़े विवाद और नशे की समस्या जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पार्टी के चुनाव चिन्ह 'तराजू' पर लाल क्रॉस लगाकर विरोध दर्ज किया गया है।

आम आदमी पार्टी को लेकर लगाए गए पोस्टरों में मुख्यमंत्री भगवंत मान की तस्वीर पर लाल क्रॉस बनाकर उन्हें 'गुरु द्रोही' और 'खालसा पंथ का विरोधी' बताया गया है। साथ ही संगत से अपील की गई है कि वे वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व का समर्थन न करें।

कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए पोस्टरों में श्री दरबार साहिब (स्वर्ण मंदिर) पर हुए हमले की ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करते हुए उसे पंजाब के लिए एक बड़ा घाव बताया गया है और पार्टी के बहिष्कार का आह्वान किया गया है।

गांव के लोगों का कहना है कि वे अब केवल चुनावी नारों या वादों के आधार पर किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। उनका मानना है कि जब तक राजनीतिक दल पंजाब के हितों, धार्मिक भावनाओं और युवाओं की समस्याओं पर गंभीरता से काम नहीं करते, तब तक उन्हें गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह विरोध किसी हिंसक आंदोलन के बजाय लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का एक शांतिपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

गो-रक्षा के नारों से आगे बढ़कर गोवंश के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने का समय

भाजपा शासित राजस्थान में जैसलमेर में घटी एक अत्यंत संवेदनशील घटना ने देश के गौ भक्त समाज को झकझोर कर रख दिया। यहां के डंपिंग यार्ड में 500 से अधिक गायों के सड़े-गले शव और हड्डियां खुले में बिखरे हुए मिले पाए गए। इस जगह का दृश्य इतना भयावह व भीषण दुर्गंध पूर्ण था कि स्थानीय लोग और गौ-प्रेमी स्वभाविक रूप से इसे देखकर क्रोधित व विचलित हो गए। इनमें से कई गायों की मौत जहरीला कचरा या पॉलीथिन खाने से हुई, जबकि इनमें बड़ी संख्या में ऐसी गायों के शव भी थे जिन्हें मृत पशुओं का निस्तारण करने वाले ठेकेदार ने इसी डंपिंग यार्ड में लाकर फेंक दिया था।

इस दर्दनाक व शर्मनाक घटना ने सरकार व निजी गौ रक्ष संगठनों के गौ-रक्षा के दावों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह केवल किसी की लापरवाही मात्र का नहीं बल्कि मानवता और हिंदू आस्था दोनों के ही अपमान से जुड़ा मामला है। पिछले एक दशक से देश में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोगों को गौरक्षा के नाम पर मारा जा चुका है। मुहम्मद अखलाक और पहलू खान जैसे अनेक लोगों की हत्या की खबरें देश-विदेश के मीडिया में प्रसारित होकर देश की बदनामी का कारण भी बन चुकी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2016-17 में इन्हीं कथित गौरक्षकों के संदर्भ में यह कह भी चुके हैं कि 'गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले 70-80 प्रतिशत लोग फर्जी हैं, जो रात में गैर-कानूनी काम करते हैं और दिन में गोरक्षक का चोला पहन लेते हैं।' मोदी ने कहा था कि उन्हें उन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है जो गोरक्षा के नाम पर अपनी 'दुकानें' खोलकर बैठ गए हैं।

निर्मल रानी
सामाजिक विचारक

उन्होंने राज्य सरकारों से ऐसे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने और उनका डोजियर तैयार करने को भी कहा था। उस समय मोदी ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं की कड़ी निंदा भी की थी। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि गौ भक्ति के नाम पर लोगों की हत्या स्वीकार्य नहीं है। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। उन्होंने असली गोरक्षकों को सलाह दी थी कि उन्हें गायों को प्लास्टिक खाने से बचाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि कटने से ज्यादा गायें प्लास्टिक और कचरा खाने से मरती हैं। गाय को लेकर बने देश के इसी तनावपूर्ण वातावरण में देश के मुस्लिम समाज ने उच्च स्तर पर कहीं फतवों से तो कहीं दिशा निर्देश जारी कर भारत के मुसलमानों को यह हिदायत जारी की है कि वे गाय की हत्या व गोमांस भक्षण यदि कहीं किया जा रहा है तो उससे पूरी तरह बाज आएं। यहां तक कि देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर अनेक प्रमुख मुस्लिम उलेमाओं और संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की वकालत की है। इनके अनुसार ऐसा करने से देश में नफरत और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी, और बहुसंख्यक समाज की आस्था का सम्मान होगा। कई इस्लामी विद्वानों और मौलानाओं का तो स्पष्ट मत है कि इस्लाम में गौ मांस खाने को सख्ती से मना किया गया है। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों का हवाला देते हुए मौलानाओं द्वारा यह बताया गया है कि गाय के मांस में बीमारी है और उसके दूध में शिफा अर्थात राहत है। अनेक मुस्लिम संगठनों ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है, ताकि गाय को लेकर होने वाली सांप्रदायिक राजनीति पर पूर्ण विराम लग सके, परंतु हिंदूवादी संगठनों द्वारा गौ हत्या को लेकर केवल मुसलमानों पर निशाना साधने वालों को इसी सिक्के के दूसरे पहलू को समझना भी जरूरी है। इस संदर्भ में पिछले दिनों हुए असम चुनावों के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का वह बयान काबिलेगौर है जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार लोगों के घर के अंदर गोमांस खाने अर्थात निजी खान-पान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती।

उन्हें इसे खाने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन इसे सार्वजनिक तौर पर खाने के बजाय अपने घरों के अंदर खाना चाहिए लेकिन सार्वजनिक रूप से या धार्मिक स्थलों के आसपास इसका सेवन कानूनन और सामाजिक भावनाओं के खिलाफ है। सवाल यह है कि जब गोवध होगा तभी तो गोमांस घरों में भी खाया जा सकेगा ? गौ-रक्षा को लेकर देश में लंबे समय से राजनीति होती रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि गोमांस भक्षण केवल किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग भी इसका सेवन करते हैं। यही कारण है कि कई राजनीतिक दल और नेता समय-समय पर वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखकर विरोधाभासी बयान देते रहे हैं। वर्ष 2017 में केरल के मल्लापुरम लोकसभा उपचुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार एन. श्रीप्रकाश ने मतदाताओं से अच्छी गुणवत्ता वाले बीफ की आपूर्ति सुनिश्चित करने और आधुनिक बूचड़खाने खुलवाने का वादा किया था।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

लोकतंत्र की मजबूती केवल सरकार से नहीं बल्कि जवाबदेह विपक्ष से भी तय होती है

लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि मजबूत संस्थाओं, जागरूक जनता और सशक्त विपक्ष से मजबूत होता है। सत्ता पक्ष सरकार चलाता है, लेकिन विपक्ष लोकतंत्र का वह महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जो सरकार से सवाल पूछता है, नीतियों की समीक्षा करता है और जनता की आवाज को संसद से सड़क तक उठाने का काम करता है। इसलिए किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना उतना ही जरूरी माना जाता है जितना सरकार का मजबूत होना लेकिन आज भारत सहित कई लोकतांत्रिक देशों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है—अगर विपक्ष कमजोर हो जाए, तो क्या लोकतंत्र भी कमजोर होने लगता है?

लोकतंत्र में विपक्ष केवल विरोध करने के लिए नहीं होता। उसका असली काम सरकार को जवाबदेह बनाना होता है। जब सरकार कोई नीति लाती है, कोई कानून बनाती है या कोई फैसला लेती है, तब विपक्ष उसकी कमियों और संभावित प्रभावों पर सवाल उठाता है। इससे सरकार पर दबाव बना रहता है कि वह जनता के हित में ही काम करे। लेकिन अगर विपक्ष कमजोर हो जाए, बिखरा हुआ हो या जनता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में असफल रहे, तो सत्ता का संतुलन बिगड़ने लगता है।

सुभाष चंद कासव
राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक
कवि लेखक एवं साहित्यकार

भारत की राजनीति में एक समय ऐसा था जब संसद में बहसें बेहद गंभीर और मजबूत हुआ करती थीं। विपक्ष सरकार के हर फैसले पर गहराई से सवाल पूछता था। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं के दौर में राजनीतिक मतभेद जरूर थे, लेकिन संसद में बहस का स्तर मजबूत माना जाता था। विपक्ष केवल आलोचना नहीं करता था, बल्कि वैकल्पिक सोच और नीतियाँ भी प्रस्तुत करता था। यही स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है

लेकिन आज कई बार यह धारणा बनती दिखाई देती है कि विपक्ष या तो बिखरा हुआ है या फिर जनता के बीच मजबूत विश्वास नहीं बना पा रहा। इसका सबसे बड़ा असर यह होता है कि सरकार पर सवाल पूछने का दबाव कमजोर पड़ने लगता है। जब सत्ता को यह महसूस होने लगे कि उसके सामने कोई मजबूत चुनौती नहीं है, तब निर्णय प्रक्रिया में संतुलन कमजोर हो सकता है।

सबसे खतरनाक स्थिति तब बनती है जब जनता भी यह मानने लगे कि विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में बिना मजबूत विपक्ष के सत्ता धीरे-धीरे निरंकुश होने लगती है। अगर सरकार के हर फैसले की केवल तारीफ हो और आलोचना को देशविरोध या नकारात्मक राजनीति कहकर खारिज कर दिया जाए, तो लोकतंत्र का मूल संतुलन बिगड़ सकता है।

आज संसद में कई बार गंभीर मुद्दों से ज्यादा राजनीतिक टकराव और शोर दिखाई देता है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएँ और प्रश्नपत्र लीक जैसे मुद्दों पर जितनी गहरी चर्चा होनी चाहिए, उतनी कई बार दिखाई नहीं देती। विपक्ष अगर इन मुद्दों को लगातार और मजबूती से उठाएगा, तो जनता की आवाज भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। मजबूत विपक्ष केवल सरकार के लिए चुनौती नहीं होता, बल्कि वह जनता के लिए सुरक्षा कवच भी होता है। अगर किसी नीति से आम आदमी प्रभावित हो रहा हो, अगर किसी वर्ग की आवाज दब रही हो या अगर किसी फैसले में पारदर्शिता पर सवाल हों, तो विपक्ष ही वह मंच होता है जो इन मुद्दों को सामने लाता है। इसलिए विपक्ष का कमजोर होना केवल राजनीतिक दलों की समस्या नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। हालांकि विपक्ष की कमजोरी के पीछे केवल सत्ता पक्ष को जिम्मेदार ठहराना भी पूरी सच्चाई नहीं होगी।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

> **विश्व** में अग्रणी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश शुद्ध या दीर्घकालीन अनुसंधान की उपेक्षा नहीं कर सकता।
>
> -होमी भाभा

संपादकीय

जीएसटी संग्रह ; अर्थव्यवस्था की सकारात्मक दिशा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था को भारत की सबसे महत्वपूर्ण कर सुधार योजनाओं में से एक माना जाता है। इसका उद्देश्य पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू करना, व्यापार को सरल बनाना तथा कर संग्रह की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना था। बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून माह में लगभग 1.95 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि केवल एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, बढ़ती आर्थिक गतिविधियों और बाजार में बढ़ते विश्वास का भी स्पष्ट संकेत है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं और विभिन्न भू-राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद भारत का लगातार मजबूत कर संग्रह यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था संतुलित गति से आगे बढ़ रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कुल जीएसटी संग्रह लगभग 6.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह उपलब्धि बताती है कि देश में व्यापार, उद्योग और सेवा क्षेत्र निरंतर विस्तार कर रहे हैं। जब किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है तथा उपभोक्ता अधिक खर्च करते हैं, तब कर संग्रह स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इस दृष्टि से जून के आंकड़े भारतीय बाजार में बढ़ती सक्रियता और आर्थिक मजबूती का प्रमाण हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार बढ़ता कर संग्रह सरकार को विकास योजनाओं पर अधिक खर्च करने की क्षमता भी प्रदान करेगा।

जून माह के जीएसटी संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उपभोक्ता मांग में आई तेजी का रहा है। विशेष रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में यात्री वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। कई प्रमुख वाहन कंपनियों ने बेहतर बिक्री के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोगों की क्रय क्षमता और उपभोक्ता विश्वास दोनों मजबूत हुए हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उपयोग की वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दैनिक उपभोग की सामग्री तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों की मांग में भी वृद्धि देखने को मिली। जब बाजार में खरीदारी बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, उद्योगों को अधिक ऑर्डर मिलते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और अंततः सरकार को अधिक कर प्राप्त होता है। इसलिए जीएसटी संग्रह में वृद्धि को व्यापक आर्थिक गतिविधियों का दर्पण माना जाता है। जीएसटी संग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह कर चोरी पर नियंत्रण और कर प्रणाली की पारदर्शिता का संकेत देता है। डिजिटल भुगतान, ई-वे बिल, ई-इनवॉयसिंग और ऑनलाइन कर भुगतान जैसी व्यवस्थाओं ने कर प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया है। पहले जहां विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कर प्रणालियां होने से व्यापारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, वहीं अब एकीकृत प्रणाली ने व्यापार को सरल बनाया है। करदाताओं के लिए प्रक्रियाएं अधिक सुविधाजनक हुई हैं और सरकार को वास्तविक समय में कर संग्रह की निगरानी करने में भी आसानी हुई है। इससे कर आधार लगातार विस्तृत हो रहा है और अधिक से अधिक व्यवसाय औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं।

पिछले वर्ष सरकार ने कई वस्तुओं पर जीएसटी दरों में संशोधन किया था। विशेष रूप से कुछ वस्तुओं पर कर दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया। उस समय अनेक विशेषज्ञों ने आशंका व्यक्त की थी कि कम कर दरों के कारण सरकार के राजस्व में कमी आ सकती है। लेकिन जून के आंकड़ों ने यह साबित किया है कि संतुलित कर नीति कई बार अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। कम कर दरों के कारण वस्तुएं सस्ती हुईं, उपभोक्ताओं की खरीदारी बढ़ी और बाजार में मांग का विस्तार हुआ। अधिक बिक्री के कारण कुल कर संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। यह अनुभव बताता है कि यदि कर व्यवस्था सरल, संतुलित और उपभोक्ता हितैषी हो तो राजस्व में कमी आने के बजाय वृद्धि भी संभव है। हालांकि पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर एक समान नहीं है। विभिन्न राज्यों के जीएसटी संग्रह के आंकड़े क्षेत्रीय असमानताओं की ओर भी संकेत करते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों में कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इन राज्यों में औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार, निर्माण कार्यों तथा उपभोक्ता मांग में तेजी देखने को मिली है। दूसरी ओर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जीएसटी संग्रह में गिरावट दर्ज की गई है। यह स्थिति बताती है कि देश के कुछ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां अपेक्षित गति से नहीं बढ़ रही हैं। ऐसे राज्यों में निवेश आकर्षित करने, उद्योगों को प्रोत्साहन देने, आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

आयात से प्राप्त जीएसटी राजस्व में लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि भी अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह ऐसे समय में हुआ है जब विश्व के कई क्षेत्रों में भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अनिश्चितता बनी हुई है। इसके बावजूद भारत का आयात-निर्यात तंत्र अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। यह इस बात का संकेत है कि भारतीय उद्योगों की उत्पादन क्षमता मजबूत है और घरेलू बाजार में मांग लगातार बनी हुई है। आयात पर बढ़ा जीएसटी संग्रह यह भी दर्शाता है कि उद्योगों के लिए कच्चे माल, मशीनों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का आयात बढ़ा है, जिससे भविष्य में उत्पादन और निवेश दोनों में वृद्धि की संभावना मजबूत होती है। सरकार द्वारा हाल के वर्षों में उठाए गए कई आर्थिक कदम भी इस सकारात्मक वातावरण के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। आयकर में राहत, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डों और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर निवेश ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। इसके अलावा 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन ने भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया है।

-शिवांश धाकड़

मृत्यु के बाद क्या होता है? विज्ञान और निकट-मृत्यु अनुभवों के बीच अनसुलझे रहस्य की पड़ताल

मृत्यु मानव जीवन का सबसे बड़ा और रहस्यमयी सत्य है। सदियों से मनुष्य यह जानने की कोशिश करता आया है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या चेतना शरीर के समाप्त होने के साथ खत्म हो जाती है या फिर आत्मा किसी अन्य रूप में अस्तित्व बनाए रखती है? आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म दोनों इस प्रश्न का उत्तर खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन आज भी यह एक अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली बनी हुई है।

प्रो. मनोज डोगरा
राजकीय महाविद्यालय
बड़सर

पिछले कुछ दशकों में 'नियर डेथ एक्सपीरियंस' यानी मृत्यु के करीब के अनुभवों पर गंभीर शोध हुए हैं। कई ऐसे लोग, जिन्हें चिकित्सकीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया था और बाद में पुनर्जीवित किया गया, उन्होंने विचित्र अनुभव साझा किए। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा, तेज प्रकाश का अनुभव किया या किसी अदृश्य शक्ति की उपस्थिति महसूस की। इन अनुभवों ने वैज्ञानिकों और पैरासाइकोलॉजिस्टों दोनों को सोचने पर मजबूर किया। वैज्ञानिकों के अनुसार मृत्यु कोई एक क्षण नहीं, बल्कि एक प्र्,या है। जब हृदय धड़कना बंद कर देता है, तब शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। धीरे-धीरे कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और मस्तिष्क की गतिविधियां समाप्त होने लगती हैं। लेकिन आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित किया है कि कई मामलों में इस प्र्,या को कुछ समय तक उलटा भी जा सकता है। सीपीआर, डिफिब्रिलेशन और आधुनिक जीवन रक्षक तकनीकों की मदद से ऐसे अनेक मरीजों को घंटों बाद भी जीवित किया गया है, जिन्हें मृत माना जा चुका था।

2011 में जापान में एक युवती को ड्रग्स ओवरडोज के कारण छह घंटे बाद पुनर्जीवित किया गया। 2019 में ब्रिटेन की ऑड्रे शोमैन नामक महिला छह घंटे तक कार्डियक अरेस्ट में रहने के बाद जीवित बच गईं। ऐसे उदाहरण बताते हैं कि मृत्यु की वैज्ञानिक परिभाषा उतनी सरल नहीं जितनी पहले मानी जाती थी। इसी आधार पर कुछ पैरासाइकोलॉजिस्ट यह तर्क देते हैं कि चेतना केवल मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकती।

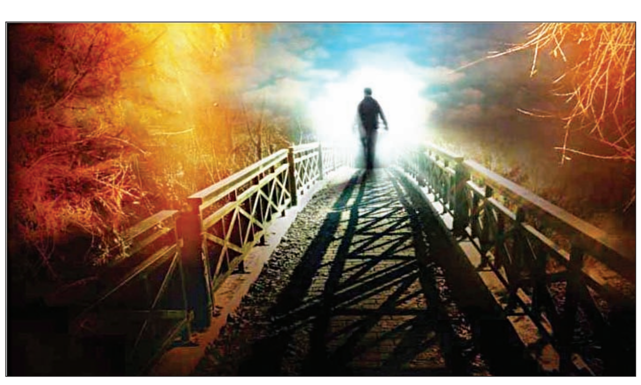

उनका मानना है कि जब मस्तिष्क की गतिविधि बंद हो जाती है, तब भी व्यक्ति किसी प्रकार के अनुभव करता है। कुछ वैज्ञानिक चेतना को 'नॉन-लोकल' शक्ति मानते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है और मस्तिष्क केवल उसे ग्रहण करने का माध्यम है। अध्यात्म भी आत्मा को अमर मानता है। श्रीमद्भगवद्गीता में आत्मा को नित्य, अजर और अमर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मृत्यु को प्राप्त होती है; यह केवल शरीर बदलती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र धारण करता है। इस दृष्टिकोण में शरीर एक साधन मात्र है, जबकि आत्मा शाश्वत चेतना का स्वरूप है। रामायण सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जीवन, मृत्यु और मोक्ष को इसी व्यापक आध्यात्मिक दृष्टि से समझाया गया है, जहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन माना गया है।

इसी विश्वास के कारण हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए प्रार्थनाएं एवं कर्मकांड किए जाते हैं। दूसरी ओर, आधुनिक विज्ञान अभी तक आत्मा के अस्तित्व को किसी प्रयोग या प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं कर पाया है। हालांकि चेतना और मृत्यु की प्र्,या पर लगातार शोध हो रहे हैं, विशेषकर न्यूरोसाइंस और मेडिकल साइंस के क्षेत्र में।

नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसे मामलों ने इस बहस को और गहरा किया है कि क्या चेतना केवल मस्तिष्क की गतिविधियों तक सीमित है या उससे परे भी उसका कोई अस्तित्व हो सकता है।

वास्तव में मृत्यु का रहस्य आज भी विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म के बीच गहन शोध और विमर्श का विषय बना हुआ है। आधुनिक चिकित्सा ने जीवन बचाने की अनेक नई तकनीकें विकसित कर ली हैं, वहीं चेतना की प्रकृति को लेकर अभी भी कई प्रश्न अनुत्तरित हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में तंत्रिका विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान मानव मस्तिष्क और चेतना के संबंध को अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर, आध्यात्मिक परंपराएं यह मानती हैं कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के शाश्वत चक्र का हिस्सा हैं तथा मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत है। यही कारण है कि विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में मृत्यु को लेकर अलग-अलग मान्यताएं होने के बावजूद उसके प्रति सम्मान और गंभीरता का भाव समान रूप से दिखाई देता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

सशक्त व्यक्तित्व की मिसाल है नीना गुप्ता

नीना गुप्ता

नीना गुप्ता का जन्म 4 जुलाई 1959 को दिल्ली में हुआ। वह हिंदी सिनेमा और टेलीविजन जगत की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी स्वाभाविक अभिनय शैली, सशक्त व्यक्तित्व और विविध भूमिकाओं के माध्यम से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई है।

अभिनय के साथ-साथ उन्होंने टेलीविजन निर्देशन, फिल्म निर्माण और रचनात्मक कार्यों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। अपने लंबे करियर में उन्होंने यह साबित किया कि प्रतिभा और समर्पण के बल पर किसी भी कलाकार के लिए उम्र कभी बाधा नहीं बनती। नीना गुप्ता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में पूरी की और बाद में अभिनय की दुनिया में कदम रखा।

कविता

भारत को महान बनाना है

प्रवीण कुमार, गांव बाडां दा घाट, डाकघर लेहड़ी सरेल, जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

भारत को महान बनाना है, हर तरफ भ्रष्टाचार है, बढ़ता जा रहा अनाचार है कहीं अत्याचार है, तो कहीं व्यभिचार है, फिर भी मेरा भारत महान है। हम भारतवासी पर विदेशी पहनावे, विदेशी रहन-सहन, विदेशी संस्कृति से ही जाने हमें क्यों प्यार है, फिर भी मेरा भारत महान। पश्चिम की नकल में तन पर वस्त्र कम होते जा रहे, नग्नता का फूहड नाच,अब तो प्रत्यक्ष दिख रहा, फिर भी मेरा भारत महान। नेता भूले हैं देश और देशहित, देशसेवा का भाव नहीं, नेता अब प्रजापालक नहीं रहे, निजहित ही साधने में लगे हैं फिर कैसे हो मेरा भारत महान। कोई लड़ रहा जाति के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई क्षेत्र के नाम पर, फिर भी मेरा भारत महान। गुणवत्ता की किसे परवाह है, स्वहित साध लिया जाए। तो देश से क्या लेना देना, तभी टैलेंटेड भी जा रहे विदेश, फिर भी मेरा भारत महान। निश्चित रूप से हमने श्रेष्ठ चिंतन को छोड़ा है, अवनति की ओर, अपने जीवन को मोड़ा है, निकृष्ट हो गए हैं हम, अपनी संस्कृति को कर आत्मसात, विकृत सोच एवं तुच्छ मनोवृति से, हर भारतीय को बचाना है, हमें भारत को महान बनाना है।

मोबाइल से पुस्तकालय तक, ई-पुस्तकों ने बनाया अध्ययन आसान

विश्व ई-पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस डिजिटल पुस्तकों अर्थात ई-पुस्तकों के महत्व, उनके बढ़ते उपयोग और पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर्पित है। आधुनिक समय में तकनीक ने शिक्षा, ज्ञान और सूचना प्राप्त करने के तरीकों में बड़ा परिवर्तन किया है। अब पुस्तकें केवल कागज़ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप और ई-पाठक उपकरणों के माध्यम से कहीं भी और कभी भी पढ़ी जा सकती हैं। ई-पुस्तकों ने ज्ञान को अधिक सुलभ, किफायती और सुविधाजनक बना दिया है। यही कारण है कि विश्व ई-पुस्तक दिवस आज के डिजिटल युग में विशेष महत्व रखता है।

सुरेश कुमार
प्रबंध निदेशक, कॉन्वेंट
सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुल्लू

ई-पुस्तक का अर्थ है ऐसी पुस्तक जो डिजिटल रूप में उपलब्ध होती है और जिसे किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सहायता से पढ़ा जा सकता है। इसमें उपन्यास, कहानी, कविता, पाठ्यपुस्तक, शोध सामग्री, पत्रिकाएँ, संदर्भ ग्रंथ और अन्य अनेक प्रकार की सामग्री सम्मिलित होती है। इंटरनेट के विस्तार और स्मार्ट उपकरणों की उपलब्धता ने ई-पुस्तकों को लाखों लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया है। अब किसी पुस्तक को प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय या पुस्तक विक्रेता के पास जाना अनिवार्य नहीं रह गया है। कुछ ही क्षणों में पुस्तक डाउनलोड कर पढ़ना संभव हो गया है।

विश्व ई-पुस्तक दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा ज्ञान को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुँचाना है। यह दिवस विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं, लेखकों और सामान्य पाठकों को यह संदेश देता है कि आधुनिक तकनीक का उपयोग शिक्षा और ज्ञानार्जन के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। साथ ही यह दिन लेखकों और प्रकाशकों को भी डिजिटल माध्यमों को अपनाने तथा अपनी पुस्तकों को अधिक से अधिक पाठकों तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है।

ई-पुस्तकों का सबसे बड़ा लाभ उनकी सरल उपलब्धता है। एक छोटे से उपकरण में हजारों पुस्तकें सुरक्षित रखी जा सकती हैं। इससे पुस्तकों को साथ लेकर चलने की कठिनाई समाप्त हो जाती है। विद्यार्थी अपनी पाठ्य सामग्री, प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें और संदर्भ सामग्री एक ही उपकरण में सुरक्षित रख सकते हैं। यात्रा के दौरान, घर पर, विद्यालय में या किसी भी स्थान पर पढ़ाई जारी रखना संभव हो जाता है। यही सुविधा ई-पुस्तकों को आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है।

ई-पुस्तकों का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ उनकी कम लागत है। अनेक डिजिटल पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध होती हैं, जबकि कई पुस्तकों का मूल्य मुद्रित संस्करण की तुलना में कम होता है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों और पाठकों को भी गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री प्राप्त करने में सहायता मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ई-पुस्तकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी ई-पुस्तकों का विशेष महत्व है। कागज़ की पुस्तकों के निर्माण में बड़ी मात्रा में लकड़ी, पानी और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि डिजिटल पुस्तकों का संतुलित उपयोग बढ़ता है, तो कागज़ की खपत कम हो सकती है, जिससे वृक्षों के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता मिलती है। हालाँकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण और उपयोग का भी पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए दोनों माध्यमों का संतुलित उपयोग ही सबसे उचित माना जाता है।

शिक्षा के क्षेत्र में ई-पुस्तकों ने नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिजिटल अध्ययन सामग्री का उपयोग तेजी से बढ़ा है। दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ई-पुस्तकें अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई हैं। महामारी के समय जब विद्यालय और पुस्तकालय बंद थे, तब ई-पुस्तकों ने विद्यार्थियों की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अनुभव ने डिजिटल शिक्षा की उपयोगिता को और अधिक स्पष्ट किया।

ई-पुस्तकों में कई ऐसी सुविधाएँ होती हैं जो पारंपरिक पुस्तकों में उपलब्ध नहीं होतीं। पाठक शब्द खोज सकते हैं, महत्वपूर्ण अंशों को चिह्नित कर सकते हैं, टिप्पणी लिख सकते हैं तथा आवश्यकता के अनुसार अक्षरों का आकार बदल सकते हैं। दृष्टिबाधित लोगों के लिए कई ई-पुस्तकों में ध्वनि के माध्यम से पढ़ने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। इस प्रकार डिजिटल पुस्तकें समावेशी शिक्षा को भी प्रोत्साहित करती हैं।

यद्यपि ई-पुस्तकों के अनेक लाभ हैं, फिर भी कुछ चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ने से आँखों में थकान हो सकती है। सभी लोगों के पास आधुनिक उपकरण या तेज़ इंटरनेट उपलब्ध नहीं होता। कई क्षेत्रों में डिजिटल संसाधनों की कमी के कारण ई-पुस्तकों का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता। इसके अतिरिक्त डिजिटल सामग्री की सुरक्षा, अनधिकृत प्रतिलिपि और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा भी महत्वपूर्ण विषय हैं। इसलिए तकनीकी विकास के साथ इन चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक है।

आज अनेक विद्यालय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और शैक्षणिक संस्थान अपने डिजिटल पुस्तकालय विकसित कर रहे हैं। विद्यार्थी अब ऑनलाइन माध्यम से हजारों पुस्तकों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी ई-पुस्तकें अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही हैं, क्योंकि वे नवीनतम अध्ययन सामग्री शीघ्रता से उपलब्ध कराती हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

छह माह में 141 मामलों में 203 को मिली सजा

एजेंसी, उरई

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ितों को समय पर न्याय दिलाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जालौन पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। पिछले छह महीनों के दौरान पुलिस की प्रभावी विवेचना, अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों की सटीक प्रस्तुति के चलते न्यायालय ने 141 मामलों में 203 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए विभिन्न अवधियों की सजा और अर्थदंड से दंडित किया है। इस उपलब्धि को पुलिस विभाग कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ी सफलता मान रहा है।

शुक्रवार को पुलिस विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत ऐसे मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है, जिनमें पर्याप्त और मजबूत साक्ष्य उपलब्ध हों तथा जिनकी सुनवाई शीघ्र कराकर दोषियों को सजा दिलाई जा सके। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को जल्द न्यायिक दंड दिलाना, पीड़ितों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास मजबूत करना तथा समाज में कानून का भय बनाए रखना है।

जालौन पुलिस ने इस अभियान के दौरान अभियोजन विभाग के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया। प्रत्येक मामले की गहन समीक्षा की गई और विवेचना अधिकारियों ने साक्ष्यों को वैज्ञानिक एवं कानूनी तरीके से संकलित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इसी का परिणाम रहा कि बड़ी संख्या में मामलों में न्यायालय ने दोष सिद्ध मानते हुए अभियुक्तों को सजा सुनाई।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, चोरी, महिला अपराध, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामले तथा अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी की गई। पुलिस अधिकारियों ने समय-समय पर केस डायरी, गवाहों के बयान और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा कर यह सुनिश्चित किया कि न्यायालय में किसी प्रकार की कमी न रह जाए।

पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने कहा कि अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उन्हें सजा दिलाना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी।

एटा हादसा : कंटेनर टक्कर से पांच यात्रियों की दर्दनाक मौत

बागवाला क्षेत्र में खड़ी बस से टकराया कंटेनर, पांच की मौत और ग्यारह यात्री गंभीर रूप से हुए घायल

एजेंसी, एटा

एटा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में कंटेनर की टक्कर से पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग घायल हो गए। हादसा बागवाला थाना क्षेत्र में उस समय हुआ जब सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बागवाला थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के एक भीषण सड़क दुर्घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। कीलरमाऊ गांव के पास यह हादसा उस समय हुआ जब खराब होकर सड़क किनारे खड़ी एक रोडवेज बस में पीछे से तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के बाहर खड़े कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बागवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल एटा स्थित वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बुलंदशहर निवासी सतेंद्र (38), फर्रुखाबाद निवासी राजेश (34), सुखराम (30), शैलेश (29) और एक अज्ञात व्यक्ति के रूप में हुई है। वहीं इस हादसे में 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें आनंद (52) निवासी नोएडा, विवेक (30), पूनम (32), विक्रांत (23), सुमित, नीतीश (30), विशाल (15), रवि (17), यतेंद्र (27), दक्ष (10), रिशु (21) और ब्रजेश (24) शामिल हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है।

कंटेनर की टक्कर से बस यात्रियों की मौत, जांच में तेज रफ्तार लापरवाही आई सामने

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रोडवेज बस दिल्ली जा रही थी और तकनीकी खराबी के कारण सड़क किनारे खड़ी थी। कुछ यात्री बस से उतरकर बाहर खड़े थे, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए कंटेनर ने बस में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे की सूचना पर जिलाधिकारी अरविंद सिंह और एसएसपी डॉ. इलामारन जी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल कराया।

जिलाधिकारी ने बताया कि हादसे की जांच कराई जा रही है और लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मृतक राजेश के परिजनों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है।यह दर्दनाक हादसा एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

न्यूज ब्रीफ

मखाना खेती प्रशिक्षण से बढ़ेगी किसानों की आय

एजेंसी, प्रयागराज। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही हैं। इसी क्रम में प्रयागराज के किसानों के लिए मखाना की वैज्ञानिक खेती अपनाने का सुनहरा अवसर उपलब्ध कराया गया है। उद्यान विभाग की ओर से मखाना विकास योजना के तहत 4 और 5 जुलाई को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों को मखाना की आधुनिक खेती, उत्पादन तकनीक, रखरखाव और विपणन की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम ने बताया कि इच्छुक किसान इस प्रशिक्षण का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम उपयुक्त कृषि भूमि होना आवश्यक है तथा उसे औद्यानिक फसलों की प्रारंभिक जानकारी भी होनी चाहिए। किसानों को निर्धारित पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद सात दिनों के भीतर आधार कार्ड, खतौनी, बैंक पासबुक और फोटो सहित आवश्यक दस्तावेज जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करने होंगे। लाभार्थियों का चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण में भाग लेकर मखाना की लाभकारी खेती अपनाने की अपील की।

ट्यूबवेल चोरी गिरोह के चार आरोपी गिरफ्तार

एजेंसी, बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कोतवाली नगर पुलिस ने ट्यूबवेल से मोटर स्टार्टर, लोहे की पाइप, केबल तार और अन्य सामान चोरी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई। पुलिस के अनुसार ग्राम मवई बुजुर्ग निवासी अनुरुद्ध प्रताप ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 जून की रात अज्ञात चोरों ने उनके ट्यूबवेल का ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, सिंचाई में इस्तेमाल होने वाली पाइप और अन्य सामग्री में आग भी लगा दी गई। मामले की जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक मवई चौराहे के पास एक कबाड़ की दुकान पर लोहे की पाइप बेचने पहुंचे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात स्वीकार करते हुए बताया कि केबल से तांबा निकालने के लिए उन्होंने तारों को आग लगाकर जलाया था। उन्होंने यह भी कबूल किया कि वे रात के समय सुनसान स्थानों और खाली मकानों को निशाना बनाकर चोरी करते थे। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ कर रही है।

लोधेश्वर मेले की तैयारियों में जुटा प्रशासन

एजेंसी, बाराबंकी। श्रावण मास में 25 जुलाई से 23 अगस्त तक आयोजित होने वाले ऐतिहासिक श्री लोधेश्वर महादेव मेले की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक कार्ययोजना तैयार कर ली है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी विभागों को समयबद्ध ढंग से व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, यातायात, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति और कानून-व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रशासन के अनुसार श्रावण मास में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को चार जोन और नौ सेक्टर में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक जोन और सेक्टर में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिकारियों की तैनाती रहेगी। मेला क्षेत्र में पेयजल, शौचालय, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग और साफ-सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग को अस्थायी चिकित्सालय, एम्बुलेंस और चिकित्सकीय टीमों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने कांवड़ मार्ग पर विशेष सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, नियमित गश्त और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए।

रूफटॉप सौर ऊर्जा में उत्तर प्रदेश बना अव्वल

एजेंसी,लखनऊ। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने घरेलू रूफटॉप सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जून 2026 में राज्य में 71,888 घरेलू रूफटॉप सौर संयंत्र स्थापित किए गए, जो किसी भी राज्य का एक माह का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अब तक प्रदेश में 10.89 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं और 6.36 लाख से अधिक सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। इससे 2,148 मेगावाट से अधिक क्षमता विकसित हुई है तथा 5,500 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी उपभोक्ताओं को दी गई है।

उत्तर प्रदेश में महापुरुषों की प्रतिमाएं बनीं सांस्कृतिक चेतना और प्रेरणा का स्त्रोत

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि महापुरुषों की प्रतिमाएं केवल कलात्मक संरचनाएं नहीं, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का अमर स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य इन प्रतिमाओं के माध्यम से युवाओं को देश के गौरवशाली इतिहास, त्याग, शौर्य और सामाजिक समरसता के मूल्यों से जोड़ना है।

मंत्री ने शुक्रवार को बताया कि पिछले पांच वर्षों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लगभग 43 महापुरुषों, राष्ट्रनायकों और संत-महात्माओं की प्रतिमाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इसके अलावा 14 प्रतिमाएं पूरी होकर स्थापना के लिए तैयार हैं, जबकि 17 अन्य प्रतिमाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने बताया कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर नायकों की साढ़े बारह फीट ऊंची अश्वारोही कांस्य प्रतिमाएं विभिन्न जनपदों में स्थापित की जा रही हैं। कई स्थानों पर इनके निर्माण और स्थापना की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

प्रतिमाएं राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना और प्रेरणा का अमर स्रोत हैं

लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65-65 फीट ऊंची प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो राष्ट्रवाद और सुशासन के प्रतीक के रूप में देखी जा रही हैं। इसके साथ ही प्रयागराज, मैनपुरी और अन्य जिलों में भी इन महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। उन्होंने बताया कि भगवान श्रीराम और निषादराज के ऐतिहासिक मिलन को दर्शाती 51 फीट ऊंची प्रतिमा प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में स्थापित की गई है, जबकि महाराजा सुहेलदेव की 40 फीट ऊंची अश्वारोही प्रतिमा बहराइच में स्थापित की जा चुकी है।

वाराणसी घाटों पर फूल बेचने वाले बच्चों की शिक्षा पर मंत्री चिंतित

एजेंसी,वाराणसी । वाराणसी में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने गंगा घाटों का निरीक्षण करते हुए फूल-माला बेचने वाले बच्चों की शिक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई और अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने शुक्रवार को वाराणसी प्रवास के दौरान गंगा नदी के किनारे स्थित घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घाटों पर फूल-माला बेचकर जीवनयापन कर रहे बच्चों को देखा और उनसे बातचीत की। बच्चों द्वारा स्कूल न जाने और शिक्षा से वंचित रहने की जानकारी मिलने पर मंत्री ने गहरी चिंता व्यक्त की और तत्काल संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे सभी बच्चों की पहचान कर उन्हें निकटतम बेसिक शिक्षा विद्यालयों से जोड़ा जाए। साथ ही उनके अभिभावकों से संवाद कर उन्हें शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि बच्चों का नियमित नामांकन सुनिश्चित हो सके।

निरीक्षण के दौरान मंत्री ने नाव से गंगा नदी की भव्यता और काशी के अविनाशी स्वरूप का अवलोकन किया। उन्होंने बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया और उसकी भव्यता की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने घाटों पर मौजूद पर्यटकों से बातचीत कर उनकी सुविधाओं और अनुभवों की जानकारी ली। रजनी तिवारी ने कहा कि सरकार बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की गुणवत्ता सुधारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।

कानपुर मेट्रो निर्माण से जलभराव पर विधायक ने काम रुकवाने की दी चेतावनी

एजेंसी, कानपुर

कानपुर में मेट्रो निर्माण कार्य के कारण उत्पन्न जलभराव की समस्या को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर तनाव बढ़ गया है। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सात दिनों के भीतर जलनिकासी व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो मेट्रो का काम रुकवाया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

विधायक ने यह बयान शुक्रवार को नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय के साथ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के दौरान दिया। लगातार बारिश के कारण गोविंद नगर क्षेत्र के कई हिस्सों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई है, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण के दौरान विधायक ने लोगों से बातचीत कर समस्याओं की जानकारी ली और नगर निगम अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान देवकी सिनेमा परिसर के पास मुख्य नाला क्षतिग्रस्त पाया गया, जिसके कारण गंदा पानी बैकफ्लो होकर दुकानों और घरों में घुस रहा था। स्थिति को देखते हुए विधायक ने मेट्रो परियोजना के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा

◆ मेट्रो निर्माण से जलभराव पर विधायक ने दिया सात दिन का अल्टीमेटम

कि निर्माण कार्य के दौरान जलनिकासी व्यवस्था को प्रभावित नहीं होना चाहिए था, लेकिन लापरवाही के कारण जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक ने मेट्रो अधिकारियों को सात दिन का अंतिम अल्टीमेटम देते हुए कहा कि नाला, सीवर और जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान तुरंत किया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेट्रो अधिकारियों ने सुधार कार्य के लिए समय मांगा है। निरीक्षण के दौरान नगर निगम, जल संस्थान और मेट्रो विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों ने भी जलभराव की समस्या को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और जल्द समाधान की मांग की।

सरयू नदी में पलटी नाव, लाइफ जैकेट से बची पांचों लोगों की जान

एजेंसी, गोरखपुर

गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित मुक्तिपथ घाट पर सरयू नदी (घाघरा) में शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया, जब एक प्राइवेट मोटर बोट लकड़ी की नाव से टकराकर पलट गई। नाव पर सवार पांच लोगों की जान उस समय संकट में पड़ गई, लेकिन लाइफ जैकेट पहने होने के कारण सभी की जान बच गई। जानकारी के अनुसार यह घटना सुबह करीब 10:45 बजे हुई, जब सरयू नदी में एक मोटर बोट सवारी लेकर जा रही थी। इसी दौरान बोट का संतुलन बिगड़ गया और वह सामने आ रही लकड़ी की नाव से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोट में सवार लोग पानी में गिर गए और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई।

घाट पर मौजूद स्थानीय नाविकों और आपदा मित्रों ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। सभी पांचों सवारों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान कुछ लोगों को हल्की चोटें आईं, जिन्हें तत्काल बड़हलगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।

प्रशासन की ओर से पहले से ही घाटों पर आपदा मित्रों की तैनाती की गई है, जो लगातार यात्रियों और नाविकों को सुरक्षा नियमों के पालन के लिए जागरूक करते रहते हैं। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की निगरानी में यह आपदा प्रबंधन व्यवस्था संचालित की जा रही है।

मुक्तिपथ घाट पर तैनात आपदा मित्रों ने बताया कि वे लगातार यात्रियों से लाइफ जैकेट पहनने की अपील करते हैं और नाव चालकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना लाइफ जैकेट किसी को भी सवारी न कराएं। प्रशासन द्वारा सभी मोटर बोट चालकों को निशुल्क लाइफ जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं।

इस घटना के बाद प्रशासन ने एक बार फिर लोगों से अपील की है कि नदी में यात्रा करते समय पूरी सावधानी बरतें और सुरक्षा नियमों का पालन अवश्य करें। अधिकारियों ने कहा कि यदि सभी यात्री सुरक्षा उपकरणों का सही उपयोग करें, तो इस तरह की दुर्घटनाओं से बड़ी जनहानि को आसानी से रोका जा सकता है।

सुलतानपुर पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश सहित तीन घायल, एक गिरफ्तार

एजेंसी, सुलतानपुर

सुलतानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50 हजार के इनामी बदमाश सहित तीन आरोपित घायल हो गए, जबकि चौथे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 11 लाख रुपये नकद, तीन अवैध तमंचे, 22 जिंदा कारतूस, एक जीप कंपास और कुछ ज्वेलरी बरामद की है।

अपर पुलिस अधीक्षक वृजनरायण सिंह ने बताया कि जिले में चोरी और नकबजनी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार गश्त और चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में थाना जयसिंहपुर पुलिस बीती रात लगभग 3 बजे पीढ़ी टोल के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक जीप कंपास में इलाके में घूम रहे हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय भागने की कोशिश की।

भागते समय बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें तीन बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों की पहचान अनिकेत चौहान, आकाश, मिथलेश चौहान और अजय के रूप में हुई है। इनमें अनिकेत चौहान 50 हजार का इनामी बदमाश बताया जा रहा है और उस पर करीब 52 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अन्य आरोपियों पर भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए सीएचसी जयसिंहपुर भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं चौथे आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

श्रद्धांजलि क्षेत्र में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सांसदों, विधायकों और स्थानीय लोगों ने भी लिया भाग

अंसारी परिवार ने शहीद ब्रिगेडियर उस्मान को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

एजेंसी, मऊ

जनपद के घोसी कोतवाली क्षेत्र स्थित बपुर गांव में शहीद ब्रिगेडियर उस्मान की 78वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अंसारी परिवार सहित कई जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया।

कार्यक्रम में शहीद ब्रिगेडियर उस्मान के शौर्य, देशभक्ति और राष्ट्र सेवा में दिए गए योगदान को स्मरण किया गया। उपस्थित लोगों ने कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।

श्रद्धांजलि सभा में आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी, मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी, उनके छोटे भाई उमर अंसारी सहित समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय नागरिकों ने भी कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर भाग लिया और शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित किए।

वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि ब्रिगेडियर उस्मान का जीवन देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा का आदर्श उदाहरण है। उन्होंने अपने सैन्य जीवन में जिस साहस और समर्पण का परिचय दिया, वह भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ऐसे वीर सपूतों के कारण ही देश सुरक्षित और मजबूत है। अंसारी परिवार ने कार्यक्रम में कहा कि उनका परिवार शहीद ब्रिगेडियर उस्मान से पारिवारिक संबंधों को लेकर गौरव महसूस करता है। इसी भावनात्मक जुड़ाव के कारण हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उनके आदर्शों और बलिदान को समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है।

सभा के दौरान वातावरण पूरी तरह देशभक्ति से ओतप्रोत रहा। उपस्थित लोगों ने एक स्वर में शहीद के बताए मार्ग पर चलने और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। अंत में सभी ने ब्रिगेडियर उस्मान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और 'शहीद अमर रहें' के नारों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने सभी अतिथियों और उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं।

मुरादाबाद में जोनल टैक्स फेडरेशन ने जीएसटी पेनाल्टी की उठाई मांग

एजेंसी, मुरादाबाद

मुरादाबाद में जोनल टैक्स फेडरेशन ने राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-1 अशोक कुमार सिंह से मुलाकात कर जीएसटी से जुड़े प्रावधानों में सुधार की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि धारा 125 के तहत छोटे व्यापारियों पर लगाई जा रही अधिकतम 25,000 से 50,000 रुपये तक की पेनाल्टी अत्यधिक है और इससे व्यापारियों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

फेडरेशन के अध्यक्ष जहीर मालिक ने एडिशनल कमिश्नर को अवगत कराया कि कई मामलों में विभागीय अधिकारी अधिकतम पेनाल्टी लगा रहे हैं, जबकि इसे न्यूनतम स्तर पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि पेनाल्टी राशि 1,000 से 2,000 रुपये तक सीमित की जाए, ताकि छोटे व्यापारियों को राहत मिल सके और कर व्यवस्था अधिक व्यापार हितैषी बन सके।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी मांग रखी कि सभी नोटिस ऑफलाइन माध्यम से भेजे जाएं और उनकी भौतिक प्राप्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे व्यापारी समय पर जवाब दे सकें और किसी प्रकार की असुविधा न हो। साथ ही पुराने एकपक्षीय वैट मामलों को दोबारा खोलने तथा बिना बकाया मांग के बैंक खातों को फ्रीज न करने की भी मांग की गई।

◆ जोनल टैक्स फेडरेशन ने जीएसटी में न्यूनतम पेनाल्टी लगाने की मांग की

इस मौके पर फेडरेशन के संस्थापक चेयरमैन गुफरान माजिद, महासचिव क्षितिज शर्मा, अंजार हुसैन और गौरव गुप्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। एडिशनल कमिश्नर ने प्रतिनिधिमंडल की सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि धारा 125 के अंतर्गत न्यूनतम पेनाल्टी लगाने और व्यापारियों के हित में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि विभाग की कोशिश रहेगी कि कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल हो।

नारनौल से रोहतक तक सीधी ट्रेन सेवा से यात्रियों को बड़ी मिली राहत

भारतेंदु संवाददाता, नारनौल

उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मदार-रेवाड़ी-मदार स्पेशल रेलसेवा का अस्थायी रूप से रोहतक तक विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से दक्षिण हरियाणा के यात्रियों को बिना ट्रेन बदले सीधे रोहतक तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से नारनौल, निजामपुर, अटेली, कुंड और रेवाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए राहत लेकर आई है।

रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन संख्या 09639 मदार-रोहतक स्पेशल प्रतिदिन सुबह 4:30 बजे मदार से रवाना होगी। यह ट्रेन किशनगढ़, फुलेरा, रींगस, नीमकाथाना, निजामपुर, नारनौल, अटेली और कुंड होते हुए सुबह 10:30 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। यहां 20 मिनट के ठहराव के बाद यह ट्रेन आगे झज्जर, अस्थल बोहर के रास्ते दोपहर 12:50 बजे रोहतक पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 09640 रोहतक-मदार स्पेशल प्रतिदिन दोपहर 1:20 बजे रोहतक से रवाना होगी। यह झज्जर, पाल्हावास और गोकलगढ़ के रास्ते 3:20 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी और 10 मिनट के ठहराव के बाद आगे कुंड, अटेली, नारनौल, निजामपुर, डाबला, नीमकाथाना, रींगस, फुलेरा और किशनगढ़ होते हुए रात 10:35 बजे मदार पहुंचेगी।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह विस्तारित सेवा केवल 3 जुलाई से 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से चलाई जाएगी। इसके बाद 16 जुलाई से 31 जुलाई तक यह ट्रेन अपने पुराने रूट मदार-रेवाड़ी-मदार पर ही चलेगी।

रेलवे का कहना है कि इस नई व्यवस्था से झज्जर और रोहतक के बीच दक्षिण हरियाणा का रेल संपर्क मजबूत होगा।

राखीगढ़ी में बनेगा विश्वस्तरीय म्यूजियम, सिंधु-सरस्वती सभ्यता को मिलेगा वैश्विक मंच विस्तार

राखीगढ़ी म्यूजियम में डिजिटल पर्यटकों को मिलेगा तकनीक से सरस्वती-सिंधु सभ्यता का जीवंत और विस्तृत अनुभव

भारतेंदु संवाददाता ,चंडीगढ़

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राखीगढ़ी में विकसित किए जा रहे विश्वस्तरीय साइट म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना केवल एक संग्रहालय न रहकर भारत की प्राचीन सरस्वती-सिंधु सभ्यता, सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान परंपरा का वैश्विक केंद्र बनेगी।

मुख्यमंत्री गुरुवार रात चंडीगढ़ में इस परियोजना की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विरासत एवं पर्यटन विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने परियोजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राखीगढ़ी में विकसित किया जा रहा इंटरप्रिटेशन सेंटर आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा, जहां डिजिटल, ऑडियो-विजुअल और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि लगभग एक लाख वर्ग फुट क्षेत्र में बनने वाले इस म्यूजियम में पांच-पांच विषय आधारित गैलरियां ग्राउंड फ्लोर और प्रथम तल पर विकसित की जाएंगी। इन गैलरियों में सरस्वती-सिंधु सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें राखीगढ़ी के सात टीलों का परिचय, उत्खनन का इतिहास, प्राप्त अवशेष, नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, जल प्रबंधन, अन्न भंडारण, व्यापार, आजीविका और सामाजिक जीवन जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होंगी।

इसके साथ ही उस काल की तकनीकी और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी वैज्ञानिक तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे पर्यटक उस युग की जीवनशैली को करीब से समझ सकें। ओरिएंटेशन गैलरी में सप्त नदियों की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के विकास की जानकारी दी जाएगी। परियोजना में डिजिटल प्रोजेक्शन, 3-डी प्रस्तुतीकरण और लघु फिल्मों के माध्यम से इतिहास को रोचक और सहज तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पर्यटकों को प्राचीन सभ्यता की पूरी कहानी एक जीवंत अनुभव के रूप में देखने को मिलेगी। इंटरप्रिटेशन सेंटर में बच्चों और युवाओं के लिए विशेष अनुभवात्मक गतिविधियां भी होंगी। यहां वे प्राचीन काल की सील बनाने की प्रक्रिया, पुरावशेषों की प्रतिकृतियां, प्राचीन ईंटों और अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं को नजदीक से देख और समझ सकेंगे।

इसके अलावा उस समय के पारंपरिक खेलों और गतिविधियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि बच्चे इतिहास को मनोरंजक तरीके से सीख सकें। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में राखीगढ़ी के तीन टीलों पर उत्खनन कार्य जारी है।

पानीपत के खेत में करंट फैलने से मजदूर की मौत, दो मजदूर झुलसे

भारतेंदु संवाददाता, पानीपत । पानीपत जिले के गांव भोड़वाल माजरी में धान रोपाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। खेत के पानी में करंट फैल जाने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को उपचार के लिए समालखा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूर बिहार के सहरसा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मृतक की पहचान 36 वर्षीय मनोज कामत के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूरों की पहचान मुलायम और परमीत के रूप में हुई है। सभी मजदूर पिछले करीब 15-20 दिनों से धान की रोपाई के लिए पानीपत आए हुए थे और गांव के किसान सुशील के खेत में रहकर काम कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार गुरुवार को मजदूर ईश्वर के खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। इसी दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। बताया जा रहा है कि खेत के पास से गुजर रही 11 हजार केवीए की हाई टेंशन बिजली लाइन का इंसुलेटर खराब होने से अचानक तेज धमाका हुआ और चिंगारी निकली। इससे बिजली का करंट खंभे के जरिए खेत के पानी में फैल गया। करंट लगने से मनोज कामत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पास काम कर रहे मुलायम और परमीत भी गंभीर रूप से झुलस गए। खेत में मौजूद अन्य मजदूरों में अफरा-तफरी मच गई और कई लोग पानी में गिर गए। हालांकि कुछ देर बाद लाइन ट्रिप होने से बड़ा हादसा टल गया।

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बिजली आपूर्ति बंद करवाई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने बिजली विभाग से रिपोर्ट मांगी है और यह जांच की जा रही है कि हाई टेंशन लाइन की मरम्मत समय पर क्यों नहीं की गई थी। वहीं ग्रामीणों ने भी खेतों के आसपास लटकी बिजली तारों की हालत पर सवाल उठाए हैं और सुरक्षा उपायों की मांग की है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

न्यूज ब्रीफ

जींद में हाइड्रोजन ट्रेन का डीआरएम निरीक्षण

भारतेंन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। जींद में देश की पहली अत्याधुनिक हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में दिल्ली डिवीजन के डीआरएम पुष्पेश त्रिपाठी ने शुक्रवार को जींद जंक्शन का दौरा कर रेलवे स्टेशन, हाइड्रोजन प्लांट और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। डीआरएम ने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल अंतिम चरण में है और अगले कुछ दिनों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर्यावरण अनुकूल ट्रेन का उद्घाटन कर सकते हैं। रेलवे ने वीवीआईपी दौरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं।

फरीदाबाद वन विभाग टीम पर हमला, केस दर्ज

भारतेंन्दु संवाददाता, फरीदाबाद । फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र स्थित अरावली के संरक्षित वन क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि कार्रवाई के दौरान पिता-पुत्र ने वन दरोगा राजेश और सुरेंद्रपाल के साथ मारपीट की, सरकारी वर्दी फाड़ दी और जान से मारने की धमकी दी। टीम नियमित गश्त पर थी और निर्माण कार्य रोकने गई थी। पुलिस ने शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश जारी है।

नूंह में एचटेट परीक्षा की तैयारियां हुईं पूरी

भारतेंन्दु संवाददाता, नूंह । नूंह में 4 और 5 जुलाई को हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट)-2026 का आयोजन किया जाएगा। जिले में आठ परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर केंद्र पर सीसीटीवी, जैमर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। प्रश्न-पत्र ट्रेजरी से पुलिस सुरक्षा में केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे। स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल विभाग को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर क्षेत्र में धारा-163 लागू रहेगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

रेवाड़ी में पत्नी ने प्रेमी संग रची पति हत्या की साजिश, दो गिरफ्तार

भारतेंन्दु संवाददाता, रेवाड़ी । रेवाड़ी जिले के कसौला थाना क्षेत्र में 21 वर्षीय मोनू की मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि उसकी पत्नी ने प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। पुलिस ने पत्नी तनु और एक आरोपी हरिओम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपी फरार हैं। 9 जून की रात मोनू को बेहोश कर नहर में फेंका गया था। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

यमुनानगर में झाड़ियों से मिला व्यक्ति का शव

भारतेंन्दु संवाददाता, यमुनानगर। यमुनानगर जिले के छछरौली क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान गांव मलिकपुर खादर निवासी 48 वर्षीय महेंद्र के रूप में हुई है। वह सुबह घर से काम पर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। शाम को परिजनों को उसके झाड़ियों में पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों का खुलासा रिपोर्ट आने के बाद होगा। पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि महेंद्र आखिरी बार किसके साथ और किस स्थान पर देखा गया था। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं–दुर्घटना, हत्या या अन्य कारण–को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है, ताकि वास्तविक कारण सामने आ सके।

फर्जी ट्रांसपोर्ट बुकिंग से स्क्रैप धोखाधड़ी आरोपी गिरफ्तार

भारतेंन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। फर्जी ट्रांसपोर्ट बुकिंग एप के जरिए धोखाधड़ी कर 10 टन से अधिक आयरन स्क्रैप बेचने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान लुधियाना के सावन एन्क्लेव निवासी गुरूप्रताप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खाते में जमा 3 लाख 20 हजार रुपये को फ्रीज कर दिया है और उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

पुलिस के अनुसार आरोपी ने ट्रक बुकिंग एप पर फर्जी मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया और फरीदाबाद से लुधियाना के लिए ट्रांसपोर्ट सेवा देने का झांसा दिया। शिकायतकर्ता देवेंद्र सिंह ने इसी एप के माध्यम से माल भेजने के लिए संपर्क किया था। 12 जून 2026 को आरोपी ने फर्जी नंबर प्लेट वाला ट्रक भेजा और उसमें करीब 10 टन 120 किलोग्राम आयरन स्क्रैप लोड कराया गया।

फतेहाबाद में ट्रांसफॉर्मर हादसे में एएलएम घायल, दो बिजलीकर्मियों पर एफआईआर

भारतेंन्दु संवाददाता , फतेहाबाद

फतेहाबाद जिले के बिजली निगम में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें एक एएलएम कर्मचारी को अपनी जान बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ कुहनी तक गंवाना पड़ा। करीब दो महीने पुराने इस हादसे में पुलिस ने अब विभाग के ही दो कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार यह घटना 11 मई को गांव आकांवाली में हुई थी। शिकायत के मुताबिक, बिजली ट्रांसफॉर्मर का जंपर टूटने की सूचना पर एएलएम हरपाल सिंह और एचकेआरएन के तहत कार्यरत पंकज कुमार मौके पर पहुंचे थे। पंकज वर्षों से कंप्लेंट सेंटर में तैनात था।

आरोप है कि जंपर ठीक करने से पहले हरपाल सिंह ने कंट्रोल रूम में फोन कर लाइन बंद करने को

कहा था। उस समय ड्यूटी पर मौजूद एसए अनिल कुमार ने उन्हें बताया कि लाइन काट दी गई है। इसी भरोसे पर पंकज को ट्रांसफॉर्मर पर चढ़ा दिया गया।

जैसे ही पंकज ट्रांसफॉर्मर पर काम करने के लिए ऊपर चढ़ा, वह हाई-वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया। करंट लगते ही जोरदार धमाका हुआ और वह गंभीर रूप से झुलसकर नीचे गिर पड़ा। उसके दाहिने हाथ, बाएं हाथ, सिर और कान पर गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत हिसार के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए उसका दाहिना हाथ कुहनी तक काट दिया। पीड़ित के बयान और बिजली निगम की जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एएलएम हरपाल सिंह और एसए अनिल कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

फरीदाबाद में रिश्वतखोरी के आरोपों पर मेयर ने दिए जांच के आदेश

भारतेंन्दु संवाददाता , फरीदाबाद

फरीदाबाद में प्रॉपर्टी आईडी सुधार के नाम पर कथित रिश्वतखोरी और अनियमितताओं के आरोपों के बाद नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। मेयर प्रवीण बत्रा जोशी ने एनआईटी जोन के जेडटीओ के खिलाफ जांच कराने के लिए नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखा है। उन्होंने इस मामले की जांच के लिए 10 दिन का समय निर्धारित किया है।

मेयर के अनुसार, उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि प्रॉपर्टी आईडी में सुधार कराने के नाम पर लोगों से रिश्वत की मांग की जा रही है। कई नागरिकों ने इस संबंध में लिखित शिकायतें भी मेयर और नगर निगम आयुक्त को सौंपी हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मेयर ने स्वतंत्र जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं, जो 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

गाजीपुर निवासी सुशील ने भी सीएम और नगर निगम कमिश्नर को शिकायत भेजकर आरोप लगाया कि जेटीओ-3 अशोक ठाकुर और उनके स्टाफ द्वारा लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और गलत तरीके से पैसे वसूले जाते हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि उनकी प्रॉपर्टी आईडी को गलत तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के नाम करने की कोशिश की गई। जब वह जानकारी लेने निगम कार्यालय पहुंचे तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। गौरतलब है कि चार वर्ष पूर्व सरकार ने शहर में प्रॉपर्टी आईडी तैयार करने के लिए याशी एजेंसी से सर्वे कराया था।

कलेसर में तेंदुए की मौत, पोस्टमार्टम में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के मिले लक्षण

भारतेंन्दु संवाददाता , यमुनानगर

यमुनानगर जिले के कलेसर वन क्षेत्र में एक नर तेंदुए की मौत से वन्य जीव विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तेंदुए में एक खतरनाक वायरस के गंभीर लक्षण पाए गए हैं, हालांकि संक्रमण की अंतिम पुष्टि के लिए नमूने हिसार स्थित प्रयोगशाला भेजे गए हैं।

जानकारी के अनुसार शाहजादवाला गांव के ग्रामीणों ने जंगल के किनारे एक बीमार तेंदुए को तड़पते हुए देखा था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलने पर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी मौत हो गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय चिकित्सकीय दल ने तेंदुए का पोस्टमार्टम किया। जांच के दौरान उसके लीवर और हृदय पर गंभीर असर, आंतों में रक्तस्राव तथा श्वसन तंत्र में संक्रमण जैसे लक्षण पाए गए। चिकित्सकों ने इन संकेतों को एक गंभीर संक्रामक रोग से मिलते-जुलते बताया है।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह रोग कुत्तों और कुछ जंगली जानवरों में तेजी से फैलने वाला संक्रमण है, जो तेंदुए जैसे मांसाहारी वन्य जीवों के लिए घातक साबित हो सकता है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि प्रयोगशाला रिपोर्ट आने के बाद ही होगी।

पशुपालन विभाग के चिकित्सक सतीश धनिया ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तेंदुए के अवशेषों का सुरक्षित निस्तारण हाथी पुनर्वास केंद्र परिसर में किया गया। मृत तेंदुआ नर था और उसकी अनुमानित आयु लगभग आठ से दस माह के बीच बताई गई है।

वन विभाग ने पूरे कलेसर वन क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में अन्य वन्य जीवों की सेहत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि किसी भी संभावित संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इस रोग की पुष्टि होती है, तो यह वन्य जीव संरक्षण के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा। विभाग ने आसपास के गांवों में भी सतर्कता बरतने और आवारा कुत्तों की निगरानी करने की सलाह दी है। वन विभाग ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी और निगरानी जारी है।

फतेहाबाद में शराब ठेके पर फायरिंग और लूट, सेल्समैन की काटी कलाई

भारतेंन्दु संवाददाता , फतेहाबाद

फतेहाबाद जिले के रतिया क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक शराब ठेके पर हथियारबंद बदमाशों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। तीन बदमाशों ने न सिर्फ ठेके पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, बल्कि सेल्समैन पर गंडासे से हमला कर उसकी कलाई काट दी और गल्ले से नकदी लूटकर फरार हो गए।

जानकारी के अनुसार, गांव कुला निवासी मुकेश अपने भाई रणजीत सिंह से मिलने घासवा गांव के शराब ठेके पर पहुंचा था। दोनों भाई आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी मुंह ढके तीन हथियारबंद बदमाश वहां पहुंचे। उनके पास देसी पिस्तौल, गंडासा और तलवार थी। बदमाशों ने आते ही गालियां देते हुए ठेके का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गए। आरोपियों ने दहशत फैलाने के लिए पिस्तौल से दो राउंड फायर किए। इसके बाद गंडासे से सेल्समैन रणजीत सिंह पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ की कलाई गंभीर रूप से कटकर अलग हो गई। हमले में रणजीत खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। उसे बचाने आए उसके भाई मुकेश को भी आरोपियों ने बुरी तरह पीटा।

इसके बाद बदमाशों ने ठेके के गल्ले से करीब 30 से 40 हजार रुपये की नकदी लूटी और मौके से फरार हो गए। गोलियों और चीख-पुकार की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को तुरंत रतिया नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया।

डॉक्टरों ने रणजीत की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उसका इलाज जारी है और हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर रतिया सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

यमुनानगर में बाइक सवार से 272 ग्राम हेरोइन बरामद

भारतेंन्दु संवाददाता , यमुनानगर। यमुनानगर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। अपराध शाखा-1 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक बाइक सवार युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 272 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग दस लाख रुपये आंकी गई है।

पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि पश्चिमी यमुना पुल के कांजनू क्षेत्र से एक युवक भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर गुजरने वाला है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर नाकाबंदी की और संदिग्ध वाहनों की जांच शुरू कर दी। इसी दौरान एक बाइक सवार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके पास से 272 ग्राम हेरोइन बरामद हुई ।गिरफ्तार आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी अक्षय के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी का पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

पलवल में जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का उपायुक्त ने किया निरीक्षण

उपायुक्त ने जलभराव प्रभावित कॉलोनियों का निरीक्षण कर सफाई व निकासी व्यवस्था सुधार के दिए सख्त निर्देश

भारतेंन्दु संवाददाता, पलवल

पलवल शहर में मानसून के दौरान उत्पन्न जलभराव की गंभीर समस्या को देखते हुए उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने शुक्रवार को विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए।

उपायुक्त ने किठवाड़ी रोड, सल्लागढ़ स्कूल के आसपास का क्षेत्र, सुखराम अस्पताल वाली गली स्थित न्यू एक्सटेंशन कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी तथा आर्य नगर सहित कई जलभराव प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। लोगों ने बताया कि बारिश के बाद कई जगहों पर पानी लंबे समय तक जमा रहता है, जिससे दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

निरीक्षण के दौरान डॉ. छिल्लर ने पाया कि कई स्थानों पर नालियों में गंदगी और अवरोध जमा होने के कारण पानी की निकासी बाधित हो रही है। इसके चलते सड़कों और गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बन रही है और इसे किसी भी हाल में तुरंत ठीक किया जाना चाहिए।

उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नालियों और जल निकासी मार्गों की तत्काल सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि नालों की नियमित सफाई न होने के कारण ही जलभराव की समस्या उत्पन्न होती है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जहां-जहां पानी जमा है, वहां से पानी को शीघ्रता से निकालने के लिए अतिरिक्त संसाधनों और कर्मचारियों की तैनाती की जाए।

उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। नगर परिषद, सिंचाई विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को मिलकर एक ठोस कार्य योजना के तहत कार्य करना चाहिए ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

डॉ. छिल्लर ने स्पष्ट किया कि संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल निकासी व्यवस्था को हर हाल में सुचारू रखा जाए और सफाई कार्यों में तेजी लाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिकों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए जलभराव से जुड़ी शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने उपायुक्त के निरीक्षण और त्वरित निर्देशों का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही क्षेत्र में जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। लोगों का कहना है कि यदि नियमित रूप से नालों की सफाई और निगरानी की जाए तो हर साल होने वाली इस समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है।

प्रशासन की इस सक्रियता से लोगों में उम्मीद जगी है कि मानसून के दौरान उत्पन्न जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा और शहर में स्वच्छ व सुचारू जल निकासी व्यवस्था स्थापित की जाएगी।

फरीदाबाद लेबर चौक पर टोकन सिस्टम शुरू मजदूरों को मिलेगा सुरक्षित रोजगार

भारतेंन्दु संवाददाता , फरीदाबाद

फरीदाबाद के सेक्टर-14 स्थित लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूरों के लिए नई टोकन प्रणाली शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य मजदूरों को पारदर्शी तरीके से काम उपलब्ध कराना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस व्यवस्था का शुभारंभ शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने किया। यह पहल एक एनजीओ के सहयोग से संचालित की जा रही है।

मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि अब लेबर चौक पर आने वाले सभी मजदूरों का पहले पंजीकरण किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें टोकन दिए जाएंगे। इन्हीं टोकनों के आधार पर मजदूरों को काम आवंटित किया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता या शोषण की संभावना समाप्त हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से मजदूरों को रोज़गार पाने में आसानी होगी और वे बिना काम के नहीं रहेंगे।

इस नई प्रणाली के तहत मजदूरों को दुर्घटना और बीमारी की स्थिति में बीमा (इंश्योरेंस) सुविधा भी

प्रदान की जाएगी, ताकि आपात स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अलावा चौक पर मजदूरों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, पीने के लिए ठंडा पानी और चाय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।

मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार मजदूरों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि मजदूरों की मजदूरी में 35 प्रतिशत की बढ़ोतरी से हजारों श्रमिकों को लाभ मिला है। बरसात के मौसम की तैयारियों को लेकर मंत्री ने कहा कि फरीदाबाद और गुरुग्राम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके साथ ही प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि लेबर चौक पर आने वाले प्रत्येक मजदूर का डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सके। अधिकारियों के अनुसार इस प्रणाली से मजदूरों की पहचान आसान होगी और ठेकेदारों द्वारा मनमानी करने पर रोक लगेगी। स्थानीय लोगों और मजदूर संगठनों ने भी इस पहल का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक कदम बताया है।

दिल्ली में बनेगा सीबीआरएन कमांड सेंटर, परमाणु हमले में भी करेगा काम

राजधानी की सुरक्षा को नई मजबूती, एआई और सीबीआरएन तकनीक से लैस होगा नया मुख्यालय

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक अत्याधुनिक कमांड सेंटर स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र राजधानी के कनॉट प्लेस स्थित मौजूदा दिल्ली फायर सर्विस मुख्यालय के स्थान पर बनने वाले नए आधुनिक मुख्यालय के भूमिगत हिस्से में बनाया जाएगा। इसे भारत का पहला रेडियेशन-शील्डेड सीबीआरएन कमांड सेंटर माना जा रहा है, जो परमाणु हमले, रेडियोलॉजिकल रिसाव या अन्य गंभीर आपदाओं के दौरान भी पूरी क्षमता के साथ कार्य करता रहेगा। यह परियोजना देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था को नई मजबूती देने वाली महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

दिल्ली फायर सर्विस के अनुसार, यह कमांड सेंटर सामान्य नियंत्रण कक्ष से पूरी तरह अलग होगा। इसे विशेष तकनीक और आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप भूमिगत बनाया जाएगा, ताकि बाहरी परमाणु विकिरण, जहरीली गैसों या अन्य खतरनाक रासायनिक तत्वों का प्रभाव इसके भीतर न पहुंच सके।

पांच साल में होगा तैयार

इस अत्याधुनिक कमांड सेंटर को दिल्ली के विभिन्न आपदा प्रबंधन केंद्रों और खोज एवं बचाव इकाइयों से सीधे जोड़ा जाएगा। नेहरू प्लेस, लक्ष्मी नगर और रोहिणी स्थित आपदा केंद्रों के साथ-साथ दिल्ली फायर सर्विस की सर्च एंड रेस्क्यू बटालियन को यहीं से निर्देश जारी किए जाएंगे। एकीकृत नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा, जिससे किसी भी बड़े हादसे के समय त्वरित कार्रवाई संभव हो सकेगी। यह व्यवस्था आपदा के दौरान समय पर निर्णय लेने और संसाधनों के प्रभावी उपयोग में सहायक सिद्ध होगी। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित केंद्रीकृत कंट्रोल रूम भी है, जिसे अगले एक वर्ष के भीतर विकसित करने की योजना है। यह प्रणाली ट्रैफिक की स्थिति, मौसम के पूर्वानुमान, आपातकालीन कॉल के पैटर्न और अन्य उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर संभावित आगजनी या अन्य घटनाओं का पहले से आकलन करने में सक्षम होगी।

प्रो. योगेश सिंह दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कुलपति प्रो. योगेश सिंह पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए उन्हें दूसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए कुलपति के तौर पर फिर से नियुक्त किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह की पुनर्नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विश्वविद्यालय की विजिटर के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रो. सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति दूसरी बार नियुक्त किया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रो. योगेश सिंह का दूसरा कार्यकाल आठ अक्टूबर से प्रभावी होगा। उनका नया कार्यकाल पांच वर्षों का होगा।

शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कुलपति के रूप में प्रो. योगेश सिंह की सेवा की शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम, विधियों और अध्यादेशों के अनुसार होंगी।

दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट की अव्यवस्था पर हाई कोर्ट नाराज, मांगी विस्तृत रिपोर्ट

कैंसर इंस्टिट्यूट की बदहाली पर हाई कोर्ट सख्त, दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली

दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और डिजिटल हेल्थकेयर सिस्टम की वास्तविकता को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली सरकार को ई-हॉस्पिटल सिस्टम का लाइव डेमो प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि केवल सरकारी दावे पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनकी प्रभावशीलता और जमीनी हकीकत भी सामने आनी चाहिए।

यह मामला उस समय गंभीर हो गया, जब दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टिट्यूट (डीएससीआई) में चिकित्सा सुविधाओं की बदहाली, आधुनिक मशीनों के लंबे समय से बंद पड़े रहने और मरीजों को जांच व उपचार के लिए महीनों तक इंतजार करने जैसी गंभीर कमियां उजागर हुईं। हाई कोर्ट ने इन परिस्थितियों को चिंताजनक मानते हुए दिल्ली सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और यह सुनिश्चित करने को कहा है कि डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ वास्तव में मरीजों तक पहुंच रहा है या नहीं।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में नेक्स्टजेन हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एचएमआईएस) और 'दिल्ली आईसीयू बेड सारथी' एप का लाइव प्रदर्शन अदालत के समक्ष किया जाए।

अदालत यह देखना चाहती है कि जिन डिजिटल प्रणालियों के माध्यम से मरीजों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा किया जा रहा है, वे वास्तव में कितनी प्रभावी हैं। इसके साथ ही राजधानी के 38 सरकारी अस्पतालों के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि यदि इन प्रणालियों को लागू करने में किसी प्रकार की तकनीकी, प्रशासनिक या संसाधन संबंधी समस्या आ रही है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए।

बिजली कंपनियों के खातों की खुलेगी परतें, सीएजी करेगा व्यापक ऑडिट

38 हजार करोड़ के रेगुलेटरी एसेट्स की होगी जांच, दिल्ली सरकार ने दिए ऑडिट के निर्देश

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में बिजली वितरण करने वाली निजी कंपनियों के खातों का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से ऑडिट कराने का औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने सीएजी को यह जांच तीन महीने के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। साथ ही बिजली वितरण कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि ऑडिट की प्रक्रिया पूरी होने तक वे उपभोक्ताओं से बकाया रेगुलेटरी एसेट्स की वसूली न करें। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों का सीएजी ऑडिट बिजली क्षेत्र में वित्तीय पारदर्शिता स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उनके अनुसार, निजीकरण के बाद कई वर्षों तक बिजली कंपनियों के वित्तीय लेन-देन, बढ़ती देनदारियों और रेगुलेटरी एसेट्स की समुचित जांच नहीं हो सकी। उन्होंने दावा किया कि अब दिल्ली की जनता को यह जानने का अधिकार है कि कुछ सौ करोड़ रुपये का रेगुलेटरी एसेट्स बढ़कर लगभग 38 हजार करोड़ रुपये तक कैसे पहुंच गया, इसका लाभ किसे मिला और आखिर इसका बोझ उपभोक्ताओं पर क्यों पड़ा।

ध्रुव राठी के वीडियो पर हाई कोर्ट का आदेश, शिकायत अपीलीय समिति 15 दिन में दे निर्णय

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के शिकायत अपीलीय कमेटी को निर्देश दिया है कि भगवान राम और सीता का कथित रुप से अपमान करने वाले यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो को हटाने की मांग पर 15 दिनों में फैसला करे। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने ये आदेश दिया।

वकील अमित सचदेवा ने याचिका दायर करके 21 मार्च के ध्रुव राठी के उस वीडियो को हटाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि ध्रुव राठी का ये वीडियो हिन्दू देवी-देवताओं का अपमान करने वाला है। ये वीडियो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। चेतन शर्मा ने कहा कि या तो गूगल उस वीडियो को हटा दे या इसे लेकर कोई न्यायिक आदेश पारित हो, जिसके आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाए।

उसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार के शिकायत अपीलीय कमेटी को निर्देश दिया है कि वो 15 दिनों के अंदर इस अपील पर फैसला करें। कोर्ट ने कहा कि उसके आदेश का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

दिल्ली में मानसून की देर से दस्तक 2021 के बाद पहली बार जुलाई में पहुंचा

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली। दिल्ली में इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून ने सामान्य तिथि से पांच दिन की देरी से दस्तक दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजधानी में मानसून का आगमन 2 जुलाई को हुआ, जबकि इसकी सामान्य तिथि 27 जून मानी जाती है। वर्ष 2021 के बाद यह पहली बार है जब मानसून जुलाई महीने में दिल्ली पहुंचा है। इससे पहले वर्ष 2021 में मानसून ने 13 जुलाई को राजधानी में प्रवेश किया था। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2025 में मानसून 29 जून, 2024 में 28 जून, 2023 में 25 जून और 2022 में 30 जून को दिल्ली पहुंचा था। इस बार इसकी देरी का प्रमुख कारण अल नीनो के प्रभाव को माना जा रहा है, जिसने मानसूनी हवाओं की गति को प्रभावित किया।

मौसम विभाग ने 3 से 8 जुलाई तक दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए वर्षा का यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में बादल छाए रहने, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने तथा कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही आंधी, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कुछ समय के लिए हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। विभाग का कहना है कि सुबह और शाम के समय मौसम का प्रभाव अधिक देखने को मिल सकता है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 30 से 37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

पिछले 26 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मानसून 13 बार जुलाई में पहुंचा है, जबकि केवल 11 बार जून में समय पर या उससे पहले दस्तक दे सका। वर्ष 2013, 2020 और 2023 ऐसे वर्ष रहे, जब मानसून सामान्य तिथि से पहले राजधानी पहुंच गया था। इस बार मानसून की देरी के बावजूद इसके आगमन ने लोगों को भीषण गर्मी और तेज धूप से काफी राहत दी है। बृहस्पतिवार सुबह राजधानी के कई इलाकों में हल्की वर्षा और तेज धूलभरी हवाओं के बाद मौसम सुहावना हो गया। हालांकि वर्षा अधिक नहीं होने के कारण वातावरण में उमस बनी रही, फिर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों ने गर्मी से राहत महसूस की।

दिल्ली पर्यटन विभाग का मैंगो फेस्टिवल शुरू

किसानों ने सजाई दुर्लभ आमों की प्रदर्शनी

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में आम प्रेमियों के लिए बहुप्रतीक्षित 35वां मैंगो फेस्टिवल शुक्रवार से शुरू हो गया है। दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित यह तीन दिवसीय उत्सव 3 से 5 जुलाई तक जनकपुरी स्थित दिल्ली हाट में आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में देशभर के विभिन्न राज्यों से आए किसान, बागवान और सरकारी संस्थान आम की 400 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां आने वाले लोग न केवल विभिन्न प्रकार के आमों को देख और खरीद सकते हैं, बल्कि कई दुर्लभ और कम प्रसिद्ध किस्मों का स्वाद भी चख सकते हैं।

फेस्टिवल में लंगड़ा, दशहरी, चौसा, तोतापुरी और आम्रपाली जैसी लोकप्रिय किस्मों के अलावा रटौल, हुस्नारा, रामकेला, केसर, मल्लिका, फजरी और गुलाब जामुन जैसे विशेष आम भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां अंगूर जितने छोटे और पपीते जितने बड़े आकार के आम भी प्रदर्शित किए गए हैं, जो लोगों की उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों से आए उत्पादक आम के साथ-साथ आम से बने अचार, जैम, जूस, पल्प और अन्य उत्पाद भी बिक्री के लिए लेकर पहुंचे हैं।

फेस्टिवल को केवल खरीदारी तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इसे मनोरंजन और पारिवारिक उत्सव का रूप भी दिया गया है। यहां आम खाने की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें सबसे कम समय में आम खाने वाला प्रतिभागी विजेता बनेगा। इसके अलावा आम पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता भी रखी गई है, जिससे लोगों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।

दिल्ली में आतंकी साजिश नाकाम आईएसआई मॉड्यूल के चार संदिग्ध गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में संभावित आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ करते हुए चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक आतंकी मॉड्यूल के संपर्क में थे और दिल्ली-एनसीआर में बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के तार कथित हैंडलर शहजाद भट्टी से जुड़े थे। पुलिस ने इनके कब्जे से दो पिस्तौल, जिनमें एक तुर्किये निर्मित जिगाना पिस्टल भी शामिल है, नौ कारतूस तथा पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हैं।

स्पेशल सेल के अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पंजाब के तरनतारन निवासी शुभदीप सिंह उर्फ विशाल, गुरजंट सिंह उर्फ ऋषि, अमृतसर निवासी साजन सिंह उर्फ हनी तथा फतेहगढ़ साहिब निवासी गगनप्रीत के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि काफी समय से इस मॉड्यूल की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। खुफिया सूचनाओं से संकेत मिले थे कि पाकिस्तान स्थित हैंडलर सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही पंजाब सीमा पर ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ भारत भेजे जाने की जानकारी भी लगातार मिल रही थी। इन सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने का अभियान तेज किया।

जांच के दौरान सबसे पहले शुभदीप सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में उसने कथित रूप से स्वीकार किया कि वह पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में था और ड्रोन के माध्यम से भेजे गए हथियार प्राप्त करने का काम करता था। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने उसके भाई गुरजंट सिंह और साजन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से भी हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए गए। तीनों से मिली जानकारी के बाद पुलिस दिल्ली पहुंची और गगनप्रीत को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार गगनप्रीत के मोबाइल फोन की जांच में कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। इनमें दिल्ली के कई धार्मिक स्थलों, पुलिस थानों, सरकारी भवनों तथा अन्य संवेदनशील स्थानों के वीडियो शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि वह इन स्थानों की रेकी कर वीडियो अपने कथित आकाओं तक पहुंचाता था।

प्रदूषण पर बड़ा प्रहार! 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना को सितंबर से मिलेगी रफ्तार

दिल्ली सरकार की 8,300 करोड़ रुपए की बड़ी पहल, सात साल चलेगा स्वच्छ हवा अभियान

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली

दिल्ली सरकार विश्व बैंक के सहयोग से 'स्वच्छ हवा, स्वस्थ दिल्ली' परियोजना सितंबर से शुरू करने जा रही है। यह पर्यावरण विभाग की सात वर्षीय परियोजना है, जिसे विश्व बैंक सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि परियोजना को तैयारियों को अंतिम रूप देने और सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 10 जुलाई को एक विशेष कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिकाएं तय की जाएंगी और कार्यक्रम के प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन की रूपरेखा पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि यह परियोजना सितंबर 2026 से अगस्त 2033 तक दिल्ली के सभी जिलों में लागू की जाएगी। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,300 करोड़ रुपये है, जिसमें 65 प्रतिशत वित्तीय सहायता विश्व बैंक उपलब्ध कराएगा, जबकि 35 प्रतिशत राशि दिल्ली सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत परिवहन, सड़क की धूल, निर्माण एवं ध्वस्तीकरण (सीएंडडी) अपशिष्ट, ठोस कचरा प्रबंधन, उद्योग, हरित क्षेत्र और जल प्रदूषण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दो प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है। पहला स्तंभ दिल्ली में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। इसके तहत परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए एक समर्पित प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बनाई जाएगी। आधुनिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, डेटा एनालिटिक्स और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी।

दूसरा स्तंभ प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है। इसके तहत पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाया जाएगा तथा वाहनों से होने वाले प्रदूषण की निगरानी के लिए अत्याधुनिक प्रदूषण जांच (पीयूसी) प्रणाली विकसित की जाएगी।

दिल्ली में शादी के सात महीने बाद पत्नी ने दुपट्टे से की पति की हत्या

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले के जगतपुरी इलाके में पति-पत्नी के बीच हुए विवाद ने एक दर्दनाक और सनसनीखेज मोड़ ले लिया। विवाह के महज सात महीने बाद एक 20 वर्षीय महिला ने अपने पति की कथित रूप से दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। प्रारंभिक पुलिस जांच के अनुसार, घटना की वजह पति का अपनी पत्नी पर विवाहेतर संबंध होने का शक था। बताया गया कि मृतक अपनी पत्नी का मोबाइल फोन चेक कर रहा था और उसमें कथित संबंधों से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच देर रात तीखी बहस शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठी। इस घटना ने एक बार फिर वैवाहिक रिश्तों में अविश्वास, संवादहीनता और गुस्से के गंभीर परिणामों को सामने ला दिया है।

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान मुस्तकीम उर्फ साहिल (19) के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पत्नी का नाम अलीशा (20) है। शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने बताया कि 2 जुलाई की तड़के लगभग 3:52 बजे जगतपुरी थाने में पीसीआर कॉल के माध्यम से सूचना मिली कि राशिद मार्केट क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति का गला घोंट दिया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को अचेत अवस्था में पाया। उसे तत्काल डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परेशानी | दिल्ली की सड़कों पर नया साइबर खतरा, ऐप के जरिए बंद किए जा रहे ई-रिक्शा

दिल्ली में ई-रिक्शा पर डिजिटल हमला! चलते-चलते बंद हो रहे वाहन

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली

दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा चालकों के सामने एक नई और गंभीर समस्या उभरकर सामने आई है, जिसने न केवल उनकी रोजी-रोटी बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के कई इलाकों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें चलते-चलते ई-रिक्शा अचानक बंद हो जाते हैं। शुरुआत में इसे तकनीकी खराबी माना गया, लेकिन बाद में सामने आया कि कुछ शरारती और मनचले लोग एक मोबाइल एप का दुरुपयोग कर जानबूझकर ई-रिक्शा को बीच रास्ते में बंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग इसे मजाक या प्रैंक बताकर ई-रिक्शा रोकते दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसका असर बेहद गंभीर हो सकता है। व्यस्त सड़क पर अचानक वाहन बंद होने से पीछे आ रहे वाहनों से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है, जिससे चालक, यात्री और अन्य राहगीरों की जान जोखिम में पड़ सकती है। इस तरह की घटनाओं ने डिजिटल तकनीक के दुरुपयोग और साइबर सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है।

जानकारी के अनुसार, यह समस्या मुख्य रूप से उन ई-रिक्शा में सामने आ रही है जिनमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली लिथियम-आयन बैटरियां लगी हैं। इन बैटरियों के संचालन और निगरानी के लिए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) एप का उपयोग किया जाता है। यह एप मूल रूप से निर्माता कंपनियों और तकनीशियनों के लिए तैयार किया गया था, ताकि बैटरी की चार्जिंग, वोल्टेज, तापमान और अन्य तकनीकी जानकारियों की निगरानी की जा सके। इसी एप में बैटरी को ऑन, ऑफ और रीस्टार्ट करने जैसी सुविधाएं भी मौजूद होती हैं। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को इस एप की जानकारी मिल गई है और वे इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

यदि ई-रिक्शा की बैटरी का ब्लूटूथ सुरक्षित नहीं है या उसका डिफॉल्ट पासवर्ड नहीं बदला गया है, तो आसपास मौजूद कोई भी व्यक्ति सीमित दूरी के भीतर इस एप के माध्यम से वाहन को नियंत्रित कर सकता है। यह स्थिति तकनीकी लापरवाही के साथ-साथ साइबर सुरक्षा की बड़ी चुनौती को भी उजागर करती है।

दिल्ली के जहांगीरपुरी, संगम विहार, बदरपुर बॉर्डर, पहाड़गंज और नई दिल्ली जैसे व्यस्त इलाकों में ऐसी घटनाएं सामने आने के बाद ई-रिक्शा चालकों में चिंता बढ़ गई है। कई चालकों का कहना है कि पूरी तरह चार्ज बैटरी होने के बावजूद वाहन अचानक बंद हो गया, जिससे उन्हें यात्रियों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी और आर्थिक नुकसान भी हुआ।

कई बार बीच सड़क पर वाहन बंद होने से लंबा जाम लग गया और यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल मजाक नहीं बल्कि गंभीर साइबर शरारत है, जिसके कारण कभी भी बड़ा सड़क हादसा हो सकता है। यदि किसी व्यस्त चौराहे या तेज रफ्तार वाले मार्ग पर अचानक ई-रिक्शा बंद हो जाए तो पीछे से आने वाले वाहन चालक समय रहते ब्रेक नहीं लगा पाएंगे, जिससे दुर्घटना की आशंका कई गुना बढ़ जाती है।

दिल्ली एयरपोर्ट पर नकदी के साथ विदेशी यात्रियों की धरपकड़, उड़ान से पहले रोके गए

भारतेंदु संवाददाता,नई दिल्ली। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने सतर्कता दिखाते हुए तीन चीनी नागरिकों को 18.95 लाख रुपये की अघोषित भारतीय मुद्रा के साथ हिरासत में लिया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब तीनों यात्री शंघाई जाने वाली उड़ान में सवार होने की तैयारी कर रहे थे।

प्रारंभिक जांच के दौरान सीआईएसएफ के जवानों को एक यात्री के सामान की तलाशी में छह लाख रुपये नकद मिले। जब उससे इस धनराशि के संबंध में आवश्यक दस्तावेज और संतोषजनक जानकारी मांगी गई तो वह कोई वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मामला तुरंत सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया।

सीमा शुल्क अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाते हुए उस यात्री के साथ मौजूद दो अन्य चीनी नागरिकों की भी तलाशी ली। जांच में उनके पास से भी बड़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा बरामद हुई। तीनों के पास से कुल 18.95 लाख रुपये नकद मिले, लेकिन वे इस धनराशि के स्रोत, उद्देश्य अथवा इसे देश से बाहर ले जाने के लिए आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके चलते अधिकारियों ने उन्हें उड़ान में सवार होने से रोक दिया और विस्तृत पूछताछ शुरू कर दी।

शंघाई जा रहे थे तीन चीनी नागरिक

अधिकारियों के अनुसार, भारत से बड़ी मात्रा में नकद धनराशि ले जाने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यदि कोई यात्री तय सीमा से अधिक नकदी लेकर यात्रा करता है या उसके पास आवश्यक घोषणा और दस्तावेज नहीं होते, तो संबंधित एजेंसियां कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। इसी कारण इस मामले में भी सीमा शुल्क विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि बरामद नकदी का वास्तविक स्रोत क्या है, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाना था और कहीं यह धन किसी अवैध गतिविधि से तो संबंधित नहीं है। दिल्ली हवाई अड्डा देश के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में शामिल है, जहां सुरक्षा एजेंसियां यात्रियों और उनके सामान की लगातार निगरानी करती हैं। सीआईएसएफ और सीमा शुल्क विभाग समय-समय पर तस्करी, अवैध विदेशी मुद्रा, सोना, मादक पदार्थ तथा अघोषित नकदी की बरामदगी जैसी कार्रवाइयों को अंजाम देते रहे हैं।

जीएमआर की सीएसआर पहल से लद्दाख के युवाओं को मिलेगा उद्योग आधारित प्रशिक्षण

कंप्यूटर से बैंकिंग तक कई क्षेत्रों में मिलेगा व्यावहारिक प्रशिक्षण

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

लद्दाख के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर सामने आया है, जिसके तहत उन्हें रोजगार से जुड़ी आधुनिक और उद्योग-आधारित स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। इस पहल की शुरुआत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शुक्रवार को की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यावहारिक और तकनीकी कौशल से जोड़ना है, जिससे उन्हें संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और वे आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत लद्दाख के सभी सात जिलों—लेह, कारगिल, द्रास, जांस्कर, शाम, नुब्रा और चांगथांग—से चयनित 36 युवाओं को पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए नई दिल्ली भेजा गया है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से रोजगार आधारित कौशल विकास पर केंद्रित है, जिसमें

रोजगार से जुड़े स्किल डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत, एलजी वी.के. सक्सेना ने दिखाई हरी झंडी

युवाओं को विभिन्न आधुनिक क्षेत्रों में दक्ष बनाया जाएगा। चयनित युवाओं में 34 लड़कियां और 2 लड़के शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि इस योजना में महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। अधिकांश प्रतिभागी पहली बार लद्दाख से बाहर जाकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो उनके लिए एक नया अनुभव होने के साथ-साथ उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

इन युवाओं को दिल्ली स्थित जीएमआर वरलक्ष्मी सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड्स में 2 से 3 महीने का गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें कंप्यूटर शिक्षा, डेटा विजुअलाइजेशन, लॉजिस्टिक्स, ग्राहक सेवा, बैंकिंग, ब्यूटी एंड स्पा, फूड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट जैसे कई क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना है ताकि वे प्रशिक्षण के बाद सीधे रोजगार प्राप्त कर सकें।

इस पूरी योजना की खास बात यह है कि प्रशिक्षण का पूरा खर्च जीएमआर समूह अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहल के तहत वहन कर रहा है, जबकि लद्दाख प्रशासन ने युवाओं की यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी संभाली है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से नौकरी दिलाने में भी सहायता प्रदान की जाएगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षण केवल कौशल सीखने तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा लाभ रोजगार के रूप में युवाओं को मिले।

अमरनाथ यात्रा के लिए एयरटेल का बड़ा कदम, नेटवर्क कवरेज का किया विस्तार

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। भारती एयरटेल ने अमरनाथ यात्रा 2026 के दौरान अपनी मोबाइल नेटवर्क सेवाओं का बड़ा विस्तार करते हुए तीर्थयात्रियों, सुरक्षाकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की घोषणा की है। कंपनी ने बताया कि इस बार यात्रा मार्गों पर विशेष तकनीकी व्यवस्था की गई है, जिससे दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में भी निर्बाध वॉयस और डेटा सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। एयरटेल ने पहलगाम मार्ग पर चंदनवारी, पिस्सू टॉप और बेताब घाटी जैसे प्रमुख स्थानों पर नई नेटवर्क साइटें स्थापित की हैं। इसके साथ ही बालटाल मार्ग पर पहले से मौजूद नेटवर्क को और मजबूत किया गया है। इस विस्तार के बाद अब दोनों प्रमुख यात्रा मार्गों—पहलगाम और बालटाल—पर बेहतर मोबाइल कवरेज उपलब्ध हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा मंदिर तक की यात्रा के दौरान संचार संबंधी किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कंपनी ने यह तैनाती स्थानीय प्रशासन और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय में की है, ताकि यात्रा के दौरान सुरक्षा, निगरानी और आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए। अधिकारियों के अनुसार, इस नेटवर्क विस्तार से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि सुरक्षा बलों और राहत कार्यों में लगे कर्मचारियों के बीच भी तेज और प्रभावी संचार सुनिश्चित होगा। एयरटेल के जम्मू और कश्मीर सर्किल के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) विक्रम आरएस ने कहा कि कंपनी कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी लोगों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि अमरनाथ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान नेटवर्क विस्तार का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और सहज अनुभव प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि यह पहल जम्मू-कश्मीर में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के एयरटेल के लगातार प्रयासों का हिस्सा है। इस नेटवर्क विस्तार से तीर्थयात्रियों को न केवल बेहतर कॉल और इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी, बल्कि आपात स्थिति में त्वरित संपर्क स्थापित करना भी आसान होगा।

जम्मू-कश्मीर दौरे में पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष

6 जुलाई से जेएंडके में सक्रिय रहेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जुलाई को अपने पहले दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे के दौरान वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा भी इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बताया जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, नितिन नवीन 6 जुलाई को जम्मू-कश्मीर पहुंचेंगे और अपने दौरे की शुरुआत विभिन्न कार्यक्रमों के साथ करेंगे। इसी दिन वे भारतीय जनसंघ (बीजेएस) के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भागीदारी की संभावना है, जहां संगठन की विचारधारा और उसके विस्तार पर भी चर्चा होगी।

दौरे के दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी नेताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे। इन बैठकों में जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की वर्तमान स्थिति और आगामी रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक सही तरीके से पहुंच रहा है।

सूत्रों ने यह भी बताया कि अपने इस दौरे के दौरान नितिन नवीन उधमपुर का भी दौरा करेंगे, जहां वे स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। यह दौरा भाजपा के लिए जम्मू-कश्मीर में संगठनात्मक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे जमीनी स्तर पर पार्टी की स्थिति का आकलन करने और भविष्य की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।

न्यूज ब्रीफ

किश्तवाड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त; पिता-पुत्र की मौत

भारतेंदु संवाददाता,किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले के पाडर क्षेत्र में गुलाबगढ़-सोहल मार्ग पर शुक्रवार को एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पिता-पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटना गुलाबगढ़ के पास सोहल मार्ग पर हुई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से घायलों को तुरंत अथोली अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार जारी है। मृतकों की पहचान अनुरुद्ध सिंह (55) पुत्र नंद लाल निवासी तियारी और उनके बेटे दीपक कुमार (30) पुत्र अनुरुद्ध सिंह निवासी तियारी के रूप में हुई है।

अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रशासन सख्त पंजीकृत तिथि से पहले यात्रा पर रोक

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को कहा कि पंजीकृत तिथि से पहले किसी भी तीर्थयात्री को अमरनाथ गुफा की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और लोगों से अपील की कि वे अपनी बारी का इंतजार करें और केवल निर्धारित तिथि पर ही यात्रा करें। एक सलाह में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार तीर्थयात्रा मार्ग पर प्रतिदिन अधिकतम तीर्थयात्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और यात्रा के सुचारू संचालन के लिए इस दैनिक सीमा का पालन करना अनिवार्य है।

पंजाब से आया श्रद्धालु सोनमर्ग के एक होटल में मिला मृत अवस्था में

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा कल से शुरू हो चुकी है। इस दौरान कई श्रद्धालु देश-विदेश से बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंच रहे हैं। इसी बीच पंजाब से आया एक श्रद्धालु सोनमर्ग के एक होटल में मृत अवस्था में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार पंजाब के बरनाला निवासी 40 वर्षीय नरिंदर कुमार (40) पुत्र परमिंदर कुमार शुक्रवार को गांदरबल जिले के सोनमर्ग इलाके के एक होटल में मरा हुआ मिला।

अनंतनाग पुलिस की मानवता, बारिश में अमरनाथ यात्रियों की कर रही मदद

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के दौरान लगातार हो रही बारिश के बीच अनंतनाग पुलिस ने यात्रियों की मदद करके अपनी मानवीय कोशिशें जारी रखी हैं। खराब मौसम के बावजूद पुलिस ने बुजुर्ग श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों की सहायता की। पुलिसकर्मी यात्रियों का सामान उठाते, पीने का पानी देते और पवित्र गुफा मंदिर तक की यात्रा आसान बनाने के लिए बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सहारा देते हुए देखे गए। यह पहल जम्मू-कश्मीर पुलिस की उस प्रतिबद्धता को दिखाती है जिसके तहत वे सालाना यात्रा के दौरान न केवल मजबूत सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि लोगों की सेवा भी पूरी संवेदनशीलता के साथ करते हैं।

कठुआ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 गौवंशीय पशु तस्करों से मुक्त

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। कठुआ जिले में गौ तस्करी पर नकेल कसते हुए कठुआ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना नगरी के सैदपुर क्षेत्र में 17 गौवंशीय पशुओं को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एक ट्रक भी जब्त किया है। जानकारी के अनुसार एसएसपी कठुआ श्रीमती मोहिता शर्मा आईपीएस के निर्देशन में पुलिस टीम ने सैदपुर नगरी क्षेत्र में नाका और चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध ट्रक नंबर पीबी08बीटी-9117 को रोका। जांच के दौरान ट्रक में 17 पशुओं को बेरहमी से ठूंस-ठूंस कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर ही दोनों आरोपियों कलाश मसीह पुत्र कवाल मसीह निवासी मुकेरियां पंजाब तथा उसके सहयोगी रविंदर पुत्र लाल मसीह निवासी मुकेरियां पंजाब को गिरफ्तार कर लिया और ट्रक को जब्त कर लिया।

कठुआ में अमरनाथ यात्रा-2026 के तहत आज होगा लेजर एंड बीम शो

भारतेंदु संवाददाता, कठुआ। श्री अमरनाथ यात्रा-2026 के अवसर पर जिला प्रशासन कठुआ द्वारा आज लखनपुर यात्री सुविधा केंद्र में भव्य लेजर एंड बीम शो का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम शनिवार शाम 8 बजे से शुरू होगा। यह आकर्षक लाइट एवं लेजर शो श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। आयोजन का उद्देश्य यात्रा के आध्यात्मिक माहौल को और अधिक भव्य बनाना है। कार्यक्रम का संचालन डीआईपीआर कठुआ के सहयोग से किया जा रहा है।

जम्मू में नशे का खेल बेनकाब! रेलवे स्टेशन के पास बड़ी खेप के साथ 1 गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स) क्राइम ब्रांच जम्मू-कश्मीर ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक अंतरराज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से लगभग 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। यह कार्रवाई 2 जुलाई 2026 को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन के पास पार्क क्षेत्र में की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आशाराम बंजारे, निवासी राजीगढ़, छत्तीसगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया जब वह नशे के पदार्थ की तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। इस कार्रवाई का नेतृत्व इंस्पेक्टर नायत अली कर रहे थे। मामले में पुलिस स्टेशन ,क्राइम जम्मू में नंबर 05/2026, एक्ट की धारा 8/20 के तहत दर्ज की गई है। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और इसके पीछे जुड़े अन्य तस्करों की तलाश जारी है।

◆10 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार

अमरनाथ यात्रा: बालटाल रूट से 1,735 और पहलगाम से 2,130 श्रद्धालु रवाना

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। वार्षिक श्री अमरनाथ तीर्थयात्रा का शुक्रवार को विधिवत शुभारंभ हो गया, जिसके साथ ही हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी। यात्रा की शुरुआत दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित इस पवित्र गुफा की ओर जाने वाले दोनों प्रमुख मार्गों—बालटाल और नुनवान (पहलगाम)—से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे के रवाना होने के साथ हुई। इसके बाद 3,865 श्रद्धालुओं का दूसरा बड़ा जत्था जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ।

◆कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का आगाज

◆201 वाहनों का कड़ा सुरक्षा घेरा

अधिकारियों के अनुसार, रुक-रुक कर हो रही बारिश के बावजूद यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रारंभ हुई।

पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबे नुनवान-पहलगाम मार्ग और अपेक्षाकृत छोटे 14 किलोमीटर लंबे बालटाल मार्ग दोनों से श्रद्धालुओं ने तड़के ही यात्रा शुरू कर दी।

इस दौरान पुरुषों, महिलाओं, साधुओं और साध्वियों सहित श्रद्धालुओं ने संबंधित जिला प्रशासन और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद 'बम बम भोले' के जयकारों के साथ अपनी पवित्र यात्रा का आरंभ किया।

तवी रिवर फ्रंट पर शिकारा राइड शुरू

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। जम्मू नगर निगम के आयुक्त एवं जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. देवांश यादव ने शुक्रवार को तवी रिवर फ्रंट पर शिकारा राइड का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य तवी रिवर फ्रंट को पर्यटन और मनोरंजन का प्रमुख केंद्र बनाना तथा स्थानीय लोगों के साथ-साथ श्री अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को एक नया अनुभव प्रदान करना है।

इस अवसर पर डॉ. देवांश यादव ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित तवी रिवर फ्रंट अब जम्मू शहर की एक नई पहचान बनता जा रहा है और यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि शिकारा राइड के संचालन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं, जिनमें लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित नाविक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती शामिल है।

बहरीन नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों की ठगी, फर्जी दस्तावेजों का खुलासा

ईओडब्ल्यू कश्मीर ने फर्जी विदेश नौकरी रैकेट का किया पर्दाफाश

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू), कश्मीर ने शुक्रवार को श्रीनगर के एक व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उस पर बहरीन में नौकरी दिलाने का वादा करके और नकली वीजा, जॉब ऑफर लेटर और यात्रा से जुड़े अन्य फर्जी दस्तावेज देकर कई नौकरी चाहने वालों से लाखों रुपये ठगने का आरोप है।

ईओडब्ल्यू द्वारा जारी एक बयान में एक प्रवक्ता ने कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कश्मीर क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर ने प्राथमिकी नंबर 67/2021 के तहत धारा 420, 468 और 471 आरपीसी के तहत फयाज अहमद ज़रगर पिता मो. शफ़ी ज़रगर निवासी कुतुब दीन पोरा, आली कदल, जामिया मस्जिद, श्रीनगर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के अपराधों के लिए श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। उन्होंने कहा कि यह मामला एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने इसी तरह शिकायतकर्ता और कई अन्य लोगों को ठगा था उनसे लाखों रुपये लिए थे और उन्हें नकली जॉब ऑफर लेटर, वीजा, एयर टिकट और अन्य फर्जी दस्तावेज दिए थे। इस योजना को विश्वसनीय बनाने के लिए पीड़ितों के ऑनलाइन इंटरव्यू और मेडिकल जांच कराई गई और उनसे एग्रीमेंट भी करवाए गए। हालांकि कोई नौकरी नहीं दिलाई गई और न ही पैसे वापस किए गए। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान आरोप सही पाए गए और सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद न्यायिक फैसले के लिए सक्षम अदालत के समक्ष चार्जशीट पेश की गई।

कश्मीर मटन संकट टला, पंजाब सरकार के हस्तक्षेप के बाद हड़ताल वापस

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। कश्मीर मटन डीलर्स एसोसिएशन (केडीएमए) ने शुक्रवार को घोषणा की कि पशु व्यापारियों की चल रही हड़ताल को वापस ले लिया गया है। यह फैसला पंजाब सरकार के हस्तक्षेप के बाद लिया गया, जिसमें कथित तौर पर पुलिस को यह निर्देश दिए गए कि चेकपॉइंट पर पशुओं को ले जाने वाले वाहनों को अनावश्यक रूप से न रोका जाए। इस निर्णय के बाद जम्मू-कश्मीर में पशुओं की आपूर्ति फिर से सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे मटन की संभावित कमी को लेकर बनी चिंता भी काफी हद तक कम हो गई है।

केडीएमए के महासचिव मेराज-उद-दीन ने बताया कि एसोसिएशन को जानकारी मिली है कि पंजाब सरकार ने पुलिस प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पशु वाहनों की आवाजाही में किसी प्रकार की बाधा न डाली जाए। उन्होंने कहा कि इसी आश्वासन के आधार पर हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, उन्होंने

◆केडीएमए ने की हड़ताल वापसी की घोषणा, सप्लाई जल्द होगी सामान्य

यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल एसोसिएशन औपचारिक और लिखित आदेशों का इंतजार कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसके बाद ही जमीनी स्तर पर स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि यदि आदेशों का सही ढंग से पालन होता है, तो आने वाले दिनों में पशु व्यापार और आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी। इससे जम्मू-कश्मीर में मटन की उपलब्धता भी स्थिर होगी और उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से चल रही इस हड़ताल के कारण पंजाब से जम्मू-कश्मीर तक भेड़ों और अन्य पशुओं के परिवहन में गंभीर बाधा उत्पन्न हो गई थी, जिससे राज्य में मटन की आपूर्ति प्रभावित होने लगी थी।

बांदीपोरा में कांग्रेस विधायक निजाम-उद-दीन भट पर हमले का आरोप

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। बांदीपोरा से कांग्रेस विधायक निजाम-उद-दीन भट ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता जलाल अकबर लोन और उनके समर्थकों ने नायदखाई ब्लॉक ऑफिस में जन शिकायत बैठक के दौरान उन पर हमला किया। विधायक भट के मुताबिक, घटना उस वक्त हुई जब वे जिले के नायदखाई ब्लॉक ऑफिस में आयोजित जन दरबार में मौजूद थे। यहां लोग अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं और शिकायतें रखने के लिए आए हुए थे। भट का आरोप है कि सोनावारी के मौजूदा विधायक के भाई जलाल अकबर लोन ने अपने समर्थकों के साथ कार्यक्रम के दौरान उन पर हमला किया।

◆जलाल अकबर लोन और समर्थकों ने किया हमला

लद्दाख बना देश का प्रमुख हाई ऑल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

देश के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शामिल लद्दाख अब खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहचान बनाता जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना के वरिष्ठ कोचों ने लद्दाख को देश के सर्वश्रेष्ठ हाई-ऑल्टीट्यूड (उच्च ऊंचाई) खेल प्रशिक्षण स्थलों में से एक बताया है। कोचों के अनुसार, यहां का कम ऑक्सीजन वाला वातावरण खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, सहनशक्ति और फिटनेस को तेजी से बढ़ाने में मदद करता है, जिससे यह स्थान विशेष रूप से उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए बेहद उपयुक्त बन जाता है।

इस संदर्भ में लेह स्थित एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम में एक माह तक चले प्रशिक्षण शिविर के बाद आयोजित संवाद कार्यक्रम में नौसेना क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राजेश तिवारी, नौसेना बॉक्सिंग टीम के मुख्य कोच एएल

नौसेना कोच बोले—लद्दाख देश का बेहतरीन हाई-ऑल्टीट्यूड प्रशिक्षण स्थल

◆लेह बना फिटनेस ट्रेनिंग का हब

लाकरा और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, यूटी लद्दाख के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर शिवा नायक ने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में उपलब्ध खेल सुविधाओं, प्रशासनिक सहयोग और प्रशिक्षण वातावरण की खुले दिल से सराहना की।

नौसेना क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राजेश तिवारी ने बताया कि 17 सदस्यीय टीम को विशेष रूप से लेह लाया गया था ताकि खिलाड़ियों को कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में प्रशिक्षण देकर उनकी फिटनेस और स्टैमिना को बेहतर बनाया जा सके।

यात्रा महबूबा मुफ्ती ने खामेनेई को बताया शोषितों की आवाज उठाने वाला नेता

ईरान पहुंचकर महबूबा मुफ्ती ने अयातुल्ला खामेनेई को किया नमन

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती शुक्रवार को ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचीं, जहां उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक संदेश साझा करते हुए कहा कि तेहरान पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से शोक और एकजुटता प्रकट करना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने अपने संदेश में अयातुल्ला खामेनेई को ऐसा नेता बताया, जिन्होंने अन्याय और दमन के खिलाफ आवाज उठाई तथा शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसे समय में ईरान की जनता के साथ खड़ा होना और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना उनके लिए महत्वपूर्ण है।

महबूबा मुफ्ती ईरानी अधिकारियों के विशेष निमंत्रण पर तेहरान पहुंची हैं। उन्हें वहां आयोजित शोक समारोहों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया

महबूबा मुफ्ती बोलीं- यह मेरे लिए सम्मान का क्षण

था। जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर से चुनिंदा लोगों को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया था, जिनमें महबूबा मुफ्ती के अलावा कई प्रमुख शिया धर्मगुरु भी शामिल हैं। तेहरान में आयोजित इन कार्यक्रमों में विभिन्न देशों के राजनीतिक नेताओं, धार्मिक प्रतिनिधियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। बड़ी संख्या में लोग अयातुल्ला खामेनेई को श्रद्धांजलि देने और ईरान की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए इन समारोहों में शामिल हुए।

अपने संदेश में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अयातुल्ला खामेनेई ने अपने जीवन में वैश्विक स्तर पर अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। उन्होंने उन्हें ऐसा नेता बताया, जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर कायम रहे और वंचित तथा शोषित वर्गों के अधिकारों की बात करते रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करना उनके लिए सम्मान की बात है। महबूबा के इस बयान के बाद उनकी यात्रा और तेहरान में मौजूदगी को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।

ईरान में आयोजित शोक समारोहों में कई देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखने को मिली। क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम पर व्यापक नजर बनी हुई है। विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने ईरान के नेतृत्व और वहां की जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित इन कार्यक्रमों में धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों ने भी भाग लिया। ईरान की ओर से विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं, ताकि सभी प्रतिनिधि शोक समारोहों में शामिल होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।

गांदरबल में सीआरपीएफ की गाड़ी सड़क से फिसली, 6 जवान घायल

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। शुक्रवार को मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनगीर टनल के पास एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के छह जवान घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब सीआरपीएफ का एक वाहन क्षेत्र से गुजर रहा था और अचानक चालक का नियंत्रण वाहन पर से हट गया, जिसके कारण गाड़ी सड़क से फिसल गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

जानकारी के अनुसार, वाहन गगनगीर टनल के निकट सामान्य गश्त या आवाजाही के दौरान था, तभी सड़क पर संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हो गया। प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि सड़क की स्थिति, मोड़ और फिसलन जैसे कारणों के चलते वाहन चालक नियंत्रण नहीं रख सका और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर फिसल गया।

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग और सुरक्षा बलों के अन्य जवान मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायल जवानों को तत्काल प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया। इसके बाद उन्हें नजदीकी मेडिकल सेंटर में आगे के इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। अधिकारियों के अनुसार, सभी घायल जवानों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और किसी की हालत गंभीर नहीं है, हालांकि कुछ को चोटें आई हैं जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले का संज्ञान लिया। पुलिस ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दुर्घटना वास्तव में चालक की गलती से हुई या फिर सड़क की स्थिति, तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारण से वाहन असंतुलित हुआ। गगनगीर टनल क्षेत्र कश्मीर घाटी के संवेदनशील और महत्वपूर्ण मार्गों में से एक माना जाता है, जहां सुरक्षा बलों की आवाजाही अक्सर रहती है।

भारतेन्दु शिखर के जनरल मैनेजर विकास बालूनी ने भारतीय वन्यजीव संस्थान के निदेशक डॉ. गोबिंद सागर भारद्वाज से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें भारतेन्दु शिखर समाचार पत्र की प्रति भेंट की।

वन विकास निगम के कर्मचारियों को मिलेगा 3 फीसदी महंगाई भत्ता व बोनस

न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़कर 450 रुपए, मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में फैसले

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है।

निगम के कर्मचारियों को एक अप्रैल 2025 से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाएगा। इसके साथ ही 21 हजार रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की भी मंजूरी दी गई है। दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण तथा न्यूनतम दैनिक मजदूरी बढ़ाने के फैसले पर भी मुहर लगी है। ये फैसले शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में लिए गए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने की। बैठक में प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार पहली अप्रैल 2025 से निगम के कर्मचारियों को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दी गई। साथ ही 21 हजार रुपए तक मासिक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय भी लिया गया।

बैठक में प्रदेश सरकार की एक अप्रैल 2026 की अधिसूचना के अनुरूप उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को भी मंजूरी दी गई, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में हर साल 240 दिन का कार्य पूरा किया है। प्रदेश सरकार की नीति के अनुसार पात्र अनुबंध कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की भी स्वीकृति दी गई। निदेशक मंडल ने विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपए से बढ़ाकर 450 रुपए करने का फैसला भी मंजूर किया। यह संशोधित दरें एक अप्रैल 2026 से लागू होंगी।

निगम के कामकाज की भी समीक्षा की गई

बैठक में निगम के कामकाज की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टरपेंटाइन (आरएंडटी) फैक्टरी के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई उल्लेखनीय बढ़ोतरी पर संतोष जताया। निदेशक मंडल ने इसके बाद नाहन स्थित आरएंडटी फैक्टरी के आधुनिकीकरण का भी फैसला लिया, जिससे उत्पादन और राजस्व मेंज और बढ़ोतरी की जा सके। मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए प्रबंध निदेशक की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, कार्यकुशलता में सुधार लाने और निगम की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए नए उपाय जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में उपाध्यक्ष एचपीएसएफडीसीएल केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव के.के. पंत, वन बल प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक संजय सूद, निदेशक (पीएफएंडपीई) एवं विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन, निदेशक मंडल के गैर-सरकारी सदस्य और निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

भाजपा की विचारधारा व संगठनात्मक मजबूती पर जयराम ठाकुर ने दिया जोर

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का गौरवशाली इतिहास राष्ट्र प्रथम की भावना, अंत्योदय के संकल्प, सेवा, सुशासन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मूल्यों पर आधारित रहा है। वह बल्ह विधानसभा क्षेत्र के कोयला माता मंदिर, राजगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियान-2026 के अंतर्गत आयोजित मंडी अभ्यास वर्ग को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंघ से लेकर विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भाजपा की यात्रा लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और समर्पण का परिणाम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रवादी चिंतन ने संगठन को वैचारिक मजबूती प्रदान की है, जिसके बल पर भाजपा आज देश की सबसे विश्वसनीय राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है और भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय अभियान का सक्रिय भागीदार है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग केवल संगठनात्मक कार्यक्रम नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं को विचार, संस्कार और राष्ट्रसेवा के प्रति अधिक प्रतिबद्ध बनाने का माध्यम हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे पार्टी की विचारधारा, केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और संगठन के मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाएं। इस अवसर पर विधायक इंद्र सिंह गांधी, प्रकाश राणा, पूर्णचंद ठाकुर, त्रिलोक जम्वाल, भाजपा जिला अध्यक्ष निहालचंद शर्मा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा, बल्ह के ग्राम केंद्र कैहड़ के बूथ संख्या 89 में उन्होंने डिजिटल प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की।

न्यूज ब्रीफ

बस नध्यार में रोकने से ग्रामीणों की परेशानी बढ़ी

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर से 60 किलोमीटर दूर हमीरपुर डिपो की बस रूट में हाल ही में किए बदलाव के विरोध में ग्राम पंचायत नध्यार के रानी लक्ष्मीबाई महिला मंडल ने मोर्चा खोल दिया है। महिला मंडल का आरोप है कि पिछले करीब 20 वर्षों से मैहरे-शाहतलाई मार्ग पर संचालित बस को बीते सप्ताह से नध्यार तक सीमित कर दिया है। इससे सबसे अधिक परेशानी स्कूली विद्यार्थियों, ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है। महिला मंडल की प्रधान राजकुमारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 40 महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार और हिमाचल पथ परिवहन निगम के हमीरपुर डिपो को भेजा गया। महिलाओं ने मांग की कि मैहरे-नध्यार-शाहतलाई बस रूट को पहले की तरह नियमित रूप से बहाल किया जाए। साथ ही मैहरे से सुबह 11 बजे नध्यार पहुंचने वाली बस सेवा को दो किलोमीटर आगे बच्छरेटू स्थित शिव मंदिर तक बढ़ाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं और आसपास के गांवों के लोगों को भी सुविधा मिल सके। बस सेवा सीमित होने से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शाहतलाई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर लौटने में दिक्कत हो रही है। कई विद्यार्थियों को टैक्सी का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि कई को चार किलोमीटर पैदल जंगल के रास्ते से घर जाना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि बस सेवा बहाल नहीं की गई, तो गांव की महिलाएं शांतिपूर्ण प लोकतांत्रिक तरीके से बस का घेराव करेंगी।

आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने में समुदाय की भागीदारी पर जोर

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम के तहत शुक्रवार को बिलासपुर स्थित 5वीं बटालियन होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र में हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना के लिए स्थानीय समुदाय, पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों और अन्य हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना तथा सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं पर चर्चा करना था। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, महिला प्रतिनिधियों, स्थानीय समुदाय और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान परियोजना के संभावित सामाजिक प्रभाव, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, लैंगिक समानता, महिलाओं एवं कमजोर वर्गों की भागीदारी तथा सामुदायिक आवश्यकताओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। होमगार्ड कमांडेंट सुशील कुमार ने बताया कि प्राप्त सुझावों के आधार पर स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट प्लान और जेंडर एक्शन प्लान तैयार किए जाएंगे, जिससे परियोजना अधिक समावेशी, सुरक्षित और प्रभावी बन सकेगी।

स्कूटी से 1.09 किलो चरस बरामद, दो काबू

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नाकाबंदी के दौरान स्कूटी से 1.09 किलोग्राम चरस बरामद कर पंजाब के दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। स्पेशल डिटेक्शन टीम फोरलेन पर पडगल में नाकाबंदी पर तैनात थी। इसी दौरान मंडी भराड़ी की ओर से कीरतपुर की तरफ जा रही पंजाब नंबर की स्कूटी को जांच के लिए रोका गया। स्कूटी पर सवार दोनों युवकों से पूछताछ के बाद उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान स्कूटी की डिकी में रखे कैरी बैग से खाकी रंग की प्लास्टिक टेप में लिपटे दो पैकेट बरामद हुए। जांच करने पर दोनों पैकेटों में पारदर्शी पॉलिथीन में लिपटी चरस मिली। तौल करने पर एक पैकेट में 663.13 ग्राम और दूसरे में 427.55 ग्राम चरस पाई गई। बरामद चरस का वजन 1090.68 ग्राम रहा।

बलग का घाट स्कूल में शिक्षकों की कमी पर आक्रोश

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। शिक्षा सदर खंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक पाठशाला बलग का घाट में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के प्रधान मनसा राम, समाजसेवी सुभाष ठाकुर सहित अन्य प्रतिनिधियों ने प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अरुण गौतम से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और तत्काल अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। एसएमसी प्रधान मनसा राम ने बताया कि विद्यालय में लगभग 60 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए मात्र एक शिक्षक ही तैनात है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के लिए सभी कक्षाओं को संभालना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना संभव नहीं है। इस संबंध में पहले भी विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ऐसे में शिक्षक की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और सुरक्षा संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रामीणों ने विभाग से जल्द मुख्य शिक्षक सहित रिक्त पदों को भरने की मांग की। इस अवसर पर रीता देवी, निशा देवी, मोनिका देवी, चंचल देवी, अंकिता देवी, सुनील कुमार सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक अरुण गौतम ने प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र शिक्षकों की व्यवस्था का आश्वासन दिया।

7 जुलाई को नगरोटा में 150 पदों के लिए इंटरव्यू

भारतेन्दु संवाददाता, नगरोटा बगवां। जिला रोजगार अधिकारी अक्षय कुमार ने बताया कार्यालय सिस इंडिया लिमिटेड हमीरपुर द्वारा सिक्योरिटी गार्ड व सुपरवाइजर पुरुष उम्मीदवारों के 150 पद भरे जाने अधिसूचित किए गए हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं एवं इससे ऊपर रखी गई है। आयु 19 वर्ष से 40 वर्ष तक रखी गई है। आवेदक को कंपनी द्वारा रुपए 17500 से 23000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा। 7 जुलाई 2026 के दिन सुबह 11 बजे उप रोजगार कार्यालय नगरोटा में इच्छुक उम्मीदवार साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को अपने साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो, रिहायशी प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र व अपना बायोडाटा की कॉपी व अनुभव प्रमाण पत्र साथ लेकर पहुंचना होगा। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार मोबाइल नंबर 8558062252 पर संपर्क कर सकते हैं। विभागीय साइट पर साक्षात्कार का ब्यौरा अपलोड कर दिया गया है सभी इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि वह साक्षात्कार में भाग लेने से पहले https://eemis.hp.nic.in पर अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद अपने-बोर्ड पर दिख रही सर इंडिया लिमिटेड हमीरपुर की रिक्तियां के लिए आवेदन करना होगा। विभागीय साइट पर ऑनलाइन आवेदन के पश्चात ही साक्षात्कार में भाग लिया जा सकेगा।

यूआईडीएआई ने आधार ऐप से ईमेल आईडी अपडेट की सुविधा शुरू की

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। यूआईडीएआई ने नागरिकों की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए आधार ऐप के माध्यम से सीधे ईमेल आईडी जोड़ने या अपडेट करने की नई सुविधा शुरू की है। अब इसके लिए आधार केंद्र जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सेवा 1 जुलाई 2026 से प्रभावी हुई है और अगले छह महीनों तक उपलब्ध रहेगी। यह सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है और डिजिटल इंडिया एवं विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप है। शुरुआत के दो दिनों में ही 2.5 लाख से अधिक लोगों ने अपने आधार में ईमेल अपडेट कर लिया है। ईमेल लिंक होने पर आधार प्रमाणीकरण के दौरान रियल-टाइम नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे, जिससे सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। इसके अलावा, आधार ऐप से मोबाइल नंबर और पता अपडेट जैसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। अब तक 40 लाख से अधिक लोग मोबाइल नंबर और लगभग 10 लाख लोग पता अपडेट कर चुके हैं। यूआईडीएआई ने नागरिकों से इस डिजिटल सुविधा का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।

बिलासपुर में पंचायतीराज चुनावों में भाजपा का क्लीन स्वीप, कांग्रेस घुमारवीं बीडीसी अध्यक्ष पद तक सिमटी

नप से जिप तक भाजपा का एकतरफा कब्जा, शाहतलाई में भी लहराया भगवा

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला बिलासपुर में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। नगर परिषद, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अधिकांश पदों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने कब्जा जमाकर जिले की ग्रामीण राजनीति में अपना दबदबा साबित कर दिया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ घुमारवीं ब्लॉक समिति का अध्यक्ष पद ही बचा पाई।

जिले की चारों नगर परिषदों— बिलासपुर, घुमारवीं, नयनादेवी तथा शाहतलाई में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पदों पर भाजपा ने एकतरफा जीत हासिल की है। शाहतलाई जैसे क्षेत्र में भाजपा की जीत को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन चुनावों में कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हो गया। ब्लॉक समिति चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। बिलासपुर और झंडूता ब्लॉक समिति में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों पद भाजपा ने जीते। नयनादेवी ब्लॉक समिति में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा रहा। वहीं घुमारवीं ब्लॉक समिति में अध्यक्ष पद कांग्रेस के खाते में गया, जबकि उपाध्यक्ष पद भाजपा ने जीत लिया। जिले की सर्वोच्च पंचायती संस्था जिला परिषद के चुनाव में भाजपा ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद जीतकर अपना परचम लहराया। इस जीत को भाजपा के लिए विशेष उपलब्धि माना जा रहा है।

कांग्रेस की हार के मायने

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, पंचायत चुनाव समय पर न करवाने और लगभग 10 महीनों तक पंचायतों के विकास कार्य ठप रहने से ग्रामीण मतदाताओं में कांग्रेस सरकार के प्रति नाराजगी थी। सड़क, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाओं के कार्य रुकने का खामियाजा कांग्रेस को इन चुनावों में भुगतना पड़ा। इन चुनाव परिणामों से स्पष्ट है कि जिला बिलासपुर की ग्रामीण राजनीति में भाजपा की पकड़ बेहद मजबूत हो गई है। यह परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत दे रहे है।

लोगों ने भाजपा को दिया समर्थन

भाजपा की यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चल रही केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा पर भरोसा जताया है।

इंदौरा में 17.46 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवक गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त

भारतेन्दु संवाददाता, इंदौरा। नूरपुर पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए बाईं इंदोरियां के पास मोटरसाईकिल सवार 2 युवकों से 17.46 ग्राम (चिट्टा) हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

एसपी नूरपुर इल्मा अफरोज ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने काठगढ़ से इंदौरा रोड के पास नाकाबंदी की हुई थी। नाके के दौरान पुलिस ने एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल नंबर एचपी97ए 8273 को जांच के लिए रोका। इस दौरान तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल सवार दो युवकों के कब्जे से 17.46 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद हुई। पुलिस ने बरामद मादक पदार्थ और मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया है। आरोपियों की पहचान साहिल कुमार उर्फ लब्बी (उम्र 25 वर्ष), पुत्र अशोक कुमार, निवासी वार्ड नंबर 3, निवासी इंदौरा, पुलिस जिला नूरपुर तथा नितिन कुमार उर्फ नन्नू (उम्र 26 वर्ष), पुत्र बलविंदर, निवासी वार्ड नंबर 3, निवासी इंदौरा पुलिस जिला नूरपुर के रूप में हुई थी। मामले में आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना इंदौरा में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नूरपुर पुलिस द्वारा मामले की आगामी गहन जांच की जा रही है, ताकि इसके अन्य संपर्कों का पता लगाया जा सके।

कॉलेज की गतिविधियों से छात्रों को कराया परिचित

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। राजकीय महाविद्यालय घुमारवीं में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्राचार्य प्रो. प्रीतम लाल ने की। प्राचार्य ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य नए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों से परिचित कराना है। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों, समय-सारिणी, महाविद्यालय की गतिविधियों, कॅरिअर एवं काउंसिलिंग, छात्रवृत्ति योजनाओं, महाविद्यालय की वेबसाइट, छात्रावास, नशा उन्मूलन, एंटी-रैगिंग नियमों, शालीन वेशभूषा, पुस्तकालय एवं ई-संसाधनों, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, एनसीसी, एनएसएस, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, रेड रिबन क्लब तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में मोबाइल फोन के उपयोग संबंधी नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. अमित कुमार, डॉ. बासु देव, डॉ. पुष्पेंद्र, डॉ. जीवेश, डॉ. बलबीर, प्रो. रमेश, प्रो. कविता और प्रो. पूनमा ने भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

कूह मझवाड़ में 500 लोगों का जांचा स्वास्थ्य

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपमंडल घुमारवीं के गांव कूह मझवाड़ में शुक्रवार को डेयरी विकास जागरूकता कार्यक्रम व निशुल्क विशाल चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हिमकोफेड के निदेशक आशीष ठाकुर ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और डेयरी व्यवसाय किसानों व पशुपालकों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर पशुपालकों को बेहतर लाभ दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार सहकारी समितियों को सशक्त बनाने, आधुनिक डेयरी ढांचा विकसित करने, सब्सिडी, आसान ऋण, पशु बीमा और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन, संतुलित पशु आहार, नस्ल सुधार, टीकाकरण, पशु बीमा और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं, निशुल्क चिकित्सा शिविर में मोहाली ट्राइसिटी से आए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने करीब 500 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श और निशुल्क दवाइयां वितरित कीं।

धर्मशाला, मंडी व सोलन में भाजपा के मेयर बनने से कांग्रेस के दावों की पोल खुली: बिंदल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि धर्मशाला, मंडी व सोलन नगर निगमों में भाजपा के मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाने के बाद कांग्रेस के उन दावों की सच्चाई सामने आ गई है, जिनमें नगर निकाय और पंचायतीराज चुनावों में जनता का समर्थन मिलने की बात कही जा रही थी।

उन्होंने कहा कि इन नतीजों से साफ है कि प्रदेश की जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया है और कांग्रेस सरकार को जवाब दिया है। राजीव बिंदल ने शुक्रवार को कहा कि 17 मई को नगर निकाय और नगर निगम चुनाव हुए थे, जबकि 26, 28 व 30 मई को जिला परिषद, बीडीसी और पंचायत चुनाव कराए गए। उनका दावा है कि इन चुनावों में भाजपा को दो-तिहाई बहुमत के साथ जीत मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार शुरू से इन चुनावों के पक्ष में नहीं थी और मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचने के बाद चुनाव कराने पड़े। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के बाद करीब डेढ़ महीने तक मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के चुनाव जानबूझकर टाले गए और उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की गई। राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन नगर निगम पर राजनीतिक नियंत्रण हासिल करने के लिए लगातार अलग-अलग तरीके अपनाए, लेकिन जनता ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूरे चुनावी दौर में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, नियमों में मनमाने बदलाव करने और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि धर्मशाला, मंडी और सोलन के नतीजे यह संदेश देते हैं कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार के कामकाज से निराश है और भाजपा की नीतियों तथा नेतृत्व पर भरोसा जता रही है।

विशेष शिक्षा केंद्र विजयपुर में अभिभावक परामर्श बैठक का आयोजन

विशेष बच्चों के शैक्षणिक व सामाजिक विकास पर चर्चा

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित विशेष शिक्षा केंद्र, विजयपुर में विशेष बच्चों के समग्र विकास एवं अभिभावकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभिभावक परामर्श बैठक का सफल आयोजन किया गया।

बैठक की अध्यक्षता श्री अरुण कुमार गौतम, निदेशक, चेतना संस्था ने की। इस अवसर पर विशेष शिक्षण केंद्र, विजयपुर की प्रधानाचार्य श्रीमती पूजा कुमारी सहित संस्थान के समस्त शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शैक्षणिक, विकासात्मक, व्यवहारिक, सामाजिक व अवधारणात्मक विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट शिक्षण पद्धतियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दैनिक जीवन कौशल, संचार कौशल, व्यवहार प्रबंधन, समावेशी शिक्षा, खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। निदेशक अरुण कुमार गौतम ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष बच्चों के सर्वांगीण विकास में विद्यालय और परिवार की साझेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभिभावकों से बच्चों की नियमित उपस्थिति, घर पर सतत अभ्यास, सकारात्मक वातावरण एवं विद्यालय द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करने का आग्रह किया, जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता और आत्मनिर्भरता में निरंतर वृद्धि हो सके। बैठक में आगामी शैक्षणिक व प्रशिक्षण गतिविधियों, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जीवन कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अभिभावक सहभागिता तथा भविष्य की कार्ययोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही अभिभावकों द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और उनके समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में अधिकांश अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपने विचार एवं सुझाव साझा किए। सभी ने संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में भी पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। बैठक का समापन विशेष बच्चों के उज्ज्वल भविष्य, आत्मनिर्भरता एवं समग्र विकास के सामूहिक संकल्प के साथ किया गया। अंत में संस्थान की ओर से सभी अभिभावकों का सहभागिता एवं सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया।

चर्चा श्री नयना देवी श्रावण अष्टमी मेले की तैयारियों को लेकर डीसी की अध्यक्षता में बैठक

एलईडी स्क्रीन से होगा माता जी की पिंडी का लाइव प्रसारण

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। श्री नयना देवी जी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में आगामी 13 से 22 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावण अष्टमी मेले की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मातृ आंचल भवन, श्री नयना देवी जी में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मेले के सफल, सुरक्षित व सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रबंधों पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान भी उपस्थित रहे। उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त को मेला अधिकारी तथा एसडीएम श्री नयना देवी जी को सहायक मेला अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को पुलिस मेला अधिकारी और डीएसपी श्री नयना देवी जी को सहायक पुलिस मेला अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेला क्षेत्र को नौ सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा तथा प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस अधिकारी की तैनाती होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 400 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाएगा।

◆ मेला क्षेत्र को 9 सेक्टरों में बांटा जाएगा, 400 से अधिक सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात

श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बस अड्डे से मुख्य मंदिर तक छह बैरिकेड लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर को मेला चिकित्सा अधिकारी तथा बीएमओ श्री नयना देवी जी को सहायक मेला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया है। विभिन्न स्थानों पर छह स्थायी एवं अस्थायी चिकित्सा सहायता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए टोबा, घवांडल और रोपवे सहित तीन प्रमुख स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे तथा विशेष बस सेवाएं भी संचालित की जाएंगी।

उपायुक्त ने कहा कि मेले के दौरान लंगर लगाने के लिए ऑनलाइन अनुमति एसडीएम कार्यालय से प्रदान की जाएगी तथा लंगर संचालकों को साफ-सफाई और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने 'ग्रीन मेला' की अवधारणा पर जोर देते हुए प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने और स्वच्छता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। पंजाब से आने वाले लगभग 300 स्वयंसेवकों की भी तैनाती की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यू) भी सक्रिय रहेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित सैंपलिंग करने के निर्देश दिए।

जल शक्ति विभाग को निर्बाध पेयजल आपूर्ति तथा विद्युत विभाग को निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए माता जी की पिंडी का लाइव प्रसारण तीन स्थानों पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से किया जाएगा। मेला क्षेत्र में एक जर्मन हैंगर भी स्थापित किया जाएगा जिसमें लगभग एक हजार श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था होगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं नगर परिषद श्री नयना देवी जी के सदस्य उपस्थित रहे।

सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर प्रतीक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय को अधिक सुलभ, त्वरित एवं जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से 'समाधान समारोह-2026' प्रारंभ किया गया है।

इस विशेष पहल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यह अभियान उन पक्षकारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिनके मामले सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं और जो आपसी सहमति, सुलह एवं मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों का समाधान करना चाहते हैं। मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा कम समय, कम व्यय तथा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संभव हो पाता है, जिससे दोनों पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय से राहत मिलती है। प्रतीक गुप्ता ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 अप्रैल 2026 से इस विशेष अभियान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उपयुक्त मामलों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाकर न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करना और पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है।

उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए एक सरल ऑनलाइन गूगल फॉर्म तैयार किया गया है, जो सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इच्छुक पक्षकार निर्धारित लिंक के माध्यम से आवेदन कर अपने मामलों को इस अभियान में शामिल कर सकते हैं। उन्होंने जिला बिलासपुर के सभी अधिवक्ताओं, वादकारियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करें। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के दूरभाष नंबर 01978-221452 पर संपर्क किया जा सकता है या अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

स्टेफनी मैकमैहन का बिदांस अंदाज

स्टेफनी मैकमैहन डब्ल्यूडब्ल्यूई की एक प्रमुख पूर्व महिला पहलवान और व्यवसायिक अधिकारी हैं। वे विन्स मैकमैहन की बेटी और ट्रिपल एच की पत्नी हैं। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुश्ती रिंग के अंदर और कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

महिला टी20 विश्व कप इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराया

फाइनल में इंग्लैंड, अब ऑस्ट्रेलिया से टक्कर

एजेंसी, लंदन

कप्तान नैट साइवर-ब्रंट और पूर्व कप्तान हीदर नाइट की शानदार अर्धशतकीय पारियों के दम पर मेजबान इंग्लैंड ने महिला टी20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब खिताबी मुकाबले में इंग्लैंड की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से 6 जुलाई को लॉर्ड्स में होगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम महज 23 रन पर तीन विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद चोट से वापसी कर रही नैट साइवर-ब्रंट और हीदर नाइट ने चौथे विकेट के लिए 133 रन की रिकॉर्ड साझेदारी कर टीम को संकट से बाहर निकाला।

साइवर-ब्रंट ने केवल 47 गेंदों में 75 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल रहा। वहीं हीदर नाइट ने 47 गेंदों में 58 रन बनाकर उनका शानदार साथ निभाया। दोनों की बदौलत इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से शुरुआत में शबनिम इस्माइल और मारिजाने कैप ने बेहतरीन गेंदबाजी की। इस्माइल ने 2 विकेट, जबकि कैप ने अपने चार ओवर में केवल 16 रन देकर एक विकेट हासिल किया। 170 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम नियमित अंतराल पर विकेट गंवाती रही। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गईं। सलामी बल्लेबाज ताज़मिन ब्रिट्स ने संघर्ष करते हुए 51 रन बनाए, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से पर्याप्त सहयोग नहीं मिला।

इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। लॉरेन बेल और चार्ली डीन ने दो-दो विकेट झटके, जबकि बाकी गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 8 विकेट पर 129 रन तक ही सीमित रखा। मैच के दौरान इंग्लैंड की फील्डिंग भी शानदार रही। सोफी एक्लेस्टोन ने कठिन कैच लपककर दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदों को झटका दिया, जबकि डैनी वायट-हॉज की सटीक थ्रो से सिनालो जाफ्टा रन आउट हुईं। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पिछले कुछ वर्षों में आईसीसी नॉकआउट मुकाबलों में मिली निराशाओं का बदला भी चुकता किया। 2023 महिला टी20 विश्व कप और 2024 महिला वनडे विश्व कप के सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मिली हार का हिसाब बराबर करते हुए इंग्लैंड अब घरेलू सरजमीं पर विश्व चैंपियन बनने से सिर्फ एक जीत दूर है।

दूसरा टी20 : भारत-इंग्लैंड के बीच कांटे की टक्कर आज

सैमसन की परीक्षा, सूर्यवंशी के डेब्यू पर टिकी निगाहें

एजेंसी, मैनचेस्टर

इंग्लैंड के खिलाफ शनिवार को होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को पदार्पण का मौका देने की बढ़ती मांग के बीच सैमसन की हर पारी पर नजर रहेगी।

पहला टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया था। उससे पहले भारत ने अभिषेक शर्मा (59) और कप्तान श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की बदौलत सात विकेट पर 189 रन बनाए थे। हालांकि सैमसन सात गेंद में सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए और उनकी धीमी बल्लेबाजी चर्चा का विषय रही।

अभिषेक शर्मा ने पिछले तीन टी20 में दो अर्धशतक जड़कर अपनी जगह मजबूत की है, जबकि सैमसन लगातार प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे हैं। ऐसे में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मौका देने की मांग तेज हो गई है। हालांकि टीम प्रबंधन युवा खिलाड़ी को लेकर जल्दबाजी के पक्ष में नहीं दिख रहा। मध्यक्रम में तिलक वर्मा से भी तेज बल्लेबाजी की उम्मीद होगी। स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट चिंता का विषय रहा है। दूसरी ओर, स्पिनरों की मददगार ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर भारतीय गेंदबाजी में बदलाव की संभावना कम है।

इंग्लैंड के पास कप्तान हैरी ब्रूक, फिल साल्ट और टॉम बैंटन जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं। ऐसे में मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दूसरे टी20 में वैभव सूर्यवंशी को भारत की ओर से पदार्पण का मौका मिलेगा।

स्पोर्ट्स विंडो

मेसी के बचे हुए मैच मत गिनिए, हर पल का आनंद लीजिए : रोड्रिगो डी पॉल

एजेंसी, मियामी। अर्जेंटीना के मिडफील्डर रोड्रिगो डी पॉल ने फुटबॉल प्रशंसकों से अपील की है कि वे लियोनेल मेसी के संन्यास या विदाई की चर्चा करने के बजाय उनके हर मैच और हर पल का आनंद लें। केप वर्डे के खिलाफ राउंड ऑफ 32 मुकाबले से पहले डी पॉल ने कहा कि मेसी जैसे खिलाड़ी बार-बार नहीं मिलते। 39 वर्षीय मेसी अपना छठा विश्व कप खेल रहे हैं और इसे अर्जेंटीना की जर्सी में उनका आखिरी विश्व कप माना जा रहा है। हालांकि डी पॉल ने कहा कि टीम अभी से मेसी के बाद के दौर के बारे में नहीं सोच रही। डी पॉल ने कहा, 'अभी हमारे पास मेसी हैं, इसलिए उनके हर पल का आनंद लेना चाहिए। अक्सर किसी शख्स की अहमियत उसके जाने के बाद समझ आती है, लेकिन हमें वर्तमान को जीना चाहिए।' इस विश्व कप में मेसी तीन मैचों में छह गोल कर चुके हैं और गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे हैं। डी पॉल ने मेसी के साथ अपनी दोस्ती को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक बताते हुए कहा कि मैदान के अंदर और बाहर उनके साथ समय बिताना उनके लिए गर्व की बात है। डी पॉल ने केप वर्डे को हल्के में लेने से भी इनकार किया। उन्होंने कहा कि ग्रुप चरण में शानदार प्रदर्शन करने वाली इस टीम के खिलाफ अर्जेंटीना पूरी गंभीरता के साथ उतरेगा। विश्व चैंपियन अर्जेंटीना शुक्रवार को जीत दर्ज कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा।

सारांश जैन और गुरनूर बराड़ ने श्रीलंका-ए को 366 रन पर समेटा

एजेंसी, गाले, (श्रीलंका)। सारांश जैन और गुरनूर बराड़ (चार-चार विकेट) की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर भारत ए दूसरे अनौपचारिक टेस्ट मैच के दूसरे दिन श्रीलंका ए को पहली पारी में 366 रन के स्कोर पर समेट दिया। श्रीलंका-ए ने कल के पांच विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू किया। शुक्रवार सुबह के सत्र में गुरनूर बराड़ ने चमीका गुणाशेखरा (13) रन को आउटकर भारत ए को छठी सफलता दिलाई। इसके बाद सारांश जैन ने केशरा नुवंता (एक) का शिकार कर लिया। 109वें ओवर में सारांश जैन ने दिलम सुदीरा (20) को पगबाधा आउट कर श्रीलंका को आठवां झटका दिया। इस दौरान सहान अराछिगे ने अपना शतक पूरा किया। अगले ही ओवर में बराड़ ने कप्तान सहान अराछिगे (127) रन को आउट कर पवेलियन भेज दिया। सहान अराछिगे ने अपनी पारी में 207 गेंदों का सामना किया और 13 चौके और दो छक्के लगाए। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बराड़ ने असंका मनोज (चार) को बोल्ड कर श्रीलंका-ए की पारी को 366 रन के स्कोर पर अंत कर दिया।

जाग्रेब ग्रैंड शतरंज टूर: अनीश को हराकर डी गुकेश संयुक्त दूसरे स्थान पर पहुंचे

एजेंसी, जाग्रेब। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने जाग्रेब ग्रैंड शतरंज टूर के दूसरे दिन शानदार वापसी करते हुए नीदरलैंड के ग्रैंडमास्टर अनीश गिरी को हराया और संयुक्त दूसरे स्थान पर पहुंच गए। फ्रांस के अलीरेजा फिरोजजा 12 में 10 अंकों के साथ शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि गुकेश, विन्सेंट कीमर, मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव और बोगदान-डेनियल डियाक सात-सात अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। सफेद मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने रुई लोपेज़ एक्सचेंज वैरिएशन में गिरी पर शुरू से दबाव बनाए रखा। गिरी जल्द ही अपनी तैयारी से बाहर हो गए और गुकेश ने एक्सचेंज जीतने के बाद कोई मौका नहीं गंवाया। इससे पहले दिन के पहले मुकाबले में डियाक से हारने के बाद उन्होंने जॉर्डन वान फोरेस्ट और गिरी को हराकर शानदार वापसी की। दूसरे भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानानंद ने जॉर्डन वान फोरेस्ट को हराया, लेकिन नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव और फिरोज़जा से हार गए। फिरोजजा के खिलाफ वह ड्रॉ की स्थिति तक पहुंचे थे, लेकिन एंडगेम की एक गलती उन्हें भारी पड़ गई। रैपिड वर्ग के तीन दौर बाकी हैं। इसके बाद खेले जाने वाले 18 ब्लिट्ज मुकाबले टूर्नामेंट के अंतिम विजेता का फैसला करेंगे।

क्रोएशिया को हराकर पुर्तगाल प्री-क्वार्टर फाइनल में

एजेंसी, टोरंटो

फीफा विश्व कप

क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऐतिहासिक गोल और अतिरिक्त समय में गोंकालो रामोस के विजयी हेडर की बदौलत पुर्तगाल ने शुक्रवार को फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली। मुकाबले के आखिरी क्षणों में क्रोएशिया ने बराबरी का गोल किया, लेकिन वीएआर जांच के बाद उसे ऑफसाइड करार देते हुए रद्द कर दिया गया। मैच का पहला गोल क्रोएशिया ने 53वें मिनट में किया। अनुभवी विंगर इवान पेरिसिच ने पुर्तगाल के गोलकीपर डियोगो कोस्टा को छकाते हुए शानदार फिनिश कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके कुछ ही मिनट बाद रोनाल्डो ने गेंद को जाल में पहुंचाया, लेकिन ऑफसाइड के कारण गोल मान्य नहीं हुआ।

पुर्तगाल को 69वें मिनट में पेनाल्टी मिली, जब रेनाटो वेइगा को निकोला व्लासिच ने बॉक्स के अंदर गिरा दिया। वीएआर समीक्षा के बाद रेफरी ने पेनाल्टी का फैसला दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बिना किसी गलती के स्पॉट किक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। यह विश्व कप नॉकआउट चरण में रोनाल्डो का पहला गोल भी रहा। इसके बाद दोनों टीमों ने लगातार आक्रमण किए। क्रोएशिया के मातेओ कोवाचिच का शानदार शॉट गोलकीपर डियोगो कोस्टा ने पोस्ट की ओर धकेल दिया, जबकि मारियो पासालिच का हेडर मामूली अंतर से बाहर चला गया। निर्धारित समय समाप्त होने के बाद जब मुकाबला अतिरिक्त समय की ओर बढ़ रहा था, तभी चौथे मिनट में राफेल लियाओ के बेहतरीन पास पर गोंकालो रामोस ने हेडर लगाकर पुर्तगाल को 2-1 की बढ़त दिला दी। ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। मैच के अंतिम क्षणों में योश्को ग्वार्डियोल ने क्रोएशिया के लिए बराबरी का गोल कर दिया, लेकिन वीएआर जांच में उन्हें ऑफसाइड पाया गया और गोल रद्द कर दिया गया। इस फैसले से क्रोएशियाई खिलाड़ी और समर्थक निराश हो गए, जबकि पुर्तगाल ने जीत का जश्न मनाया। इस जीत के साथ पुर्तगाल ने प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना स्पेन से 7 जुलाई को डलास में होगा।

स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराया

एजेंसी, वैंकूवर

ब्रील एम्बोलो और डैन न्डोये के गोलों की बदौलत स्विट्जरलैंड ने फीफा विश्व कप-2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली। अब स्विट्जरलैंड का सामना मंगलवार को इसी मैदान पर कोलंबिया और घाना के बीच होने वाले मुकाबले की विजेता टीम से होगा।

स्विट्जरलैंड ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और 10वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली। 20 वर्षीय युवा खिलाड़ी जोहान मंजांबी ने बाएं फ्लैंक से शानदार दौड़ लगाते हुए लो क्रॉस दिया, जिस पर ब्रील एम्बोलो ने आसान फिनिश कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।

मंजांबी का यह टूर्नामेंट में दूसरा असिस्ट रहा। युवा खिलाड़ी अब तक चार विश्व कप मैचों में तीन गोल और दो असिस्ट दर्ज कर चुके हैं। दूसरे हाफ की शुरुआत होते ही स्विट्जरलैंड ने अपनी बढ़त दोगुनी कर दी। 46वें मिनट में बॉक्स के बाहर मिली गेंद पर डैन न्डोये ने शानदार नियंत्रण दिखाते हुए अल्जीरिया के गोलकीपर लुका जिदान को छकाकर गेंद जाल में पहुंचा दी।

इसके बाद स्विस टीम ने मजबूत रक्षात्मक प्रदर्शन करते हुए अल्जीरिया को वापसी का कोई मौका नहीं दिया और 2-0 की आसान जीत दर्ज की। ग्रुप चरण में दो जीत और एक ड्रॉ के साथ ग्रुप-बी में शीर्ष पर रहने वाली स्विट्जरलैंड की टीम पूरे टूर्नामेंट में अब तक अजेय बनी हुई है। हालांकि, स्विट्जरलैंड 2006, 2014, 2018 और 2022 विश्व कप में अंतिम-16 से आगे नहीं बढ़ सका था। तीन बार विश्व कप क्वार्टर फाइनल खेलने वाली स्विस टीम अब 1954 के बाद पहली बार अंतिम आठ में जगह बनाने की कोशिश करेगी।

सोना 3104 रुपए हुआ महंगा चांदी 2 .33 लाख रुपए पहुंची

एजेंसी, नई दिल्ली

सोना-चांदी के दाम में आज 3 जुलाई को लगातार चौथे दिन तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,104 रुपए बढ़कर 1,46,107 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले गुरुवार को इसकी कीमत 1,43,003 रुपए प्रति 10 ग्राम थी।

वहीं, एक किलो चांदी 4,504 रुपए बढ़कर 2,33,354 रुपए पर पहुंच गई। इससे पहले 2 जुलाई को इसकी कीमत 2,28,850 रुपए प्रति किलो थी। सोना पिछले चार दिन में 4,686 रुपए और चांदी 13,374 रुपए महंगी हुई है। इससे पहले सोमवार को सोना 1.41 लाख रुपए और चांदी 2.2 लाख रुपए पर थी। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 12,908 रुपए और चांदी 2,934 रुपए महंगी हुई है। 31 दिसंबर 2025 को 10ग्र सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.46 लाख रुपए पर पहुंच गया है। वहीं, चांदी 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.33 लाख रुपए पर पहुंच गई है। इस दौरान 29 जनवरी को सोने ने 1.76 लाख रुपए और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का ऑलटाइम हाई भी बनाया था।

सेंसेक्स 261 अंक और निफ्टी 95 अंक हुआ तेज

एजेंसी, मुंबई। शेयर बाजार में आज यानी 3 जुलाई को तेजी रही। सेंसेक्स 261 अंक की तेजी के साथ 77,764 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 95 अंक की बढ़त रही, ये 24,270 के स्तर पर बंद हुआ। रियल्टी, ढ्रुझ और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। शेयर बाजार में 2 जुलाई को बढ़त रही। सेंसेक्स 579 अंक की तेजी के साथ 77,502 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 170 अंक की बढ़त रही। ये 24,176 पर बंद हुआ था।

पीएम मोदी का राजस्थान-गुजरात आज 1.06 लाख करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार, 4 जुलाई को राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे, जहां वे कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री जोधपुर और बालोतरा में लगभग 1.06 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें नए हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन, उड़ान योजना का विस्तार, देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल परियोजना और कई ऊर्जा व रेल परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण, सौर ऊर्जा परियोजनाओं और रेलवे दोहरीकरण जैसी योजनाओं की भी नींव रखी जाएगी। इस दौरान हजारों युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे जाएंगे।

गुजरात के साणंद में प्रधानमंत्री देश की सेमीकंडक्टर क्षमता को बढ़ावा देने वाली सीजी सेमी की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट इकाई का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना सेमीकंडक्टर मिशन के तहत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इससे ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम व इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पाकिस्तान में बस खाई में गिरी कम से कम 40 यात्रियों की मौत

एजेंसी, इस्लामाबाद

पाकिस्तान के बलोचिस्तान प्रांत में आज क्वेटा से पेशावर जा रही बस झोब और डेरा इस्माइल खान के बीच डाना सर इलाके में गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार यह हाल के वर्षों में इस इलाके की सबसे घातक सड़क दुर्घटना है। बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने हादसे की पुष्टि की है।

जियो न्यूज और दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बलोचिस्तान के मुख्यमंत्री के प्रवक्ता रिंद ने कहा कि जिला अधिकारी, बचाव एजेंसियां और अन्य संबंधित विभाग राहत कार्य में जुटे हैं। जिला उपायुक्त शेरानी वली काकर ने कहा कि ऊबड़-खाबड़ इलाका होने के कारण बचाव दलों को दुर्घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि बलोचिस्तान के नजदीकी अस्पतालों में आपातकाल घोषित किया है।

अधिकारियों ने बताया कि बस के ब्रेक फेल होने की आशंका है। मृतकों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल भेजा जा रहा है।

रिपोर्ट: अमेरिका ने ईरान को दी इसराइली साजिश की चेतावनी

एजेंसी, वॉशिंगटन

अमेरिका-ईरान के बीच अप्रैल में शुरू हुई बातचीत के दौरान अमेरिका को डर था कि इजराइल, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ को निशाना बना सकता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल-ईस्ट के कुछ सहयोगी देशों के जरिए तेहरान को सतर्क रहने का संदेश भिजवाया।

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका को डर था कि अगर दोनों वार्ताकारों की हत्या हुई तो युद्धविराम और शांति प्रक्रिया टूट जाएगी। उस समय ट्रम्प प्रशासन होर्मुज स्ट्रेट खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की कोशिश कर रहा था।

◆ कहा-अराघची और गालिबाफ की हत्या कर सकता था इसराइल

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में होने वाली एक बैठक से पहले भी ईरान को हमले का खतरा था। इसी कारण पाकिस्तान ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल के विमान को फाइटर जेट की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक पहुंचाया। लौटते समय भी सुरक्षा अलर्ट मिलने पर विमान की मशहद में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और डेलिगेशन सड़क के जरिए तेहरान पहुंचा।

भारत-बांग्लादेश के बीच रेल सेवा दोबारा शुरू होने की उम्मीद

एजेंसी, सिलीगुड़ी

भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री रेल सेवाएं मिताली, बंधन और मैत्री एक्सप्रेस के दोबारा शुरू होने की संभावना तेज हो गई है। सिलीगुड़ी में रेलवे और कूटनीतिक स्तर पर चल रही चर्चाओं के बाद संकेत मिले हैं कि दोनों देशों के बीच संपर्क ट्रेन सेवाएं जल्द बहाल हो सकती हैं।

सूत्रों के अनुसार, रेल अधिकारियों की बैठकों में ट्रैक, रूट और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जा रही है। यदि तैयारियां समय पर पूरी हुईं तो इसी महीने सेवाएं बहाल हो सकती हैं, हालांकि अभी कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं की गई है। इन ट्रेनों का संचालन 2024 में सुरक्षा कारणों से अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। सेवाओं में 'मैत्री एक्सप्रेस', 'बंधन एक्सप्रेस' और 'मिताली एक्सप्रेस' शामिल हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच प्रमुख यात्री संपर्क का माध्यम रही हैं। हाल ही में बांग्लादेश में वीजा सेवाओं के फिर से शुरू होने और राजनीतिक हालात में सुधार के बाद दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ने के संकेत मिले हैं। रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलते ही संचालन की आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना है।

यूनिसेफ की चेतावनी लेबनान में 1 लाख बच्चों की पढ़ाई खतरे में

एजेंसी, बेरुत। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) ने एक बयान में कहा है कि यदि युद्ध में क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सितंबर तक मरम्मत नहीं की गयी तो लेबनान के लगभग एक लाख बच्चों के नये शैक्षणिक सत्र से वंचित होने का खतरा है। यह चेतावनी यूनिसेफ और लेबनान के शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्रालय के देशव्यापी सर्वेक्षण के बाद आयी है, जिसमें पश्चिम एशिया के हालिया संघर्ष के कारण देश के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक नुकसान की बात सामने आयी है। इस मूल्यांकन में विद्यालयों और व्यावसायिक केंद्रों सहित 340 प्रभावित शैक्षणिक संस्थानों की पहचान की गयी है।

इनमें से 17 पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं और कई अन्य को सुरक्षित रूप से दोबारा खोलने से पहले बड़े पैमाने पर मरम्मत की आवश्यकता है। यूनिसेफ ने आगाह किया कि लंबे समय तक विद्यालय से दूर रहने के कारण बाल श्रम और कम उम्र में शादी जैसे जोखिम बढ़ सकते हैं।